www.indiatodayhindi.in

गरीबों की थाली क्यों है अब भी खाली?

उत्तर प्रदेशः चेहरा बदलती मुस्लिम सियासत

झारखंडः जबान पर छिड़ गई नई जंग

16 फरवरी, 2022 50 रुपए

इंडिया टुडे

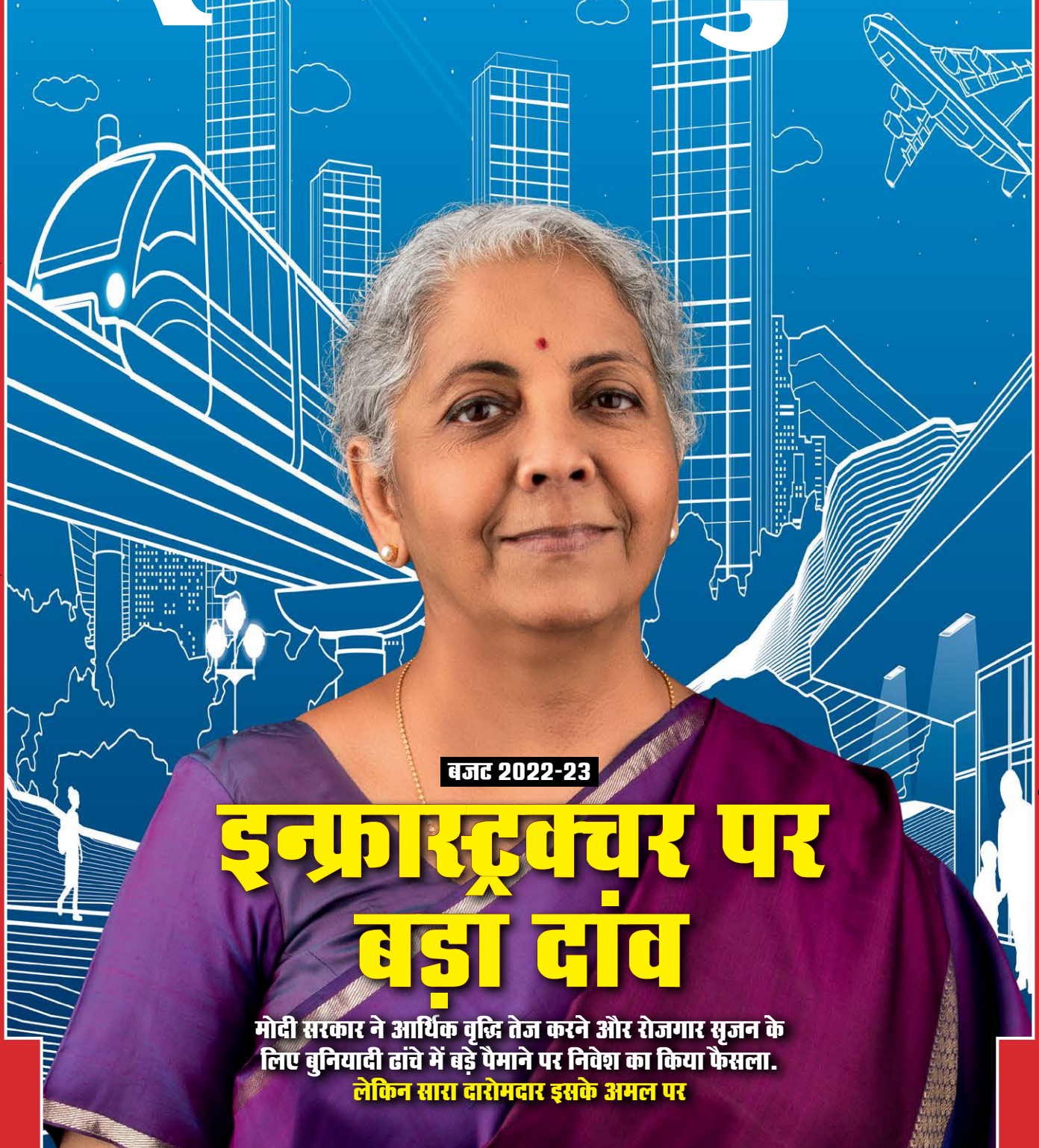

बजट 2022-23

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव

मोदी सरकार ने आर्थिक वृद्धि तेज करने और रोजगार सृजन के लिए बुनियादी ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश का किया फैसला.
लेकिन सारा दारोमदार इसके अमल पर

RNI NO 45823/86 REGISTERED NO. DL(ND)-11/6042/2021-22-2023; LICENSED TO POST WPP NO U(C)-31/2021-23; FARIDABAD/46/2020-22

अग्रिम सप्ताह के लिए प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित; एलपीसी दिल्ली-आरएमएस-दिल्ली-110006 से प्रत्येक शनिवार और सोमवार को प्रेषित; कुल पन्नों की संख्या 62 (आवरण सहित)

VISIT…

पतंजलि®

प्रकृति का आशीर्वाद

51
बेशकीमती
जड़ी–बूटियों से युक्त

"इन्टरनेशनल रिसर्च* से साबित है
कि पतंजलि च्यवनप्राश

इम्यूनिटी बढ़ाये

और

**दे इन्फ्लेमेशन
से लड़ने की ताकत**"

*कफ़-कोल्ड को दूर करके
रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने व
सभी रोगों से लड़ने की शक्ति देने वाला
आयुर्वेदिक रसायन,
पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए।*

*प्रकाशित रिसर्च पेपर की अधिक जानकारी हेतु विज़िट करें:
www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphar.2021.751576/full

ऑनलाइन खरीदें– www.patanjaliayurved.net | कस्टमर केयर - 18001804108 | ई–मेल - feedback@patanjaliayurved.org | वेबसाइट - www.patanjaliayurved.org

प्रधान संपादक की कलम से

हम अपने राजनैतिक नेताओं के बारे में उनके पहले के रवैए के मद्देनजर खराब ही सोचने के आदी हैं. लेकिन कई बार वे हमें चौंका देते हैं. जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने हालिया बजट से किया. अमूमन यही माना जाता है कि नेताओं का मुख्य मकसद चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने का होता है. उत्तर प्रदेश जैसे अहम राज्य के साथ पांच राज्यों में चुनाव होने हैं तो उम्मीद यही थी कि यह बजट मतदाताओं को लुभाने के लिए रियायतों से भरा होगा. हालांकि वित्त मंत्री ने उस लालच पर काबू पाया और महामारी के दबाव के बावजूद राजकोषीय संतुलन का ख्याल रखने वाला बजट पेश किया.

करीब 93 साल पहले आई महामंदी ने दुनिया भर में बेरोजगारों, बेघरों की फौज बढ़ाई और कारोबार को धराशायी कर दिया था. उस विनाशकारी घटना के अध्ययन में अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने सार्वजनिक नीतियों के जरिए सरकारी हस्तक्षेप की वकालत की थी. सीतारमण ने वही टुकड़ों में किया. उन्होंने रपटती अर्थव्यवस्था को महामारी के पहले की स्थिति में लाने के लिए 7.5 लाख करोड़ रु. के पूंजीगत खर्च का ऐलान किया, जो 35 फीसद का इजाफा है. उनके बजट का बड़ा फोकस आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भारी सार्वजनिक खर्चे पर है, जिसमें सड़क, रेल, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, नौ परिवहन और लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर जैसे आर्थिक वृद्धि के सात इंजनों पर जोर है. सरकार को उम्मीद है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर पर इस जोर से पांच साल में 60 लाख रोजगार पैदा होंगे. उसमें नल जल मिशन के लिए 60,000 करोड़ रु. का प्रावधान है और शहरी तथा ग्रामीण गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाने का वादा है. बजट में राज्यों को अपनी प्राथमिकताएं तय करने के लिए ब्याज-मुक्त कर्ज एक लाख करोड़ रु. तक बढ़ा दिया गया है. उसमें एक लाख करोड़ रु. के सैन्य उपकरण देसी उद्योग से खरीदने की प्रतिबद्धता जताई गई है.

17 फरवरी, 2021

सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) के आंकड़ों के मुताबिक, देश 2018 और 2021 के बीच सबसे लंबी मंदी का शिकार हुआ. इस अवधि में देश में बेरोजगारी औसतन 7.2 फीसद रही, जबकि वैश्विक बेरोजगारी दर 5.7 फीसद थी. माना जाता है कि महामारी की दूसरी लहर में एक करोड़ लोग रोजगार गंवा बैठे. 2020-21 में अर्थव्यवस्था 7.3 फीसद सिकुड़ गई. थोक मूल्य महंगाई दो अंकों में है, ईंधन और बिजली क्षेत्र की कीमतें 20 फीसद बढ़ गई हैं. इसी से जुड़ा राजकोषीय घाटा है, जो बताता है कि सरकार की कमाई और खर्च कितना है. 2022 में इसके 6.9 फीसद रहने का अनुमान है. ऐसे में सरकार अर्थव्यवस्था को झटका दिए बगैर खर्च करना जारी नहीं रख सकती. उसकी देनदारी पहले ही काफी ऊंची है; कर्ज भुगतान में बजट का 20 फीसद चला जाता है. बजट का करीब 80 फीसद पहले से तय खर्चों में ही निबट जाता है. इसलिए सरकार के पास कुछ करने की गुंजाइश थोड़ी रह जाती है. ओमिक्रॉन के साये ने इसे बदतर ही बनाया है. शुक्र है कि तीसरी लहर दूसरी जैसी विनाशकारी नहीं है, लेकिन उसने अनिश्चित-सा रवैया ही जाहिर किया है.

खुशखबरी की हल्की रेखा झलकने लगी है. आर्थिक गतिविधियों में इजाफे से इस वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में देश की जीडीपी वृद्धि दर 8.4 फीसद रही. जनवरी में जीएसटी की आमद 1.4 लाख करोड़ रु. के रिकॉर्ड पर पहुंच गई. विश्व बैंक और आइएमएफ के मुताबिक, भारत 2021-24 में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज बढ़त दर्ज करता रहेगा. आइएमएफ ने 2023-24 में वास्तविक जीडीपी वृद्धि 7.1 फीसद रहने का अनुमान लगाया है. सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण का आकलन है कि 2021-22 में जीडीपी वृद्धि दर 9.2 फीसद रहेगी. अर्थशास्त्रियों का कहना है कि हमें महामारी के पहले वाली स्थिति में पहुंचने के लिए 10 फीसद वृद्धि की जरूरत होगी. अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए सरकार के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर देने की यही वजह है.

सरकार शहरी मनरेगा जैसी योजना लाने से बची, जिससे शहरी इलाकों में वेतन भुगतान होता. ग्रामीण मनरेगा के प्रावधान को भी 25 फीसद घटा दिया गया. इससे दो बातों के संकेत मिलते हैं. या तो सरकार का मानना है कि गांवों में रोजगार की स्थिति उतनी बुरी नहीं है, या फिर वह खैरात के बदले इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के बहुआयामी असर पर ज्यादा भरोसा कर रही है. लेकिन इस बहुआयामी असर को अर्थव्यवस्था में उतरने और बेहद जरूरी रोजगार सृजन में वक्त लगेगा. किसानों के घाव सहलाने की कोशिश 1.63 करोड़ किसानों से गेहूं और धान की खरीद के लिए 2.37 लाख करोड़ रु. के प्रावधान का वादा करके की गई है.

सरकार महामारी की सबसे बुरी मार झेलने वाले मध्य वर्ग और गरीबों के हाथ में तत्काल पैसा देकर ज्यादा कुछ कर सकती थी, लेकिन उसे अपना राजकोषीय घाटे का लक्ष्य हासिल करना है तो उसके पास पैसे ही नहीं थे. खासकर पिछले बजट में बड़े धूम-धड़ाके के साथ घोषित किए गए 1.75 लाख करोड़ रु. के निजीकरण की योजना भी औंधे मुंह गिर गई. अप्रैल से दिसंबर 2021 तक वह सिर्फ 9,364 करोड़ रु. ही जुटा पाई. सरकार को उम्मीद है कि एलआइसी के सूचीबद्ध होने से यह आंकड़ा मार्च तक बढ़ेगा. इससे भी निराशाजनक तथ्य यह है कि अगले वित्त वर्ष के लिए विनिवेश का आंकड़ा 65,000 करोड़ रु. पर आ गया है, जो पिछले साल के मुकाबले आधे से भी कम है. हमारे पास इस अंक में देश के मध्य वर्ग और गरीबों पर आर्थिक दुर्दशा के असर पर खास रिपोर्टें हैं.

देश में लगातार बड़ी समस्या अमल की रही है. भारी-भरकम रकम का प्रावधान और बड़ी योजनाओं का ऐलान किया जाता रहा है, लेकिन बजट के मुताबिक खर्च नहीं हो पाता. केंद्र सरकार 2021 के बजट में किए गए प्रावधान का सिर्फ 59.6 फीसद ही खर्च कर पाई. उसने उस वर्ष के लिए 5.54 लाख करोड़ रु. कैपेक्स का लक्ष्य रखा था लेकिन नवंबर तक सिर्फ 49 फीसद (2.73 लाख करोड़ रु.) हासिल कर पाई. इस सरकार की सबसे बड़ी चुनौती लेटलतीफ और सुस्त नौकरशाही से काम करवाना है. एग्जीक्युटिव एडिटर एम.जी. अरुण अपनी खास रपट में पड़ताल करते हैं कि खर्च के अंतर को कैसे पाटा जाए. हमारे बजट पैकेज 'इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव' को हमारे ब्यूरो ने तैयार किया है और आकलन किया है कि क्या बजट अर्थव्यवस्था की वृद्धि और रोजगार की रफ्तार बढ़ा पाएगा.

सरकार ने आजादी के शताब्दी वर्ष 2047 तक अगले 25 साल के अमृत काल की रूपरेखा भी बनाई है. यह सराहनीय लक्ष्य है. लेकिन हमें कीन्स की दूसरी दलील भी याद कर लेनी चाहिए कि सरकारों को लंबे दौर में बाजार की ताकतों के समस्या सुलझा लेने का इंतजार करने के बजाए अल्प अवधि में समस्या का हल निकाल लेना चाहिए. उन्होंने लिखा है, ''लंबे वक्त में हम सब मर जाएंगे.'' इसके अलावा, इस सरकार ने इस बात पर दांव लगाया है कि इन्फ्रास्ट्रक्चर में उसके निवेश से दो साल में अर्थव्यवस्था जोरदार ढंग से उठ खड़ी होगी, जब 2024 में आम चुनाव का वक्त आएगा.

अरुण पुरी

(अरुण पुरी)

इंडिया टुडे

www.indiatodayhindi.in

चेयरमैन और प्रधान संपादक: अरुण पुरी
वाइस चेयरपर्सन: कली पुरी
ग्रुप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: दिनेश भाटिया
ग्रुप एडिटोरियल डायरेक्टर: राज चेंगप्पा
चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर: मनोज शर्मा
एडिटर: सौरभ द्विवेदी
सीनियर डिप्टी एडिटर: दयाशंकर शुक्ल सागर
सीनियर एडिटर: मोहम्मद वक़ास
एसोसिएट एडिटर: शिवकेश मिश्र, आशीष मिश्र (लखनऊ)
असिस्टेंट एडिटर: मनीष दीक्षित, सुजीत ठाकुर
राज्य ब्यूरो: पुष्यमित्र (पटना), रोहित परिहार (जयपुर), एम.जी. अरुण (मुंबई), राहुल नरोन्हा (भोपाल), अमरनाथ के. मेनन (हैदराबाद)
ग्रुप क्रिएटिव एडिटर: नीलांजन दास
एसोसिएट आर्ट डायरेक्टर: चंद्रमोहन ज्योति
असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर: असित रॉय
ग्रुप फोटो एडिटर: बंदीप सिंह
फोटो डिपार्टमेंट: यासिर इकबाल, राजवंत रावत, चंद्रदीप कुमार, मंदार सुरेश देवधर (मुंबई)
चीफ फोटो रिसर्चर: प्रभाकर तिवारी
प्रिंसिपल फोटो रिसर्चर: सलोनी वैद
प्रोडक्शन चीफ: अभिनव पुणला
एसोसिएट पब्लिशर: विद्या मेनन (इंपैक्ट)
इंपैक्ट टीम
नेशनल हेड: सुपर्णा कुमार (गवर्नमेंट ऐंड पीएसयू)
सीनियर जनरल मैनेजर: जीतेंद्र लाड (वेस्ट)
जनरल मैनेजर: मयूर रस्तोगी (नॉर्थ), उपेंद्र सिंह (बेंगलूरु)
डिप्टी जनरल मैनेजर: इंद्रनील चटर्जी (ईस्ट)
ग्रुप चीफ मार्केटिंग ऑफिसर: विवेक मल्होत्रा
सेल्स एवं ऑपरेशन
सीनियर जनरल मैनेजर: दीपक भट्ट (नेशनल सेल्स)
जनरल मैनेजर: विपिन वग्गा (ऑपरेशंस)
डिप्टी जनरल मैनेजर: राजीव गांधी (नॉर्थ)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: योगेश गोधनलाल गौतम (वेस्ट)
डिप्टी रीजनल सेल्स मैनेजर: एस. परमशिवम (साउथ)
सीनियर सेल्स मैनेजर: पीयूष रंजन दास (ईस्ट)

INDIA TODAY GROUP

वर्ष: 36; अंक: 11; 10-16 फरवरी, 2022; प्रत्येक शनिवार को प्रकाशित

- **संपादकीय कॉर्पोरेट कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, इंडिया टुडे ग्रुप मीडियाप्लेक्स, एफसी-8, सेक्टर 16-ए, फिल्म सिटी, नोएडा-201301, फोन: 0120-4807100;
- **ग्राहकी चंदा भेजें:** इंडिया टुडे (हिंदी), पो. बॉक्स 114, नई दिल्ली-110001
- **ग्राहक सेवा:** कस्टमर केयर, इंडिया टुडे ग्रुप, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301, टोल फ्री फोन नं. 1800 1800 100 (बीएसएनएल/एमटीएनएल लाइनों से) फोन: दिल्ली, फरीदाबाद से (95120) 2479900; शेष भारत से (0120) 2479900. (सोम से शुक्र-सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक), फैक्स: (0120) 4078080. ई-मेल: wecare@intoday.com
- **सर्कुलेशन कार्यालय:** लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड, सी-9, सेक्टर-10, नोएडा (उत्तर प्रदेश)-201301
- **इंपैक्ट कार्यालय:** 1201, 12वां तल, टावर 2ए, वन इंडियाबुल्स सेंटर, (जुपिटर मिल्स) एस.बी. मार्ग, लोअर परेल (पश्चिम)-मुंबई-400013. फोन: 022-66063355 फैक्स: 022-66063226
- **क्षेत्रीय विज्ञापन कार्यालय:** ए1-ए2, एनके सेंटर, विनुज्य निकुंज, उद्योग विहार, फेज-5, गुड़गांव, हरियाणा, फोन: 0124-4948400;
- 201-204 रिचमंड टावर्स, द्वितीय मंजिल, 12 रिचमंड रोड, बंगलुरु-560 025 फोन: 2212448, 226233, टेलेक्स: 0845-2217 INTO IN. फैक्स: 080-2218335.
- रजिस्टर्ड कार्यालय: एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001
- लिविंग मीडिया इंडिया लि. विश्व भर में सर्वाधिकार सुरक्षित. किसी भी रूप में सामग्री की नकल प्रतिबंधित. इंडिया टुडे अनिमंत्रित प्रकाशन सामग्री को लौटाने की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करता.
- सभी विवादों का निबटारा दिल्ली/नई दिल्ली की सीमा में आने वाली सक्षम अदालतों और फोरमों में किया जाएगा.
- **लिविंग मीडिया इंडिया लि. के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक मनोज शर्मा द्वारा एफ-26, फर्स्ट फ्लोर, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली-110001 से प्रकाशित और थॉमसन प्रेस इंडिया लि., 18-35, माइलस्टोन, दिल्ली-मथुरा रोड, फरीदाबाद-121 007 (हरियाणा) में मुद्रित. संपादक: राज चेंगप्पा**

सुर्खियां
माओवादी: सरेंडर की पॉलिसी कितनी कामयाब
पेज 5

भीतर

फुरसत
सवाल-जवाब/वामिका गब्बी: ओशो की दीवानी
पेज 60

बुनियादी ढांचे पर जोर

मोदी सरकार बुनियादी ढांचे में निवेश करके देश को तेज विकास की राह पर लाना चाहती है. लेकिन इस मकसद को हासिल करने के लिए प्रभावी क्रियान्वयन बेहद महत्वपूर्ण है.

केंद्रीय बजट 2022

1 क्रियान्वयन *20*
2 गरीबी *24*
3 मध्य वर्ग *30*
4 प्रतिरक्षा *36*
5 स्वास्थ्य *38*
6 कृषि *39*
7 शिक्षा *40*
8 क्रिप्टोकरेंसी *41*

चंद्रदीप कुमार

विधानसभा चुनाव 2022

उत्तर प्रदेश

42 चेहरा बदलती मुस्लिम सियासत

सियासी दलों ने इस बार नए और युवा चेहरों को बनाया उम्मीदवार

पश्चिमी यूपी

48 वफादारी की जंग

दो ध्रुवों के बीच झूल रहे यहां के मतदाता गहरी दुविधा में हैं

गोवा

50 मांडवी के तट पर मंडल राग

पिछड़ी जाति की राजनीति गोवा का चुनावी माहौल बदल रही

उत्तराखंड

53 अपने ही घर में खैर नहीं

प्रतिद्वंद्वियों से घिरे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भाजपा के गढ़ में कठिन चुनाव लड़ने को मजबूर

इंडिया टुडे

इंडिया टुडे मैगजीन मिलने में दिक्कत हो रही है?
7303086006 पर नाम पता या 'हेलो' संदेश भेजें.
या मेल करें: wecare@intoday.com
हम आपसे संपर्क कर लेंगे.

आवरण: नीलांजन दास

पाठकों के लिए सूचना: कभी-कभी आपको इंडिया टुडे पत्रिका में 'इम्पैक्ट फीचर' या 'एडवरटोरियल' या 'फोकस' के पन्ने नजर आएंगे. ये विज्ञापन होंगे और इन्हें बनाने में पत्रिका के संपादकीय स्टाफ शामिल नहीं होते.

INDIA TODAY GROUP

पाठकों को सलाह दी जाती है कि पत्रिका में प्रकाशित किसी भी सेवा या व्यक्ति के विज्ञापन और प्रचार से संबंधित सामग्री से वचनबद्धता कायम करने, पैसा भेजने या खर्च करने से पहले उचित जांच-पड़ताल कर लें. विज्ञापनदाताओं के किसी भी दावे का उत्तरदायित्व इंडिया टुडे ग्रुप का नहीं है. ऐसे किसी भी तरह के दावों को विज्ञापनदाता अगर नहीं पूरा करता है तो इंडिया टुडे ग्रुप के प्रकाशनों के मुद्रक, प्रकाशक, एडिटर-इन-चीफ और एडिटर इसके लिए जिम्मेदार नहीं होंगे.

समाचार सारः
असहज शुरुआत
पेज 7

झारखंडः जबान पर
छिड़ी नई जंग
पेज 8

सुर्खियां

रीट 2021 घोटालाः
घालमेल का फैलता दायरा
पेज 10

बड़ी कामयाबी
सुकमा जिले के मलाईगुड़ा कैंप में गणतंत्र दिवस पर सरेंडर करने वाले 23 माओवादियों के साथ सुरक्षाकर्मी

माओवादी

सरेंडर की पॉलिसी कितनी कामयाब

राहुल नरोन्हा

मध्य प्रदेश में सक्रिय सात बड़े माओवादियों ने बीते एक साल में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में समर्पण किया. इनमें डिविजनल कमांडर दिवाकर भी है, जिसे महाराष्ट्र-मध्य प्रदेश-छत्तीसगढ़ के नए इलाके में विस्तार का काम सौंपा गया था. समर्पण करने में तो खैर कोई बुराई नहीं पर यह समर्पण दिलचस्प इसलिए हैं क्योंकि 2010 के बाद एक भी माओवादी ने मध्य प्रदेश में हथियार नहीं डाले. नतीजतन, मध्य प्रदेश पुलिस को इन प्रमुख माओवादियों (और उनसे मिलने वाली सूचनाओं) तक पहुंचने के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है.

दूसरे राज्यों में हो रहे समर्पणों से प्रेरित होकर मध्य प्रदेश सरकार अपनी मौजूदा 1997 की माओवादी समर्पण नीति की कमियों और खामियों को दूर करने के लिए नई 'माओवादी समर्पण और पुनर्वास नीति' का मसौदा लेकर आई है. सूत्र कहते हैं कि यह माओवादियों से समर्पण करवाने के मामले में वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों के बीच छिड़ी आपसी होड़ का नतीजा है. केंद्र सरकार की ओर से 2014 में माओवादी समर्पण और पुनर्वास नीति का सूत्रपात करने के बाद ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र सहित कई ऐसे राज्यों ने अपनी-अपनी समर्पण नीतियों में फेरबदल किया. मगर उन्हें मिली-जुली कामयाबी ही मिली.

मध्य प्रदेश की मसौदा नीति बताती है कि इसके तहत मिलने वाले फायदों का पात्र कौन होगा. इनमें मध्य प्रदेश के भीतर और बाहर दोनों जगह रहकर गैरकानूनी गतिविधियों में लिप्त लोग शामिल हैं. उन्हें 5 लाख रुपए या उस माओवादी कार्यकर्ता के सिर पर रखे गए इनाम की रकम में से जो भी ज्यादा हो, मिलेगी. इसके अलावा पुलिस के हवाले किए गए हथियारों और गोला-बारूद के लिए अतिरिक्त धनराशि दी जाएगी. पिछले अपराधों

के लिए माफी का भी प्रावधान है. ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की नीतियों की देखा-देखी, अन्य माओवादी सदस्यों, वित्तीय स्रोतों, असलहे और गोला-बारूद के बारे में जानकारी देने की जिम्मेदारी हथियार डालने वाले माओवादी की होगी. राज्य स्तर की एक समिति प्रक्रिया की छानबीन करके फैसला लेगी कि समर्पण स्वीकार किया जाए या नहीं. मगर समर्पण के लिए उग्रवादियों की कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की गई है, जैसा ओडिशा ने किया है.

मध्य प्रदेश की मसौदा नीति में ज्यादा जोर समर्पण करने वाले माओवादियों के पुनर्वास पर दिया गया है. उन्हें कौशल विकास के लिए तीन महीने तक प्रति माह 6,000 रुपए और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान देने का प्रावधान है. पुनर्वास नीति, पढ़ने के इच्छुक माओवादी कार्यकर्ता को 36 महीने तक प्रति माह 2,000 रुपए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत अनाज, स्वास्थ्य बीमा और खुफिया जानकारी जुटाने में मदद देने के काम के लिए गोपनीय सैनिक के तौर पर रोजगार देने की पेशकश करती है. हथियार डालने वाला कार्यकर्ता अगर दूसरे माओवादियों के खात्मे या गिरफ्तारी में मदद करता है तो उसे पुलिस बल में पूर्णकालिक कॉन्स्टेबल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है. दिलचस्प यह कि समर्पण के वक्त अगर वह नक्सली अविवाहित है तो इस नीति में उसे शादी के लिए 25,000 रुपए देने का प्रावधान है.

पिछले अपराधों के लिए माफी सभी समर्पण नीतियों में विवादास्पद मुद्दा रहा है. मध्य प्रदेश की मसौदा नीति इस पर भी ध्यान देती है. छानबीन समिति समर्पण से पहले किए गए अपराधों के मामले वापस लेने की सिफारिश कर सकेगी. अलबत्ता चूंकि कानून में गंभीर अपराधों के लिए माफी का प्रावधान नहीं है, लिहाजा आम तौर पर होता यह है कि ऐसे अपराधों के लिए अदालत में चालान (आरोपपत्र) ही दाखिल नहीं किए जाते. राज्य के एक बड़े पुलिस अफसर कहते हैं, ''इससे राज्य को समर्पण करने वाले नक्सली पर सरकार का नियंत्रण बनाए रखने में भी मदद मिलती है, खासकर जब उनके ऊपर फिर अपराध की दुनिया में लौट जाने का दबाव होता है.'' माओवादी हिंसा में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए खेती की जमीन, रोजगार और नकद मुआवजा देने के प्रावधान भी इस मसौदा नीति में हैं. मध्य प्रदेश में संयोग

चंगुल में बड़ा नक्सली माओवादी नेता दिवाकर और उसकी पत्नी छत्तीसगढ़ पुलिस की हिरासत में

से अब तीन ही जिले, मंडला, डिंडोरी और बालाघाट आधिकारिक तौर पर माओवाद से प्रभावित रह गए हैं. भारत की विद्रोह विरोधी रणनीतियों में समर्पण और पुनर्वास पर बहुत ज्यादा जोर रहा, लेकिन 2014 की राष्ट्रीय नीति के बाद अब उन्हें तर्कसंगत और आसान बनाया गया है. माओवाद प्रभावित राज्यों में समर्पण नीतियों को लागू करने का अनुभव मिला-जुला रहा है. मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में, जहां माओवाद का फैलाव और प्रभाव ज्यादा रहा है, उसकी नीति के शुरुआती दिनों में भ्रष्टाचार और फर्जी समर्पण की कई खबरें सामने आई थीं.

माओवाद प्रभावित राज्यों में समर्पण नीति का मिश्रित परिणाम दिखा है: आंध्र को सफलता मिली पर छत्तीसगढ़ बहुत ज्यादा सफल नहीं रहा

छत्तीसगढ़ ने पहली समर्पण और पुनर्वास नीति 2004 में घोषित की, पर उसे ज्यादा कामयाबी नहीं मिली. 2004 और 2014 के बीच, जब राज्य ने दूसरी नीति का ऐलान किया तो कुल जमा कोई सौ लोगों ने समर्पण किया. फर्जी समर्पण और सरगनाओं के बजाए सुरक्षाकर्मियों के हाथों मजबूर छुटभैयों के समर्पण को लेकर तब भी सवाल उठाए गए थे. दूसरी नीति के बाद 2016 में कोई 1,160 कथित माओवादियों ने समर्पण किया, पर केंद्र सरकार की छानबीन समिति ने फैसला दिया कि उनमें से 1,000 से ज्यादा लोग माओवादी कहलाने लायक नहीं थे. उससे एक साल पहले राज्य सरकार की छानबीन समिति ने भी पाया कि समर्पण करने वाले 75 फीसद माओवादी कार्यकर्ता पुनर्वास पैकेज के पात्र नहीं थे.

दूसरी तरफ, आंध्र प्रदेश की समर्पण और पुनर्वास नीति ज्यादा कामयाब रही, जो 1993 में लाई गई और लगातार बेहतर बनाई गई. 2005 से 2015 के बीच आंध्र प्रदेश में माओवादी घटनाएं 500 से घटकर दो पर आ गईं. नक्सलरोधी ग्रेहाउंड फोर्स को इसका श्रेय दिया गया पर मध्य प्रदेश के अधिकारी कहते हैं कि इसमें पुनर्वास उपायों का भी बराबर योगदान है. रिमोट ऐंड इंटरनल एरिया डेवलपमेंट योजना के तहत पुनर्वास कार्यक्रम का पूरा फोकस ग्रामीण इलाकों पर रहा. विश्लेषक कहते हैं कि इन उपायों से माओवादियों की नए रंगरूटों की खोज पर असर पड़ा है.

मगर समर्पण और पुनर्वास नीति से उग्रवादी गतिविधियां क्या कमजोर होती दिखाई देती हैं? मध्य प्रदेश में नक्सल ऑपरेशंस के आइजी साजिद फरीद शापू कहते हैं, ''कतई नहीं. माओवाद से निबटने में आंध्र प्रदेश के मॉडल की कामयाबी से पता चलता है कि समर्पण का सीधा संबंध कार्रवाइयों के जरिए उनके ऊपर डाले गए दबाव से है. इस मोर्चे पर कोई ढिलाई नहीं होनी चाहिए. समर्पण नीति की कामयाबी दरअसल बहुत कुछ कार्रवाइयों की कामयाबी पर निर्भर है.'' मध्य प्रदेश भी माओवाद से निबटने के लिए उनके इलाकों में पूरी तरह आदिवासियों के बल का गठन कर रहा है. वैसे, पूर्वी मध्य प्रदेश में इस काम के लिए एक समर्पित सशस्त्र बल 'द हॉक' पहले से है. ■

समाचार सार

राहुल की असहज शुरुआत

कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए नए साल की शुरुआत कुछ अच्छी नहीं रही. सबसे पहले उनके निकट मित्रों में से एक आर.पी.एन. सिंह पाला बदलकर भाजपा में चले गए. पंजाब के अपने हालिया दौरे में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने देखा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू आगामी चुनावों के लिए खुद को सीएम कैंडिडेट के रूप में नामित करने की मांग कर रहे थे. यहां भले ही राहुल ने उस फैसले को यह कहते हुए टाल दिया हो कि पार्टी इस बारे में कार्यकर्ताओं से बात करेगी लेकिन कांग्रेस शासित छत्तीसगढ़ में कलह सतह पर आने लगी है. राज्य के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने कह दिया कि भूपेश बघेल के बाद उन्हें रोटेशन के आधार पर मुख्यमंत्री की कुर्सी देने का वादा था. लगता है राहुल के लिए दुश्वारियां दल बांधकर आई हैं.

इलस्ट्रेशनः सिद्धांत जुमडे

...मुझे पहचानो?

केरल के मुख्यमंत्री **पिनाराई विजयन** को अपने झक्क सफेद मुंडू और आधी आस्तीन के कुर्ते के अलावा दूसरे किसी लिबास में शायद ही देखा गया हो. लेकिन अमेरिका में दो हफ्ते चले इलाज ने शायद उनका मेकओवर कर दिया है. मुख्यमंत्री को हाल ही में दुबई में एक संक्षिप्त पड़ाव के दौरान देखा गया, जहां उनकी कई आधिकारिक व्यस्तताएं थीं. उन्हें अपने बेटे से भी मुलाकात करनी थी जो वहां काम करते हैं. वहां पूरी बाजू की सफेद कमीज और काली पतलून में विजयन पहचान में ही नहीं आ रहे थे. शायद यही उनका मकसद भी था—राज्य में विपक्ष उनकी वापसी की मांग कर रहा है कि वे आएं और केरल में कोविड-19 के बदतर होते संकट की जिम्मेदारी उठाएं.

एएनआइ

शराब और सूचना

बिहार के शिक्षक उस वक्त चकरा गए जब 28 जनवरी को शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी किया, जिसमें उन्हें शराब के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूकता फैलाने का निर्देश दिया गया था. शिक्षकों को कहा गया था कि वे किसी को भी अवैध रूप से शराब बेचता पाएं तो गुप्त रूप से इसकी सूचना अधिकारियों को दें. बहरहाल, एक दिन के बाद शिक्षा मंत्री **विजय चौधरी** ने स्पष्ट किया कि ऐसी सूचना देना कोई अनिवार्य नहीं है. जाहिर है, अभी भी विकल्प खुला है?

जो जागेगा, सो पावेगा

हालांकि, तेलंगाना में अगले विधानसभा चुनाव नवंबर 2023 में होने हैं, लेकिन चर्चा है कि मुख्यमंत्री **के. चंद्रशेखर** राव समय से पहले चुनाव करवाने की सोच रहे हैं. उन्होंने हाल ही में 21 विधायकों, तीन सांसदों और दो विधान परिषद सदस्यों को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है. वे इसी महीने पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी समिति की घोषणा करने वाले हैं. यह पांच साल के अंतराल पर हुआ है. लेकिन चुनाव के मामले में यह अब भी जल्दी है.

—संदीप उन्नीथन, साथ में अनिलेश एस. महाजन, राहुल नरोन्हा, अमिताभ श्रीवास्तव, अमरनाथ के. मेनन और जीमॉन जैकब

आनंद दत्त

नाराजगी
'बाहरी भाषा नाय चलतो' नारे के साथ विरोध-प्रदर्शन में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया

झारखंड

जबान पर छिड़ी नई जंग

आनंद दत्त, रांची से

जनवरी की 30 तारीख को झारखंड के धनबाद और बोकारो में हजारों आदिवासी और मूलनिवासी सड़कों पर उतर आए. उन्होंने वहां करीब 50 किलोमीटर की मानव शृंखला बनाई. इसी के साथ राज्य में भाषाई युद्ध छिड़ गया. दरअसल, ये लोग झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (जेएसएससी) की ओर से मैट्रिक और इंटर स्तरीय परीक्षाओं के लिए क्षेत्रीय भाषा की श्रेणी में भोजपुरी, मगही, अंगिका और उर्दू को जगह दिए जाने का विरोध कर रहे हैं. आंदोलनकारियों को क्षेत्रीय भाषा के तौर पर बाहरी (बिहारी) भाषाएं मंजूर नहीं हैं.

नाराजगी इतनी ज्यादा है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान बोकारो में रास्ते से गुजर रहे भाजपा नेता और पूर्व सांसद रवींद्र राय को लोगों ने खदेड़ दिया. उनकी गाड़ी पर हमला किया गया और उसके शीशे तोड़ दिए. उन्होंने 200 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआइआर दर्ज कराई है.

दरअसल, झारखंड सरकार ने बीते 23 दिसंबर, 2021 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था. इसके मुताबिक, जेएसएससी की ओर से मैट्रिक और इंटर स्तरीय परीक्षाओं के लिए जनजातीय भाषा की श्रेणी में संथाली, कुडुख, खड़िया, हो, मुंडारी, असुर, बिरजिया, बिरहोरी, भूमिज और माल्तो को शामिल किया गया. वहीं, क्षेत्रीय भाषा की श्रेणी में नागपुरी, पंचपरगनिया, बांगला, अंगिका, कुरमाली, मगही, उड़िया, खोरठा और भोजपुरी को जगह दी गई. अगले दिन एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ और उर्दू को सभी जिलों की क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल कर दिया गया.

जिलावार जारी सूची के मुताबिक, बोकारो और धनबाद में क्षेत्रीय भाषा की श्रेणी में भोजपुरी, मगही, उर्दू, खोरठा, बांग्ला, कुरमाली और नागपुरी को रखा गया है. आंदोलन में शामिल बोकारो के पत्रकार और तुपकाडीह गांव के रहनेवाले 29 वर्षीय तीर्थनाथ आकाश कहते हैं, ''इन दो जिलों में भोजपुरी, मगही बोलने वाले लोग न के बराबर हैं. जो लोग हैं, वे किराएदार हैं या हाल के वर्षों में जमीन खरीदकर यहां बस गए हैं. हम इन्हें बाहरी और अतिक्रमणकारी मानते हैं. यहां अधिकतर लोग खोरठा बोलते हैं.'' जब खोरठा शामिल है, फिर विरोध क्यों? बोकारो जेनामोड़ के सामाजिक कार्यकर्ता और किसान 39 वर्षीय सोहराय हांसदा बताते हैं, ''इन भाषाओं के लोग अगर नियुक्त होते हैं तो वे सीधे गांव तक पहुंच जाएंगे. वे अपनी भाषा लेकर ही जाएंगे. उसके प्रचार-प्रसार के लिए उनके पास अथाह सामग्री है. मसलन, सरस्वती पूजा में केवल भोजपुरी गाना सुनने को मिल रहा है. ऐसे में खोरठा कहां तक टिक पाएगी? हम अगली पीढ़ी को अपनी भाषा कहां से दे पाएंगे?''

यह रोजगार से भी जुड़ा हुआ मसला है. रांची यूनिवर्सिटी में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग के प्रमुख प्रो. हरि उरांव कहते हैं,

''झारखंडी भाषाओं में अब पीजी स्तर तक पढ़ाई होती है. फेलोशिप, स्कॉलरशिप मिल रही हैं. नौकरी भी मिल रही है. लोगों को भविष्य दिख रहा है. उन्हें आभास हो रहा है कि अगर भोजपुरी, मगही को जगह मिल गई तो उनके लिए रोजगार के मौके कम हो जाएंगे.''

जेएसएससी कई सारे पदों पर भर्तियां निकालती है. जिला और राज्यस्तरीय नियुक्तियों में एक पेपर क्षेत्रीय-जनजातीय भाषा का भी होगा, जिसके प्राप्तांक को जोड़कर मेरिट लिस्ट बनेगी. आंदोलनकारियों का मानना है कि खोरठा एवं अन्य जनजातीय भाषाओं के मुकाबले भोजपुरी, मगही, अंगिका के सिलेबस की किताबें अधिक उपलब्ध हैं जिससे इनके परीक्षार्थियों के पास करने की संभावना अधिक होगी. तोपचांची, धनबाद के रहनेवाले जयराम महतो का कहना है कि जिलावार नियुक्ति स्थानीय लोगों को वरीयता देने के लिए होती है. वे कहते हैं, ''हम बिहार और यूपी के लोगों से मुकाबला नहीं कर सकते. अगर हम स्थानीय भाषा में परीक्षा देंगे तो उनसे बेहतर कर पाएंगे.''

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2021 को नियुक्ति वर्ष घोषित किया था. कोरोना का वास्ता देकर वे 2022 में अपने नौकरी के वादे को पूरा करने की बात कह रहे हैं. जाहिर है, अगर क्षेत्रीय-जनजातीय भाषा में युवाओं को नौकरी मिलने लगे, तो उसे पाने की संभावना और उस भाषा के बचने की संभावना बढ़ जाती है.

इससे पहले 12 अगस्त, 2021 को जेएसएससी ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया था. उसमें क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में 30 फीसद अंक प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया था. इसी महीने पलामू और गढ़वा जिलों में हिंदी भाषा को क्षेत्रीय भाषा वर्ग में शामिल करने के लिए आंदोलन शुरू हुआ. दरअसल, बिहार से सटे होने के कारण इन जिलों में अधिकतर लोग हिंदी के अलावा भोजपुरी, मगही, अंगिका बोलते हैं. युवाओं को डर था कि नागपुरी, खोरठा को शामिल और अनिवार्य कर दिया गया तो उन्हें नौकरी नहीं मिल पाएगी. तब हिंदी को छोड़ भोजपुरी, मगही को जोड़ा गया. डाल्टनगंज की राजनीति में सक्रिय स्थानीय युवक 27 वर्षीय सन्नी शुक्ला कहते हैं, ''बोकारो और धनबाद में हुए आंदोलन के बाद हमें आशंका है कि फिर इन भाषाओं को हटा दिया जाएगा. इसके अलावा जिन भाषाओं को शामिल किया गया है, वे यहां नहीं बोली-समझी जातीं.''

भाषा आंदोलन के साथ स्थानीय नीति लागू करने की मांग भी जोर पकड़ रही है. बीते

नौकरी की कशमकश

- 4,125 पदों पर बहाली निकालने के लिए जेएसएससी की अधियाचना
- 1,301 पदों पर वैकेंसी निकाली गई
- 3,01,1 98 स्वीकृत पदों की कुल संख्या
- 2,44,016 पद सीधी नियुक्ति से भरे जाएंगे
- 57,182 पद प्रोन्नति के आधार पर भरे जाएंगे
- 8.9 फीसद है राज्य में बेरोजगारी दर

नोटः विभिन्न पदों की सभी भर्तियां जेएसएससी के जरिए; स्रोतः एल.एम. ख्यांग्ते समिति रिपोर्ट, जेएसएससी विज्ञापन, सीएमआइई रिपोर्ट

''अलग राज्य के आंदोलन के बाद पहली बार झारखंड में इतनी बड़ी संख्या में लोग अपनी भाषा के लिए सड़क पर उतरे हैं. अब यह लड़ाई रुकने वाली नहीं है''

गीताश्री उरांव
पूर्व शिक्षा मंत्री, झारखंड

विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेएमएम) ने 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीय नीति और फिर नियोजन नीति लागू करने का वादा किया था. वहीं, पूर्व की रघुवर दास सरकार ने इसके लिए 1985 को आधार वर्ष माना था. उसके मुताबिक, 1985 तक जो झारखंड आ गए थे, जिनके पास संपत्ति थी, उनको झारखंडी माना जाएगा. वैसे, हेमंत सरकार ने इसे अभी तक खारिज नहीं किया है. पर एक नियम जरूर जोड़ दिया गया है कि वही व्यक्ति सरकारी परीक्षाओं में शामिल हो पाएंगे जिन्होंने दसवीं-बारहवीं झारखंड से पास की है. कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर कहते हैं, ''एक ओर तो 1932 की बात की जा रही है. दूसरी ओर नए नियम से अगर कोई कभी भी दसवीं-बारहवीं झारखंड से पास करता है, तो उसे स्थानीय माना जाएगा. ये विरोधाभासी है.''

दो साल बाद भी सरकार ने अपना वह वादा नहीं निभाया है. इसको लेकर जेएमएम दबाव में है. शिबू सोरेन सहित सरकार में शामिल अन्य आदिवासी नेता और कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की जब भी इसे लागू करने की मांग उठाते हैं, कांग्रेस सहित अन्य दलों के गैर-आदिवासी नेता इसका विरोध करते हैं. बीती 29 जनवरी को जब कांग्रेस के झारखंड के नए प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे, तो पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव ने दोपहर के समारोह में उनका स्वागत किया. लेकिन शाम होते-होते स्थानीय नीति और भाषा पर पार्टी का रवैया स्पष्ट न होने का आरोप लगाते हुए उरांव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया. उरांव ने *इंडिया टुडे* को बताया, ''जिस भोजपुरी, मगही को बिहार में राजभाषा का दर्जा नहीं दिया गया है, उनको यहां की सरकार ने वरीयता दी है. इसमें कांग्रेस नेता भी शामिल हैं. इसके लिए अलग राज्य की लड़ाई नहीं लड़ी गई थी. किसी भी राज्य का मुख्य आधार तो उसकी भाषा, संस्कृति ही है.''

जेएमएम नेता और राज्य के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने 31 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि बोकारो और धनबाद से भोजपुरी तथा मगही को हटाया जाएगा. उन्होंने *इंडिया टुडे* से कहा, ''बोकारो, धनबाद, गिरिडीह में एक भी घर नहीं है जहां लोग भोजपुरी बोलते हों. उसको प्राथमिकता देने का कोई आधार नहीं.'' क्या कांग्रेस के दबाव में यह निर्णय लिया गया था? शिक्षा मंत्री ने सवाल को टालते हुए कहा, ''खुद ही समझ लीजिए.''

दरअसल, शहरी इलाकों में वोटरों को साधने के लिए रघुवर सरकार ने भोजपुरी, मैथिली, मगही और अंगिका को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया था. कांग्रेस ने अब यहां पैठ बढ़ाने के लिए इन भाषाओं को जोर देकर शामिल कराया है. वहीं, शिबू सोरेन ने मांझी-महतो यानी आदिवासी और महतो वर्ग का एक बड़ा वोट बैंक तैयार किया था. इसमें मूलनिवासी महतो का वोट छिटक-सा गया है. हेमंत इस वोटवर्ग को मजबूती से जोड़ना चाहते हैं. यही वजह है कि पहले उन इलाकों में भोजपुरी और मगही को शामिल करना, विरोध के बाद हटाना तथा क्षेत्रीय-जनजातीय भाषा में 30 फीसद अंक अनिवार्य जैसी कवायद लगातार की जा रही हैं. जाहिर है, भाषा के जरिए शह और मात का खेल जारी है. ■

रीट 2021 घोटाला

गहलोत का कड़ा इम्तिहान

रोहित परिहार

इकत्तीस हजार स्कूली शिक्षकों की भर्ती के लिए पिछले साल सितंबर में आयोजित राजस्थान पात्रता प्रवेश परीक्षा (रीट) में घोटाले के कारण—जिसमें परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला शामिल है—अशोक गहलोत सरकार बुरी तरह से घिर गई है. राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (एसओजी) की जांच के बाद पिछले हफ्ते इस सिलसिले में राजीव गांधी स्टडी सर्कल (आरजीएससी) के कई सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं या शक के घेरे में हैं. कांग्रेस समर्थित थिंक टैंक आरजीएससी के अध्यक्ष खुद मुख्यमंत्री गहलोत हैं. गहलोत के करीबी सहयोगी और उनकी सरकार में तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री सुभाष गर्ग इस संगठन के राष्ट्रीय समन्वयक हैं.

रीट परीक्षा के लिए 26 लाख से अधिक लोगों ने आवेदन किया था, जिनमें से 16 लाख परीक्षार्थियों ने 26 सितंबर, 2021 को परीक्षा दी थी. परीक्षा में घोटाले की बात परीक्षा के समय ही सामने आ गई थी जब एक प्रारंभिक सूचना में पुलिस को पता लगा था कि परीक्षा के दिन सवाई माधोपुर के कुछ परीक्षार्थियों ने प्रश्नपत्र का हल हासिल करने के लिए परीक्षा के दौरान ही कोटा में कुछ लोगों तक प्रश्नपत्र पहुंचा दिया था. गहलोत सरकार के लिए सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि उसके ऊपरी स्तर पर के आरोप लग रहे हैं. परीक्षा में हुई गड़बड़ी में भी कथित तौर पर कुछ पुलिस अधिकारियों के परिजन शामिल थे. जांच शुरू होने से अब तक 38 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

बीती 20 जनवरी को एसओजी ने गुजरात में भजनलाल बिश्नोई नाम के एक व्यक्ति समेत कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया जिसके बाद परीक्षा घोटाले के बड़े पैमाने का होने के और सबूत सामने आए. इन संदिग्धों से हुई पूछताछ के बाद राजस्थान के पुलिस महानिदेशक एम.एल. लाठर का कहना है, ''ऐसा लगता है कि प्रश्नपत्र बेचने का पहला सौदा 5 करोड़ रुपए में हुआ था, जिसके बाद कई सौ अन्य लोगों को 15 लाख रुपए तक में उसे बेच दिया गया.'' इस बात का भी संदेह है कि गहलोत सरकार के मंत्रियों और प्रदेश कांग्रेस कमेटी में शामिल नेताओं और उनके सहयोगियों ने इस व्यापक घोटाले में मदद की और लाभान्वित हुए.

> आरजीएससी के कई सदस्य गिरफ्तार हो गए हैं या शक के घेरे में हैं. यह कांग्रेस समर्थित थिंक टैंक है और मुख्यमंत्री गहलोत इसके चेयरमैन हैं

मुख्यमंत्री गहलोत व्यक्तिगत रूप से इस मामले पर नजर बनाए हुए हैं और इससे सरकार की प्रतिष्ठा पर आई आंच को कम करने का प्रयास कर रहे हैं. राज्य पुलिस की ओर से की गई गिरफ्तारियों का उन्होंने यह कहते हुए समर्थन किया है कि ''किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा.'' अपनी बात में वे जोड़ते हैं कि, ''मुझे एक बार *इंडिया टुडे* में यह कहते हुए उद्धृत किया गया था कि 'हर गलती सजा मांगती है.' अब रीट पेपर लीक के मामले में भी मैं उसी बात पर कायम हूं.'' गहलोत ने 30 जनवरी को आरजीएससी के सदस्य तथा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, डी.पी. जरोली को हटा दिया. इस बीच, गिरफ्तार लोगों की संख्या 38 तक पहुंचने के साथ ही गहलोत ने तीन अन्य अधिकारियों को निलंबित कर दिया. सभी तरह की भर्ती प्रक्रिया की सुरक्षा में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ने उच्च

सुर्खियां

बड़ी मुश्किल
(सामने) घोटाले की सीबीआइ जांच की मांग करते प्रदर्शनकारी; (इनसेट) डी.पी. जरोली; और राज्य मंत्री सुभाष गर्ग के साथ मुख्यमंत्री गहलोत

न्यायालय के पूर्व न्यायमूर्ति वी.के. व्यास की अध्यक्षता में एक समिति भी गठित की है. इसके अलावा उन्होंने घोषणा की है कि राज्य परीक्षाओं में प्रश्नपत्र लीक करने जैसी भर्ती संबंधी धोखाधड़ी के लिए दंड को और सख्त किए जाने वाले कानून बनाए जाएंगे.

फिर भी, इन प्रयासों से जनता का गुस्सा शांत नहीं हुआ है. पुलिस जांच से लगातार हो रहे पर्दाफाश से मिल रही मदद के चलते विपक्षी नेताओं के हमले भी लगातार जारी हैं. इस प्रकरण में सरकार के घोर आलोचकों में शामिल रहे सांसद और भाजपा नेता किरोड़ी लाल मीणा की मांग है कि राजस्थान सरकार इस मामले की जांच सीबीआइ (केंद्रीय जांच ब्यूरो) को सौंपे. उनका कहना है कि रीट की पूरी प्रक्रिया पैसा बनाने की कवायद थी और इसके हर चरण में भ्रष्टाचार था—पेपर सेट करने और उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने से लेकर परिणामों में हेरफेर करने और प्रश्न पत्रों को लीक करने तक. उन्होंने विशेष रूप से परीक्षा के समय पीसीसी अध्यक्ष और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के साथ-साथ राज्यमंत्री सुभाष गर्ग को भी निशाना बनाया है. गहलोत ने 2020 में सचिन पायलट की जगह डोटासरा को पीसीसी प्रमुख बनाया था. गर्ग राष्ट्रीय लोक दल के विधायक हैं और सरकार में मंत्री होने के साथ ही गहलोत के करीबी माने जाते हैं.

मीणा ने डोटासरा पर अपने निर्वाचन क्षेत्र सीकर में एक कोचिंग संस्थान के माध्यम से पेपर लीक करने की व्यवस्था करने का भी आरोप लगाते हुए कहा कि उक्त संस्थान ने 2,000 प्रश्नों का वह प्रश्न बैंक बेचा था जिसमें से अंतिम रूप से प्रश्नपत्र बनाया गया था. उनका तर्क है कि सीबीआइ जांच ही कुछ कर सकेगी क्योंकि इसमें संवेदनशील पदों पर काबिज प्रमुख कांग्रेस नेता शामिल हैं. भाजपा विधायक और पूर्व शिक्षा मंत्री वासुदेव देवनानी कहते हैं, ''बिना आग के धुआं नहीं उठता और रीट की आग में गहलोत सरकार को भारी नुक्सान हुआ है.''

जनवरी की 30 तारीख को मीणा ने विस्फोटक आरोपों की झड़ी लगाते हुए कहा था कि परीक्षा में धोखाधड़ी सुनिश्चित करने के लिए ही महत्वपूर्ण जिलों में आरजीएससी के नौ सदस्यों को रीट परीक्षाओं की 'निगरानी' की जिम्मेदारी निभाने के लिए चुना गया था. उदाहरण के लिए, उनका कहना है कि जयपुर में आरजीएससी सदस्य प्रदीप पराशर को चुना गया था, जबकि पराशर के पास कोई अन्य आधिकारिक पद नहीं था. एक शैक्षणिक संस्थान चलाने वाले राम कृपाल मीणा को मौखिक आदेश पर उप-समन्वयक के रूप में चुना गया था. जांच शुरू होने के बाद से ही पराशर और राम कृपाल दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. माना जाता है कि पराशर उस समूह का हिस्सा थे जो जयपुर में शिक्षा विभाग के स्ट्रांग रूम से विभिन्न जिलों में प्रश्नपत्रों के परिवहन का काम संभाल रहे थे. माना जा रहा है कि लीक हुआ प्रश्नपत्र उसी समय चोरी हो गया था. इस बात के भी सबूत हैं कि जब यह घटना हुई तो जरोली उस इमारत में मौजूद थे, हालांकि उन्होंने इससे इनकार किया है.

इन आरोपों के जवाब में डोटासरा ने कहा है कि एसओजी को अपनी जांच पूरी करने के लिए समय दिया जाना चाहिए. गर्ग का कहना है कि उन्हें निशाना बनाए जाने का कारण उनका तेजी से राजनैतिक उदय है. उन्होंने अपने ऊपर लग रहे आरोपों को वापस मीणा पर लगाने का प्रयास करते हुए सुझाव दिया कि एसओजी को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि क्या मीणा खुद भी इसी तरह के अपराधों में शामिल गिरोहों से संबंध रखते हैं. इधर, मुख्यमंत्री गहलोत ने रीट के घोषित परिणाम रद्द करने और परीक्षा पुनः आयोजित किए जाने की मांगों को मानने से यह कहते हुए इनकार किया है कि ऐसा करना ईमानदारी से सफल हुए योग्य लोगों के प्रति अनुचित होगा. राज्य सीबीआइ जांच का भी विरोध कर रहा है, शायद इस डर से कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार जांच का इस्तेमाल कांग्रेस के नेतृत्व वाली राजस्थान सरकार को शर्मिंदा करने के लिए करेगी.

लगता नहीं कि रीट घोटाले के नतीजों का असर जल्द ही दूर हो सकेगा. इसे अभी ही 2020 में पायलट के विद्रोह के समय की चुनौती के बराबर का संकट माना जा रहा है. संयोग से, पायलट खुद लंबे समय से गर्ग और डोटासरा दोनों का विरोध करते रहे हैं. लोगों का मानना था कि उनके कारण ही डोटासरा से मंत्री पद छिन गया था जबकि गर्ग को नवंबर में कैबिनेट विस्तार में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी नहीं मिली. उन्होंने हाल ही में रीट मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हुए मामले की पारदर्शी जांच और व्यवस्था में लोगों का विश्वास बहाल करने के लिए दोषियों को दंडित करने की बात कही है.

विपक्ष को उम्मीद है कि वर्तमान में रीट परिणामों को रद्द करने और घोटाले की सीबीआइ जांच का आदेश देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा राजस्थान उच्च न्यायालय अंततः सीबीआइ जांच का आदेश देने के लिए तैयार होगा. परिणाम जो भी हो, इस प्रकरण के कारण मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की आगे की राह पथरीली हो गई है. ■

प्रश्नपत्र चोरी की कीमत

5 करोड़ रु.
में प्रश्नपत्र बेचा गया चुराने के तत्काल बाद, ऐसा माना जाता है. इसके बाद आगे यह सैकड़ों अन्य लोगों को 15 लाख रुपए तक में बेचा गया

51
आवेदक प्रति पद का औसत था रीट 2021 की परीक्षा में. इसमें कुल 31,000 पदों के लिए 16 लाख उम्मीदवार थे

38
लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है अभी तक रीट घोटाले के सामने आने के बाद, इसकी जांच अभी जारी है

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा दांव

मोदी सरकार ने राहत पैकेज के बदले देश को तेज आर्थिक विकास की राह पर ले जाने की मंशा से इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए बटुआ खोला, मगर इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए योजनाओं को वाकई जमीन पर उतारना जरूरी

एम.जी. अरुण, श्वेता पुंज और अनिलेश एस. महाजन

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब 2022-23 के केंद्रीय बजट की तैयारी शुरू की, तो उनके सामने जबरदस्त चुनौतियां थीं. चुनौतियों की फेहरिस्त में सबसे ऊपर उन 5.3 करोड़ लोगों के लिए रोजगार जुटाने के तरीके और साधन खोजने थे, जिनकी रोजी-रोटी दिसंबर 2021 तक छिन गई थी. जैसा कि सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी (सीएमआइई) के आंकड़ों से जाहिर होता है. अधिकांश तबाही 2020-21 में हुई, जब महामारी की दो लहरों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया और आर्थिक वृद्धि को गर्त में डुबो दिया—ऐसी बुरी हालत इससे पहले 40 साल पहले आई थी. उससे हर कारोबार मटियामेट हो गया, एमएसएमई (लघु, छोटे और मझोले उद्यम) की तो रीढ़ ही टूट गई, जो बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया कराता है.

फोटोः चंद्रदीप कुमार

35% बढ़ोतरी पूंजीगत खर्च में, पिछले वित्त वर्ष के बजटीय खर्च के मुकाबले

खर्च की प्राथमिकताएं

मंत्रालय	बजट अनुमान 2021-2022	संशोधित अनुमान 2021-2022	बजट अनुमान 2022-2023
आवास और शहरी मामले मंत्रालय	28,821.99 25,759.01 54,581	47,893.76 25,956.5 73,850.26	49,208.45 27,341.01 76,549.46
बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग मंत्रालय	1,519.35 183 1,702.35	976.57 608.8 1,585.37	1,135.19 574.31 1,709.5
रेल मंत्रालय	2,954.64 1,07,100 1,10,054.64	2,956.12 1,17,100 1,20,056.12	3,267.13 1,37,100 1,40,367.13
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय	9,870.89 1,08,230.11 1,18,101	9,898.44 1,21,250.63 1,31,149.07	11,363.71 1,87,744 1,99,107.71
ऊर्जा मंत्रालय	13,757.03 1,564.97 15,322	14,236.38 1,085.62 15,322	16,061.63 13.11 16,074.74

● राजस्व खर्च ● पूंजीगत खर्च ● कुल (करोड़ रु. में)

स्रोतः वित्त मंत्रालय

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

उधर ईंधन और खाद्यन्न महंगाई ने अपना बदसूरत सिर उठा लिया, जिसकी एक वजह कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में तेज बढ़ोतरी है और लोगों के लिए मुसीबतें लेकर आया. अच्छी बात यह थी कि हाल में अर्थव्यवस्था में बहाली के संकेत दिखाई देने लगे, हालांकि ओमिक्रॉन से पैदा तीसरी लहर ने थोड़ी अड़चन पैदा की. मौजूदा वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में अर्थव्यवस्था 8.4 फीसद बढ़ी, लेकिन यह वृद्धि की क्षमता के जरा नजदीक नहीं थी.

सीतारमण ने तय किया कि वे खैरात बांटने के बजाए सार्वजनिक खर्च को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देकर आर्थिक गतिविधियों में जान डालेंगी. उन्होंने सरकार के पूंजीगत खर्च (कैपेक्स) में 35 फीसद की भारी बढ़ोतरी की, जिससे यह 2021-22 में 5.44 लाख करोड़ रुपए के बजटीय खर्च से 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया, जो जीडीपी का 2.9 फीसद बैठता है. इसमें राज्यों को एक लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्ज भी शामिल है, जो उन परियोजनाओं के लिए दिया जाएगा जो वे लेना चाहें. सीतारमण ने अधिकांश पूंजीगत खर्च उन क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के लिए रखा है, जिन्हें उन्होंने 'वृद्धि के सात इंजन' कहा है, सड़क, रेलवे, हवाई अड्डे, बंदरगाह, सार्वजनिक यातायात, जलमार्ग और लॉजिस्टिक्स. उन्होंने कहा, ''ये सातों इंजन मिली-जुली ताकत से अर्थव्यवस्था को आगे खींचेंगे.'' इन्हें ऊर्जा ट्रांसमिशन, आइटी संचार, पानी और सीवरेज, और सामाजिक बुनियादी

सीतारमण ने ज्यादातर पूंजीगत खर्च का फोकस 'वृद्धि के सात इंजनों' पर रखा है. जैसे सड़कें, रेलवे, हवाई अड्डे, सार्वजनिक परिवहन, जल परिवहन और लॉजिस्टिक

ढांचे से बल मिलेगा.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 फरवरी को कहा, ''बजट ज्यादा बुनियादी ढांचे, ज्यादा निवेश, ज्यादा वृद्धि और ज्यादा नौकरियों की संभावनाओं से भरपूर है.'' इन वर्षों के दौरान मोदी सरकार अर्थव्यवस्था को मंदी से निकालने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा करती रही है. बजट 2022-23 से पहले के चार वर्षों में भी इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए भारी प्रावधान किया गया—वित्त वर्ष 2020 में 3.36 लाख करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2021 में 4.39 लाख करोड़ रुपए, वित्त वर्ष 2022 में 5.54 लाख करोड़ रुपए और अब वित्त वर्ष 2023 में 7.5 लाख करोड़ रुपए. 2019 में सरकार ने 102 लाख करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी नेशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआइपी) योजना की शुरुआत की थी.

ऐसे समय जब आर्थिक वृद्धि के दो प्रमुख चालक—उपभोक्ता मांग और निजी निवेश—महामारी की वजह से काफी कमजोर पड़ गए हैं, केंद्र का लक्ष्य आपूर्ति पक्ष में जान डालकर अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की है. इससे, सीतारमण मानती हैं कि मध्य से लंबी अवधि में वृद्धि के लिए काफी अवसर पैदा होंगे. और फिर, उनके हिसाब से, ज्यादा नौकरियों और रोजगार की राह खुलेगी, जिससे उपभोक्ता खर्च और मांग में इजाफा हो सकता है. वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन ने *इंडिया टुडे* से कहा, ''बजट की व्यापक थीम वृद्धि बहाल करना और फायदेमंद रोजगार का सृजन करना है. हमारा मानना है कि रोजगार वृद्धि के जरिए पैदा होंगे, न कि खैरातों से. वृद्धि रोजगार की सबसे अच्छी जननी है और ऐसा करने के लिए हमने पूंजीगत खर्च में भारी बढ़ोतरी की है और यह मानी हुई बात है कि इसका अर्थव्यवस्था पर बहुगुणक प्रभाव होता है.'' इसीलिए उनका कहना है कि सरकार के पास मौजूद सीमित संसाधन इस दिशा में लगाए गए हैं.

वृद्धि के सात इंजन

सरकार के खर्च में इस भारी बढ़ोतरी को अंजाम देने के लिए केंद्र ने जिस साधन के इस्तेमाल का मनसूबा बनाया है, वह है 'पीएम गतिशक्ति', जो आर्थिक वृद्धि के लिए संपूर्ण कायापलट का नजरिया अपनाता है. आर्थिक कायापलट अबाध मल्टीमोडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक दक्षता के लिए पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के दायरे में सातों इंजन आएंगे. गतिशक्ति मास्टर प्लान के मुताबिक इसमें राज्य सरकारों द्वारा किया जा रहा इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास भी शामिल होगा.

मास्टर प्लान का केंद्र-बिंदु विश्वस्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचा और लोगों तथा वस्तुओं दोनों की आवाजाही के विभिन्न साधनों तथा परियोजना स्थलों को जोड़ना होगा. इन्फ्रास्ट्रक्चर विशेषज्ञ और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर सीआइआइ की नेशनल काउंसिल के चेयरमैन विनायक चटर्जी कहते हैं, ''मांग दबे होने की स्थिति में नीति निर्माताओं और अर्थशास्त्रियों के सामने दो विकल्प होते हैं. एक, लोगों के हाथ में पैसे देकर मांग को जिंदा किया जाए. दूसरा रास्ता बड़े पैमाने पर सार्वजनिक कामों से होकर जाता है. भारत ने बेशक सार्वजनिक निवेश के जरिए वृद्धि को बल देने का विकल्प चुना है.''

अर्थशास्त्रियों और उद्योगपतियों का कहना है कि पूंजीगत खर्च के प्रस्तावों में, जो ज्यादातर

''सार्वजनिक खर्च को हर हाल में अगुआई करनी जारी रखनी चाहिए और निजी निवेश तथा मांग को 2022-23 में बढ़ावा देना चाहिए''

निर्मला सीतारमण
केंद्रीय वित्त मंत्री

गेट्टी इमेजेज

6.9% जीडीपी का राजकोषीय घाटा मौजूदा वर्ष में, बजट अनुमान 6.8 फीसद के मुकाबले

859.5 करोड़ यात्रियों के लिए रेलवे की वित्त वर्ष 2022-23 में तैयारी

मनीष अग्निहोत्री

''मकसद यह है कि सिग्नल टेक्नोलॉजी का देश में विकास किया जाए और उसे निर्यात के लिए विश्वस्तरीय बनाया जाए, ताकि उन देशों को दिया जा सके, जो अच्छे रेलवे नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं''

अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय रेल, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स तथा आइटी मंत्री

बुनियादी ढांचे से जुड़े हैं, रोजगार की ज्यादा गुंजाइश और निजी खपत पर अत्यधिक बहुगुणक प्रभाव की क्षमता है. पीरामल ग्रुप के चेयरमैन अजय पीरामल कहते हैं, ''पूंजीगत खर्च से काफी निजी निवेश आने और आर्थिक वृद्धि को सहारा मिलने की संभावना है. कैपेक्स के हर एक करोड़ रुपए से आर्थिक उत्पादन 2.45 करोड़ रुपए बढ़ जाता है.'' यही नहीं, पीरामल यह भी कहते हैं कि आधुनिक इन्फ्रास्ट्रक्चर और मल्टीमोडल कनेक्टिविटी से माल ढुलाई और लोगों की आवाजाही में मदद मिलेगी, जो सभी कारोबार के लिए जरूरी है. ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के एमडी वरुण बेरी का कहना है कि कैपेक्स में बढ़ोतरी ''बड़े उद्योगों और एमएसएमई से सेवाओं और निर्मित इनपुट की मांग को उकसाएगी और बेहतर बुनियादी ढांचे के जरिए किसानों की मदद करेगी.''

कायापलट के सात इंजनों को सरकार किस तरह बढ़ावा देने का मनसूबा बना रही है? एक संक्षिप्त विश्लेषण—

वृद्धि का राजमार्ग

बुनियादी ढांचे में मोदी सरकार का ज्यादातर जोर राजमार्गों पर है. 2022-23 में केंद्र की योजना राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर विस्तार करने यानी इसे कुल 1,36,440 किलोमीटर के पांचवें हिस्से तक बढ़ाने की है. सार्वजनिक संसाधनों के अलावा 20,000 करोड़ की धनराशि 'वित्तपोषण के नए-नवेले' तरीकों से जुटाई जाएगी. अगले

मोदी सरकार के पूंजीगत खर्चों में ज्यादातर जोर राजमार्गों पर है. केंद्र 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को 25,000 किमी बढ़ाना चाहता है

वित्त वर्ष के लिए सड़क और राजमार्गों पर पूंजीगत खर्च 2021-22 के संशोधित अनुमान से केवल 0.8 फीसद ज्यादा है. क्रिसिल का एक विश्लेषण कहता है कि पूरे 1.88 लाख करोड़ रुपए सकल बजटीय सहायता से आएंगे, जो मौजूदा वित्त वर्ष से 55 फीसद ज्यादा है. सड़कों के लिए सरकार ने बाहरी बजटीय संसाधनों का प्रावधान नहीं किया है. क्रिसिल की डायरेक्टर ईशा चौधरी बताती हैं कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तेजी से बढ़ते कर्ज को देखते हुए सरकार सीधे धन खर्च करेगी. जहां सड़कें और राजमार्ग सफलता से पूरे हो चुके हैं, वहां दस फीसद धन संपत्तियों के मौद्रिकीकरण से आएगा.

निजी क्षेत्र को साथ लाना सरकार के लिए बड़ी चुनौती हो सकती है, तब भी जब वह सार्वजनिक खर्च पर जबरदस्त जोर देकर निजी निवेश में भी अच्छी बढ़ोतरी की उम्मीद कर रही है. केंद्र सरकार में सड़क परिवहन

“बजट का व्यापक थीम आर्थिक वृद्धि को बहाल करना और फायदेमंद रोजगार पैदा करना है”

टी.वी. सोमनाथन
केंद्रीय वित्त सचिव

रॉयटर्स

और राजमार्ग मंत्रालय के पूर्व सचिव विजय छिब्बर कहते हैं कि सरकार ने इन्फ्रास्ट्रक्चर निर्माण पर जोर देने का इरादा तो साफ कर दिया, लेकिन ‘‘हमें निजी क्षेत्र को आंखों से ओझल नहीं होने देना चाहिए. सरकार तो अपनी तरफ से बढ़-चढ़कर काम कर रही है, आवंटन करके अच्छा काम किया गया है. इतना ही विशेष प्रयास निजी क्षेत्र को लाने के लिए भी किया जाना चाहिए.’’ संसद में सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के एक लिखित उत्तर के अनुसार, नवंबर 2021 तक सड़क निर्माण में निजी क्षेत्र का निवेश 15,164.2 करोड़ रुपए था; 2020-21 में यह 12,475.5 करोड़ रुपए और 2019-20 में 21,926 करोड़ रुपए था.

मोदी सरकार पब्लिक-प्राइवेट भागीदारी के अलग-अलग मॉडल के साथ काम करती रही है और पीपीपी के तहत सड़क निर्माण के विभिन्न माध्यमों के आदर्श रियायत समझौतों की लगातार समीक्षा कर रही है. चिंता की एक बात यह है कि मौजूदा वित्त वर्ष के नौ महीनों में जब औसतन 6,000 किमी और पिछले वित्त वर्ष में 13,200 किमी राजमार्ग बने हों, तो 2022-23 में राजमार्गों का 25,000 किमी विस्तार ज्यादा ही महत्वाकांक्षी हो सकता है. हाइब्रिड एन्युइटी मॉडल परियोजनाओं में योग्यता का मानदंड कम करने और रियायत पाने वाले को काम के आधार पर भुगतान करने के बजाए मासिक भुगतान करने सरीखे उपायों से मदद मिली. क्रेडएवेन्यू के एक अध्ययन से पता चला कि 2024-25 तक पूरी की जाने वाली केवल 5 फीसद परियोजनाएं नवंबर 2020 तक पूरी हुई थीं. 2020-21 में पूरे भारत में 13,298 किमी राजमार्गों का निर्माण हुआ था.

तेज पटरी पर

वित्त वर्ष 2022-23 में जिस एक और बुनियादी ढांचे पर जोर होगा, वह है रेलवे, जो पिछले साले के मुकाबले करीब 2.5 गुना ज्यादा 895.5 करोड़ यात्रियों के अलावा 147.5 करोड़ टन माल ढोने के लिए कमर कस रही है. रेलवे ने 2022-23 के लिए 2.39 लाख करोड़ रुपए का राजस्व लक्ष्य तय किया है, जो 2021-22 के मुकाबले 18 फीसद ज्यादा है. सीतारमण ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की दो दुलारी योजनाओं के लिए भी प्रावधानों का ऐलान किया. उनमें से एक स्वदेश में ही विकसित सिग्नल प्रणाली ‘कवच’ है, जबकि दूसरी वंदे भारत ट्रेनों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ाना और अगले तीन साल में ऐसी 400 नए ट्रेन सेट शुरू करना है.

इस साल रेलवे को 1,40,367 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन मिला, जो पिछले

अवसर और उम्मीदें

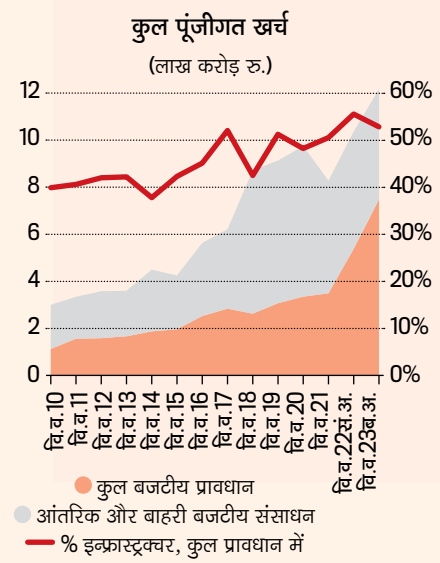

वि.व.: वित्त वर्ष; सं.अ.: संशोधित अनुमान; ब.अ.: बजट अनुमान

चंद्रदीप कुमार

कुल पूंजीगत खर्च और इन्फ्रास्ट्रक्चर खर्च दोनों में वित्त वर्ष 2021 में तेज बढ़ोतरी हुई है

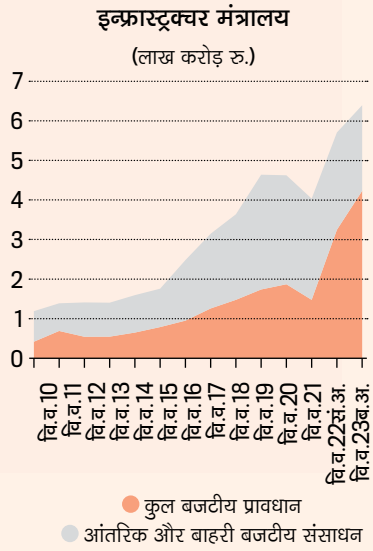

स्रोतः क्रिसिल

वित्त वर्ष 23 के लिए बजट में बड़ा जोर रेलवे पर भी है, जिसने अपना राजस्व लक्ष्य 2.39 लाख करोड़ रु. रखा है, जो 2021-22 की तुलना में 18 फीसद अधिक है

साल के 1,20,065 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से 16.9 फीसद ज्यादा है. रेलवे को इसके अलावा अतिरिक्त बजटीय सहायता, कर्ज और सार्वजनिक उपक्रमों की आय वगैरह से करीब एक लाख करोड़ रुपए मिलते हैं. यह सार्वजनिक ट्रांसपोर्टर आंतरिक साधनों से भी करीब 10,000 करोड़ रुपए जुटाता है. समर्पित माल गलियारे (डीएफसी) के लिए बजट में 15,710.44 करोड़ रुपए रखे गए हैं. परिचालन और रखरखाव के लिए रेलवे गलियारे की संपत्तियों का मौद्रिकीकरण भी करेगा. मगर जब तक निजी निवेश आए, वैष्णव पीएसयू से काम करवा रहे हैं और उनके लिए धन आवंटित करवाया है.

वैष्णव को उम्मीद है कि 400 ट्रेन सेट चलाने का लक्ष्य अगले तीन साल में पूरा कर लिया जाएगा. ये ट्रेन सेट यात्रियों को नया अनुभव देंगे, क्योंकि अन्य सुविधाओं के अलावा इनमें बंद गलियारे में सफर किया जा सकेगा, जिससे धूल-मुक्त वातावरण मिलेगा. ये ट्रेनें तेजी से रफ्तार पकड़ सकती और तेजी से रफ्तार कम कर सकती हैं, इसलिए यात्रा का समय और गंतव्य पर पहुंचने का कुल समय पारंपरिक ट्रेनों के मुकाबले कम होगा. कवच कार्यक्रम के तहत इस साल 2,000 किमी ट्रैक के सिग्नल अपग्रेड किए जाएंगे. वैष्णव कहते हैं, ''उद्देश्य यह है कि देश में ही टेक्नोलॉजी का विकास किया जाए और निर्यात के लिए इसे विश्वस्तरीय बनाया जाए. इसका निर्यात उन देशों को किया जाएगा जो पहले ही बहुत अच्छे रेल नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं.''

फोकस के अन्य क्षेत्र

शहरों में तेज रफ्तार सफर पक्का करने और सार्वजनिक यातायात सेवाओं को बढ़ावा देने की खातिर सीतारमण ने मेट्रो नेटवर्क बिछाने की गति तेज करने के लिए 19,130 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान किया है. पिछले साल इन परियोजनाओं पर 18,978 करोड़ रुपए खर्च किए गए. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के मेट्रो नेटवर्क के अलावा मेट्रो रेल लखनऊ, मुंबई, बेंगलूरू, कोच्चि, हैदराबाद और, बिल्कुल हाल ही में शुरू, कानुपर में चल रही हैं. इसके अलावा, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (आरआरटीएस) के जरिए बड़े शहरी केंद्रों को नजदीकी छोटे शहरों से जोड़ने के लिए भी बजट में प्रावधान किए गए हैं. ऐसा अपने किस्म का पहला नेटवर्क एनसीआर में बन रहा है, जिसका निर्माण 4,710 करोड़ रुपए की पूंजीगत लागत से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) कर रहा है. 82 किमी लंबे दिल्ली-गाजियाबद-मेरठ आरआरटीएस गलियारे का काम बीते एक साल में आगे बढ़ा है. इसमें दो डिपो और स्टेबलिंग यार्ड सहित 25 स्टेशन होंगे. एनसीआरटीसी ने गलियारे के 56 किमी का निर्माण शुरू कर दिया है.

हवाई अड्डे पीएम गतिशक्ति कार्यक्रम के स्तंभों में से एक हैं. नागरिक विमानन मंत्रालय के लिए 2022-23 के लिए बजट में 10,667

करोड़ रुपए रखे गए हैं, जबकि 600.7 करोड़ रुपए क्षेत्रीय कनेक्टिविटी की उसकी ध्वजवाहक योजना उड़ान के लिए हैं. 2021-22 में मंत्रालय को 3,224 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन एयर इंडिया के विनिवेश से उसका खर्च ऊंची छलांग लगाकर 72,652 करोड़ रुपए पर पहुंच गया. महामारी के दो साल बाद जब विमानन क्षेत्र परेशानियों से घिरा है, उम्मीद थी कि एटीएफ (एविएशन टर्बाइन फ्यूल) पर उत्पाद शुल्क में कटौती की जाएगी, लेकिन बजट ने इस क्षेत्र को कोई सीधी राहत देने से कन्नी काट ली. एयरलाइनों की परिचालन लागत का 25-40 फीसद एटीएफ में चला जाता है. आइसीआरए की रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ राज्य एटीएफ पर 25-30 फीसद वैट वसूलते हैं.

भारत का मात्रा के लिहाज से करीब 95 फीसद और मूल्य के लिहाज से 70 फीसद व्यापार समुद्री परिवहन के जरिए होता है. भारत में 12 बड़े और 205 छोटे तथा मध्यम बंदरगाह हैं. सागरमाला राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत छह नए बड़े बंदरगाह विकसित किए जाएंगे. भारत 7,517 किमी लंबी तटरेखा के साथ 16वां सबसे बड़ा समुद्री देश है. बंदरगाह और पोताश्रय निर्माण और रखरखाव के लिए सरकार ने उदार नियमों के तहत 100 फीसद तक एफडीआइ की इजाजत दी है. उसने बंदरगाहों, अंतर्देशीय जलमार्गों और अंतर्देशीय बंदरगाहों का विकास, रखरखाव और परिचालन करने वाले उद्यमों को 10 साल के कर अवकाश की छूट दी है. केंद्र ने बंदरगाहों, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के लिए 2022-23 के बजट में 16,074.74 करोड़ रुपए रखे हैं, जो 2021-22 के 15,322 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से ज्यादा हैं.

सीतारमण ने पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय

बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जोर इस वादे के साथ है कि पूरी अर्थव्यवस्था पर उसका बहुगुणक असर होगा. स्टील, सिमेंट और दूसरी निर्माण सामग्रियों की मांग बढ़ने से रोजगार में तेजी आएगी

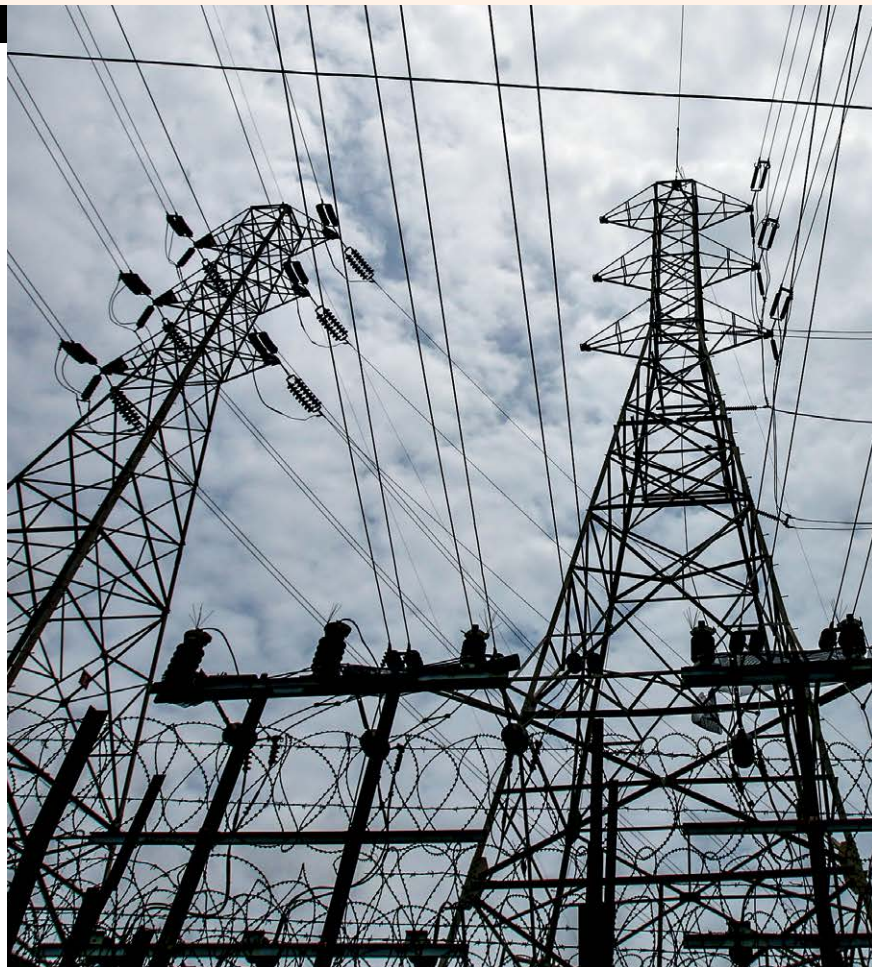

रॉयटर्स

बजट एक नजर में

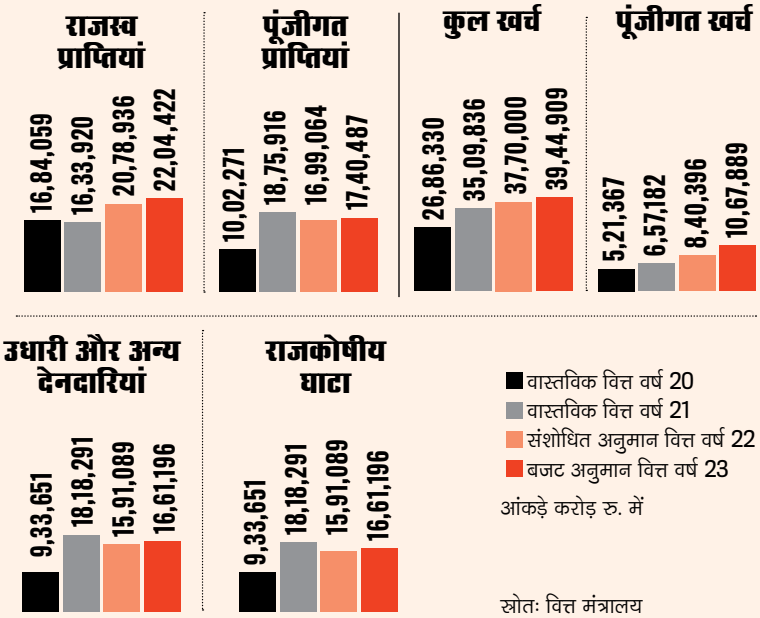

आंकड़े करोड़ रु. में

स्रोतः वित्त मंत्रालय

मास्टर प्लान को जमीन पर उतारने का काम तेज करने के लिए प्रावधान किए. वर्ल्ड बैंक के अनुमान के मुताबिक, भारत में औसत लॉजिटिक्स लागत जीडीपी की करीब 14-16 फीसद है, जबकि अमेरिका और जापान सरीखे विकसित देशों में यह 6-8 फीसद है.

अड़चनों पर नजर

बुनियादी ढांचे पर सरकार का जोर देना संभावनाओं से भरपूर है. बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए स्टील, सीमेंट और अन्य प्रमुख वस्तुओं की मांग बढ़ने की उम्मीद है, जिसके नतीजतन उत्पादन क्षमता का विस्तार होगा और नौकरियां का सृजन होगा. सरकार को अगले पांच साल में साठ लाख नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है. मगर बहुत कुछ इस पर निर्भर करेगा कि तमाम परियोजनाओं का काम निर्धारित समयसीमा के भीतर कैसे पूरा होता है. कई परियोजनाएं लाल फीते की भेंट चढ़ जाती हैं और जमीन अधिग्रहण में काफी देर होती है. सीतारमण ने बताया कि मोदी सरकार ने हाल के वर्षों में 25,000 से ज्यादा अनुपालन और 1,486 केंद्रीय कानून खत्म किए हैं, लेकिन कारोबारी सहूलत निवेशकों की बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है.

इस बीच सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में उपभोक्ताओं के हाथ में ज्यादा धन रखने के उपाय कर सकती है. गिरती ग्रामीण मांग के चलते दिसंबर की तिमाही में एफएमसीजी क्षेत्र मात्रा के लिहाज से साल-दर-साल 1.8 फीसद सिकुड़ा, जो पांच तिमाहियों में पहली गिरावट थी. जब कच्चे तेल की अंतरराष्ट्रीय कीमतें 90 डॉलर प्रति बैरल के आसपास हैं, ऊंची महंगाई के चलते मांग के और कमजोर पड़ने की आशंका है.

''बजट में कुछ चूकें साफ दिखाई देती हैं, जैसे मनरेगा, खाद्यान्न, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडियों के लिए कम प्रावधान और स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा कोविड टीकाकरण पर नाकाफी ध्यान देना. बजट में अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश थी, जिसका सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया''

डी.के. श्रीवास्तव
चीफ पॉलिसी एडवाइजर, ईवाइ इंडिया

बजट पर नजर रखने वाले उम्मीद कर रहे थे कि सरकार शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसा कुछ लेकर आएगी. ऐसा हुआ नहीं. ईवाइ इंडिया के चीफ पॉलिसी एडवाइजर डी.के. श्रीवास्तव कहते हैं, ''बजट में कुछ चूकें साफ दिखाई देती हैं, जैसे मनरेगा, खाद्यान्न, उर्वरक और पेट्रोलियम सब्सिडियों के लिए कम प्रावधान और स्वास्थ्य इन्फ्रास्ट्रक्चर तथा कोविड टीकाकरण पर नाकाफी ध्यान देना.'' अलबत्ता वे यह भी कहते हैं कि बजट में अतिरिक्त राजकोषीय गुंजाइश थी, जिसका सरकार ने इस्तेमाल नहीं किया. अगर वह ऐसा करती, तो उपयुक्त अनुपूरक बजटों के जरिए या राजकोषीय मजबूती की रफ्तार तेज करके साल के दौरान कम प्रावधानों की भरपाई कर सकती थी.

आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार का इरादा अपने बटुए के फीते तुरंत कसने के बारे में सोचे बगैर खर्च करते रहने का है, पर ऐसा वह धीरे-धीरे एक अवधि में करेगी. मौजूदा साल में संशोधित राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.9 फीसद रहने का अनुमान है, जबकि इसका बजट अनुमान 6.8 फीसद था. 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 6.4 फीसद रहने का अनुमान है. इसके बारे में सीतारमण ने कहा कि यह राजकोषीय मजबूती के उस व्यापक रास्ते या 'राजकोषीय उड़ान पथ' के अनुरूप है, जिसकी घोषणा उन्होंने राजकोषीय घाटे को 2025-26 तक 4.5 फीसद के स्तर से नीचे लाने के लिए पिछले साल की थी. सीतारमण ने कहा कि बजट अर्थव्यवस्था के लिए अगले 25 साल का विजन सामने रखता है. इस अवधि को उन्होंने ''अमृत काल'' कहा, जो भारत की स्वतंत्रता के 100 वर्ष की तरफ ले जाती है. कई विशेषज्ञ कहते हैं कि बुनियादी ढांचे की योजनाओं की सफलता की कुंजी उन्हें जमीन पर उतारने में है.

लेखा महानियंत्रक (सीजीए) के आंकड़े बताते हैं कि 30 फीसद 2021-22 के पहले आठ महीनों में (नवंबर 2021 तक के ही आंकड़े मौजूद हैं) खर्च नहीं की जा सकी. सीजीए के अनुसार, नवंबर तक सरकार का कुल खर्च 2021-22 के बजट में तय 34.8 लाख करोड़ रुपए के मुकाबले 20.7 लाख करोड़ रुपए था. सोमनाथन कहते हैं, ''रकम उपलब्ध करवाना एक बात है और परियोजनाओं को पूरा करवाना दूसरी. जमीन पर अभी काम होने हैं—निविदाओं पर काम सौंपना है, अनुमतियां हासिल करनी हैं. आर्थिक मामलों के विभाग ने पिछले साल कैपेक्स की गहन निगरानी की और इस साल भी वह ऐसा करेगा.'' ज्यादा तेजी से अमल इसलिए भी जरूरी है ताकि नतीजे भारत को ज्यादा तेज वृद्धि की राह पर ले जा सकें. तभी ज्यादा नौकरियों से सृजन और लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के व्यापक लक्ष्य भी जल्द से जल्द साकार किए जा सकेंगे. ■

लेकिन खर्च भी तो हो...

पूंजीगत व्यय मद में तो 35 फीसद की बढ़ोतरी की गई है लेकिन असल खर्च आवंटित रकम के मुकाबले काफी कम रहना चिंता का बड़ा सबब

एम. जी. अरुण

स 1 फरवरी को केंद्रीय बजट पेश करते वक्त वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के करदाताओं के प्रति आभार जताया और उनके बारे में कहा, ''खुलकर योगदान दिया और सरकार के हाथ मजबूत किए.'' सीतारमण ने कुछ भारी-भरकम घोषणाएं भी कीं, जिसमें अगले वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत खर्च के प्रावधान को 35 फीसद बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ रुपए करना शामिल है. हालांकि करदाताओं और विशेषज्ञों के लिए अमल में हीला-हवाली सबसे ज्यादा चिंता का विषय है, जिससे हर साल बजट की घोषणाओं और वास्तविक खर्च में चौड़ी खाई दिखती है. इसकी वजह केंद्र और राज्य सरकारों की बेहद सुस्त नौकरशाही और फंड जारी करने की अजीबोगरीब प्रक्रिया है, जिससे काफी देर हो जाती है.

कोविड महामारी ने हालात और बदतर कर दिए, जैसा कि मौजूदा वित्त वर्ष से जाहिर है. लिहाजा, केंद्र और राज्य दोनों स्तर पर सरकारी खर्च में फर्क काफी बढ़ गया. महालेखा नियंत्रक (सीजीए) के आंकड़ों से पता चलता है कि वित्त वर्ष 2021-22 के आठ महीनों (सिर्फ नवंबर तक के आंकड़े उपलब्ध) में केंद्र में खर्च के लिए तय रकम 40 फीसद खर्च नहीं हुई थी. सीजीए के मुताबिक, केंद्र सरकार का नवंबर तक कुल खर्च 20.7 लाख करोड़ रु. था, जबकि 2021-22 के बजट में 34.8 लाख करोड़ रु. का प्रावधान था. इसका मतलब है कि तय रकम का सिर्फ 59.6 फीसद ही खर्च किया जा सका.

धीमा खर्च

सरकार का 2021-22 का तय पूंजीगत खर्च 5.54 लाख करोड़ रु. है, लेकिन नवंबर तक सिर्फ 49 फीसद (2.73 लाख करोड़ रु.) हो पाया. पूंजीगत खर्च वह है जो कि सरकार मशीनरी, उपकरण, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं वगैरह के विकास के साथ जमीन जैसी स्थाई संपत्तियां खरीदने पर करती है. विभिन्न मंत्रालय शायद वित्त वर्ष के अंत में अपने पूंजीगत खर्च में इजाफा करें.

राष्ट्रीय इन्फ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन (एनआइपी) के लिए 44,700 करोड़ रु. का प्रावधान किया गया था, जिसे सीधे आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) को ही खर्च करना था. डीईए का वित्त वर्ष के लिए कुल पूंजी प्रावधान 56,500 करोड़ रु. है. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, नवंबर तक सिर्फ 2 फीसद या 1,150 करोड़ रु. ही खर्च हो पाए थे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने अपने विभाग के प्रावधान 20,100 करोड़ रु. में से सिर्फ 5,100 करोड़ रु. ही खर्च किया.

इन्फ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी फर्म फीडबैक वेंचर्स के चेयरमैन विनायक चटर्जी का अनुमान है कि सरकार के तय किए पूंजीगत खर्च का करीब 55 फीसद ही खर्च हो पाया है. चटर्जी कहते हैं, ''वित्त वर्ष के इस वक्त तक तो खर्च करीब 66 फीसद हो जाना चाहिए.'' इस वर्ष दो दिक्कतें आईं. कोविड की दूसरी लहर की वजह से अप्रैल-जून में प्रोजेक्ट रुके रहे और फिर इधर ओमिक्रॉन वेरिएंट से तीसरी लहर आ गई. *इंडिया टुडे* से बातचीत में चटर्जी बताते हैं, ''खर्च में कमी की वजह कोविड महामारी हो सकती है. कितने ही कामगार बीमार पड़ गए, जिससे परियोजनाओं पर अमल में देरी हुई.'' सीजीए के आंकड़ों से पता चलता है कि महामारी के पहले के वर्ष 2019-20 में ज्यादातर मंत्रालयों ने अपने संशोधित खर्च अनुमान के मुकाबले खर्च का अपना लक्ष्य (90 फीसद और ज्यादा) पूरा कर लिया था. वित्त वर्ष 2021-22 के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के लिए 73,931.8 करोड़ रु. खर्च का प्रावधान था. उसमें से नवंबर तक 47,006 करोड़ रु. (करीब 64 फीसद) खर्च हुए. अप्रैल 2021 तक स्वास्थ्य पर कुल सरकारी खर्च में राज्यों की हिस्सेदारी 69 फीसद थी. राज्य स्तर पर केंद्रीय योजनाओं पर अमल

40% रकम उस बजट की नवंबर 2021 तक बची रह गई थी जिसे केंद्र ने वित्त वर्ष 2021-22 में दिया था

70% लक्ष्य, राजस्व जुटाने का (19.7 लाख करोड़ रु. में से 13.7 लाख करोड़ रु.) सरकार ने हासिल कर लिया

राज्य हुए बेपरवाह

पूंजीगत व्यय और कर्ज उठाने के आंकड़े बताते हैं कि राज्य अपने यहां विभिन्न परियोजनाओं को गति दे पाने में नाकाम रहे हैं

राजकोषीय घाटा

राज्यों का सकल राजकोषीय घाटा संशोधित अनुमान से कहीं नीचे है, जो खर्च में ढिलाई को साफ जाहिर करता है

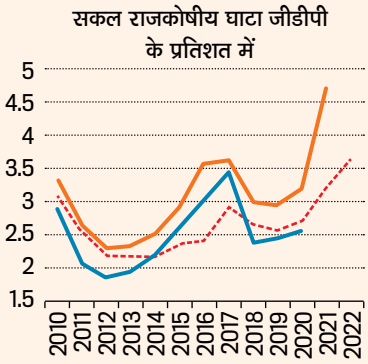

पूंजीगत खर्च

राज्यों का पूंजीगत खर्च बजट में निर्धारित और संशोधित दोनों ही अनुमानों से कहीं नीचे रहा है

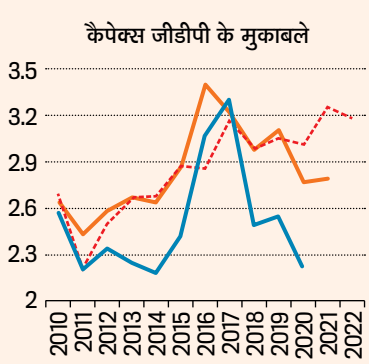

बजट में तय — संशोधित — असल खर्च (आंकड़े प्रतिशत में)

इलस्ट्रेशनः तन्मय चक्रवर्ती

उधारी बेमन की

राज्य मार्च 2021 के बाद से बाजार से उधारी उठाने का अपना लक्ष्य पूरा करने में नाकाम रहे हैं. इससे उनके घटते खर्च का अंदाजा मिलता है

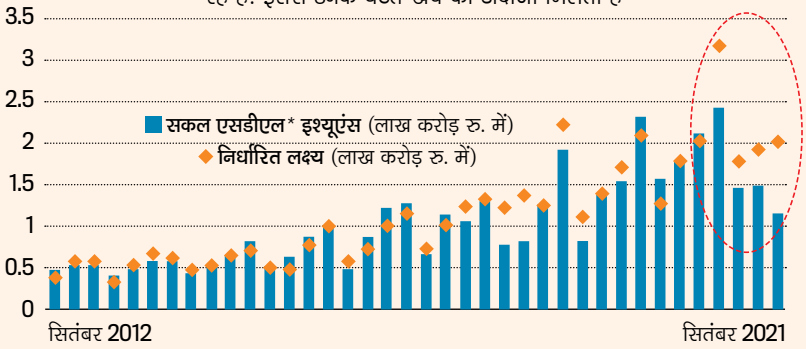

* एसडीएलः स्टेट डेवलपमेंट लोन्स/राज्य विकास कर्ज

स्रोतः आरबीआइ, क्रेडिट सुइस अनुमान

के लिए केंद्र प्रमुख रूप से वित्त आयोग और विभागीय प्रावधानों के जरिए रकम देता है. नई दिल्ली स्थित गैर-मुनाफा हेल्थ ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म (एचएसटीपी) के एक अध्ययन के मुताबिक, स्वास्थ्य के मोर्चे पर कम खर्च की मुख्य वजहें कमजोर स्वास्थ्य व्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र में कर्मियों की कमी, सरकारी मसले और खरीद तथा निर्माण की पेचीदा प्रक्रिया है.

दूसरी वजह केंद्र से हासिल रकम को राज्यों में जिला स्तर तक पहुंचने में लगने वाली देरी है. एचएसटीपी की सुधा चंद्रशेखर और भुवनेश्वर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ की सरित के. राउत के अप्रैल 2021 के अध्ययन के मुताबिक, ''देरी सरकारी खजाने से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मुख्यालय और फिर वहां से

महामारी ने हमें यह बात अच्छी तरह से समझा दी है कि राहत पहुंचाने और नए रोजगार दे पाने में सक्षम परियोजनाओं को सिरे चढ़ाने के लिए सरकारी मशीनरी का बेहतर ढंग से इस्तेमाल कितना जरूरी है

जिला स्वास्थ्य संस्थाओं तक रकम पहुंचने की प्रक्रिया में लगती है, जिनके कई बैंक खाते होते हैं. इससे पारदर्शिता भंग होती है और निगरानी काफी पेचीदा हो जाती है.''

जल शक्ति मंत्रालय नवंबर तक वित्त वर्ष के लिए तय राशि का सिर्फ 34 फीसद ही खर्च कर पाया था; वह पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 44 फीसद खर्च कर चुका था. हालांकि मंत्रालय जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक सभी ग्रामीण घरों तक पीने का पानी पहुंचाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य का पीछा कर रहा है. अनुमानित 18.7 करोड़ ग्रामीण घरों में से अगस्त 2021 तक सिर्फ 17 फीसद तक ही किसी तरह नल जल पहुंच पाया है. जल जीवन मंत्रालय के लिए प्रावधान अनुमानित 3.6 लाख करोड़ रु. है, जिसमें से 2.08 लाख करोड़ रु. केंद्र की हिस्सेदारी का है. चटर्जी की राय है कि तमाम अड़चनों के बावजूद जल जीवन मिशन ने सराहनीय प्रगति की है.

लेकिन इसके क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए चटर्जी निगमों, ट्रस्टों और देसी-विदेशी फाउंडेशनों को जोड़ने की वकालत करते हैं, जो कुछ गांवों को अपनाकर इसमें हिस्सेदारी करने की ख्वाहिश रखते हैं. चटर्जी कहते हैं, ''स्थानीय जल सुविधाओं के लिए पानी समितियों के गठन का विस्तार बिजली, सार्वजनिक स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किया जाना चाहिए.'' इस बीच, कृषि मंत्रालय 2021-22 के बजट प्रावधान का नवंबर तक सिर्फ आधी रकम ही खर्च कर पाया था, जबकि आयुष मंत्रालय 51 फीसद, कोयला मंत्रालय 60 फीसद और संचार तथा शिक्षा मंत्रालय क्रमश: 53 और 48 फीसद रकम ही खर्च कर पाए थे.

राजस्व के मामले में सरकार नवंबर तक वित्त वर्ष के लिए निर्धारित राजस्व का करीब 70 फीसद (कुल 19.7 लाख करोड़ रु. में से 13.7 लाख करोड़ रु.) हासिल कर चुकी थी. कुल निर्धारित 15.4 लाख करोड़ रु. के कर राजस्व में उसे 11.3 लाख करोड़ रु. हासिल हो चुके थे. नवंबर में केंद्र ने 95,082 लाख करोड़ रु. राज्यों को कर खाते में उनकी हिस्सेदारी के मद में ट्रांसफर किए. यह कर संग्रह में इजाफे की वजह से हुआ. यह बजट अनुमान के मुताबिक दोबारा मासिक हस्तांतरण था. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा हिस्सा (17,057 करोड़ रु.) मिला. उसके बाद बिहार (9,563 करोड़ रु.), मध्य प्रदेश (7,464 करोड़ रु.), पश्चिम बंगाल (7,153 करोड़ रु.) और महाराष्ट्र (6,006 करोड़ रु.) का नंबर था. राज्यों को कर हस्तांतरण साल में 14 किस्तों में होता है और संशोधित अनुमान के हिसाब से भरपाई अमूमन मार्च में की जाती है. पर सवाल है कि राज्य कितने कारगर ढंग से रकम का इस्तेमाल कर रहे हैं?

ऊंघते-उनींदे राज्य

केंद्र की योजना और फंड से बड़ी परियोजनाओं पर राज्य अमल करते हैं. 2022-23 में अर्थव्यवस्था में कुल निवेश के इजाफे के लिए केंद्र राज्यों को एक लाख करोड़ रु. देगा. यह 50 साल के लिए ब्याज मुक्त कर्ज राज्यों की सामान्य कर्ज उठान से अलग होगा. कई केंद्रीय योजनाएं तय समय से पीछे चल रही हैं. जानकारों का कहना है कि ज्यादातर समस्या राज्यों के स्तर पर है. भारतीय रिजर्व बैंक के नवंबर में जारी राज्य बजट सार-संक्षेप से पता चलता है कि कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में राज्य काफी पिछड़ रहे हैं और उसकी वजह से बजट में खर्च के प्रावधान और वास्तविक खर्च में बड़ा अंतर है. बजट में खर्च का प्रावधान पूरे साल का होता है, जबकि संशोधित अनुमान वित्त वर्ष के नौ महीने के आंकड़ों के आधार पर आकलन होता है. ये आकलन अक्सर बजट में खर्च के प्रावधान से ज्यादा होते हैं.

हालांकि, वास्तविक खर्च आखिरकार जब पेश किया जाता है तो उसमें भारी कमी दिखती है. इसका अंदाजा राज्य के बजटीय घाटे में कमी से भी लगाया जा सकता है. घाटा तब होता है जब सरकारी खर्च करों और दूसरे स्रोतों से जुटाए राजस्व से ज्यादा हो जाता है. ज्यादा बजटीय घाटे का मतलब है कि सरकार ने उधारी या कर्ज उठाकर अपने राजस्व से ज्यादा खर्च कर डाला है. हालांकि कम बजटीय घाटा चिंता का विषय है क्योंकि उससे सरकारी खर्च में

आखिर लागू कैसे हों

केंद्रीय मंत्रालय भी तयशुदा लक्ष्य तक खर्च नहीं कर पाए **2021-22** में

मंत्रालय	वित्त वर्ष 2021-22		% असल खर्च की तुलना	
	बजट अनुमान	खर्च (नवंबर 2021 तक)	मौजूदा वित्त वर्ष	पिछला वित्त वर्ष
कृषि और किसान कल्याण	1,31,531.19	66,409.12	**50%**	52%
आयुष	2,970.3	1,524.06	**51%**	58%
कोयला	534.88	323.41	**60%**	38%
संचार	75,265.22	40,040.16	**53%**	61%
प्रतिरक्षा	4,78,195.62	3,17,438.28	**66%**	63%
शिक्षा	93,224.31	44,285.23	**48%**	41%
इलेक्ट्रॉनिक्स और आइटी	9,720.66	3,294.94	**34%**	40%
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन	2,869.93	954.78	**33%**	44%
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	73,931.77	47,006.01	**64%**	74%
जलशक्ति	69,053.02	23,751.66	**34%**	44%
एमएसएमई	15,699.65	9,874.43	**63%**	31%
ऊर्जा	15,322	6,056.47	**40%**	35%
सड़क परिवहन और राजमार्ग	1,18,101	80,567.68	**68%**	65%
कपड़ा	3,631.64	1,747.8	**48%**	45%
पर्यटन	2,026.77	268.51	**13%**	33%

आंकड़े करोड़ रुपए में; स्रोत: कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स

''आवंटन और असल खर्च में भारी फासले के लिए कोविड से उपजे अड़ंगों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है. श्रमिक और कर्मचारी बड़े पैमाने पर बीमार पड़ गए. इस वजह से परियोजनाओं के काम में देरी हुई''

विनायक चटर्जी
चेयरमैन, फीडबैक वेंचर्स

कमी का पता चलता है. आरबीआइ का डेटा बताता है कि 2021-22 में जीडीपी के 3.6 फीसद पर राज्यों का बजटीय घाटा 2020-21 के संशोधित अनुमान 4.7 फीसद से 1.1 फीसद कम था. एशिया पैसिफिक स्ट्रैटजी और इंडिया इक्विटी स्ट्रैटजी फॉर क्रेडिट सुइस के सह-प्रमुख नीलकंठ मिश्र कहते हैं, ''अंतिम घाटा हमेशा संशोधित अनुमान से नीचे रहता है और अक्सर बजट के अनुमान से भी कम रहता है. बजटीय घाटे से कम घाटा ज्यादातर खर्च न कर पाने की वजह से होता है, जो लॉकडाउन की वजह से काफी प्रभावित हुआ है.''

आरबीआइ के डेटा में बजटीय घाटे के राज्यवार आंकड़ों के अभाव में यह पता लगाना मुश्किल है कि कौन-से राज्य ज्यादा फिसले हैं. राज्यों ने कितना कम खर्च किया, इसका अंदाजा सरकार के पास मौजूद बची नकदी से भी लगता है. राज्य सरकारें आरबीआइ से लेनदेन नहीं कर सकतीं, लेकिन वे अधिशेष रकम से केंद्र के जीरो कूपन बॉन्ड खरीद सकती हैं. केंद्र इस रकम को आरबीआइ में रखता है. मिश्र के मुताबिक, आंकड़ों से पता चलता है कि 2020-21 के आखिर में केंद्र ने 2.7 लाख करोड़ रु. आरबीआइ में जमा कर रखा है, मतलब राज्यों का घाटा जीडीपी के 3 फीसद के आसपास है.

मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में राज्यों ने लक्ष्य से 80,000 करोड़ रु. कम उधार उठाए और बची हुई रकम 20,000 करोड़ रु. आसपास पहुंच गई. मिश्र कहते हैं, ''2021-22 में भी घाटा जीडीपी के 3 फीसद के आसपास हो सकता है और उधारी बजट अनुमान से एक लाख करोड़ रु. कम हो सकती है.''

तेलंगाना के पूर्व मुख्य सचिव एस.के. जोशी क्रियान्वयन में देरी के लिए कई वजहों की ओर इशारा करते हैं, और ये वजहें एक से दूसरे प्रोजक्ट में अलग-अलग होती हैं. वे कहते हैं, ''एक तो बजट में खर्च तय होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के बीच संवाद का अभाव है. दूसरे, दिल्ली और राज्यों में चीजों के आगे बढ़ने की गति काफी अलग होती है, अमूमन यह प्रभारी व्यक्ति पर निर्भर होता है. योजना के स्तर पर आंके गए मूल्य से कीमतों में बढ़ोतरी और राज्यों की हिस्सेदारी, चाहे वह जितनी हो, देने में अक्षमता भी परियोजनाओं के लटकने और केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में देरी की वजहें होती हैं.'' इसके अलावा, प्रोजेक्ट या परियोजना की प्रकृति को लेकर राज्य विशेष मसले होते हैं, जिन पर योजना के स्तर पर बात नहीं होती है.

अनिंदितो मुखर्जी/गेट्टी इमेजेज

सुस्त रफ्तार पहले से ही विलंबित चल रहे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की गुजरात में धोलेड़ा साइट में काम में लगे कर्मचारी

खामियां और सबक

नाम न छापने की शर्त पर मुंबई स्थित एक अर्थशास्त्री का कहना है कि राज्य सरकारें हमेशा संशोधित बजट अनुमान ऊंचा रखती हैं, ताकि लक्ष्य से कम काम हो. यह बात कोविड के पहले के वर्षों में भी सही थी. उनकी दलील है कि सरकारें खर्च न करने का बहाना कोविड को नहीं बना सकतीं. ''सरकारों को निजी कंपनियों जैसा रवैया अपनाना चाहिए और आश्वस्त करना चाहिए कि कोई बड़ी रुकावट न हो. सरकारें अमूमन आपदा से बहाली की तैयारी रखती हैं. लेकिन महामारी ने मानो उनकी पोल खोल दी. जब करदाताओं के पैसे को सही ढंग से खर्च करने की बात आती है तो वे पकड़ी जाती हैं.''

''बजट में खर्च का प्रावधान हो जाने के बाद केंद्र और राज्यों के अफसरों के बीच संवाद का नितांत अभाव देखा गया है. और दोनों के ही छोर पर काम की गति में काफी फर्क है''

एस.के. जोशी
पूर्व मुख्य सचिव, तेलंगाना

दूसरे लोग सरकार से वित्त वर्ष के अंत तक लक्ष्य हासिल करने की उम्मीद करते हैं. बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस का कहना है कि केंद्र के खर्च में कमी उपभोक्ता मामलों, खाद और ईंधन के क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है, जहां सब्सिडी दी जाती है. मसलन, सरकार के मुफ्त खाद्यान्न कार्यक्रम के लिए 2021-22 के मद में 98,000 करोड़ रु. का प्रावधान था. वे कहते हैं, ''अनाज पहले ही एफसीआइ को दिया जा चुका हो सकता है, पर हिसाब-किताब वित्त वर्ष के अंत में लगाया गया हो सकता है. जब तक पूंजीगत खर्च से समझौता नहीं किया जाता, वृद्धि पर असर नहीं पड़ता.''

हालांकि खर्च के मोर्चे पर कमियां तो पहले के वर्षों में भी हुई हैं, लेकिन महामारी ने इस जरूरत पर जोर डाला है कि राहत और ऐसी परियोजनाओं के लिए सरकारी मशीनरी के कारगर इस्तेमाल की दरकार है, जिससे बड़े पैमाने पर रोजगार पैदा हो. आरबीआइ के डेटा के मुताबिक, ऐसा 2021-22 में होता नहीं लगा. केंद्र और राज्य सरकारों दोनों को महामारी से कुछ कड़े सबक सीखना चाहिए. वे योजनाओं पर अमल कारगर ढंग से करें, अगर खर्च का लक्ष्य हासिल करने और लोगों को लाभ पहुंचाने का इरादा हो.

—साथ में **अमरनाथ के. मेनन**

गरीबों की थाली खाली

केंद्र सरकार के कल्याणकारी योजनाओं पर भारी-भरकम खर्च के बावजूद महामारी के वर्षों में गरीबी हटाने के मोर्चे पर भारत का प्रदर्शन कमजोर रहा. बजट भी कम ही उम्मीद बंधाता है

कौशिक डेका

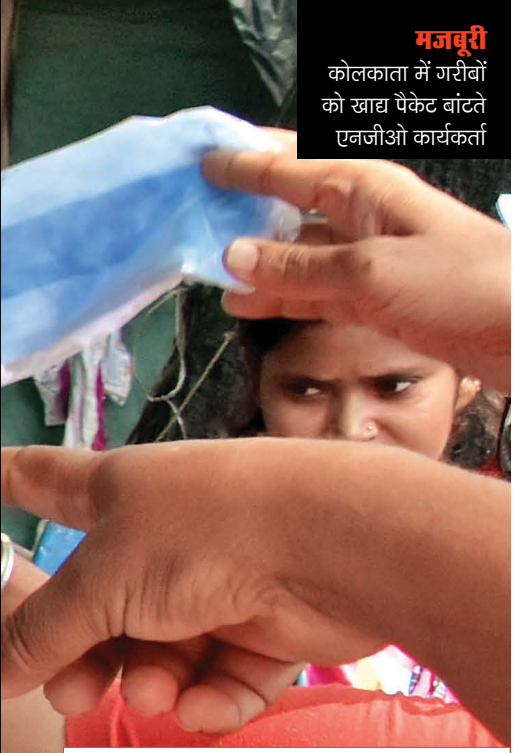

मजबूरी
कोलकाता में गरीबों को खाद्य पैकेट बांटते एनजीओ कार्यकर्ता

एएफआइ

असमानता की हद

142 अरबपति थे 2021 में भारत में जबकि 2020 में यह संख्या 102 थी

84% भारतीयों की आय में महामारी के आने के समय गिरावट आई

स्रोत: ऑक्सफेम इंडिया रिपोर्ट,2022, फोर्ब्स

अस्वस्थ विभाजन

साल 2021 में प्रकाशित नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआइ) के अनुसार, स्वास्थ्य और शिक्षा में खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों की गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) की आबादी में भी हिस्सेदारी ज्यादा रहती है. खराब प्रदर्शन करने वाले और शीर्ष पर काबिज राज्यों के बीच की खाई बढ़ती जा रही है

भारत के सबसे गरीब बड़े राज्य

1. बिहार **51.9**
2. झारखंड **42.4**
3. उत्तर प्रदेश **37.8**
4. मध्य प्रदेश **36.6**
5. असम **32.7**

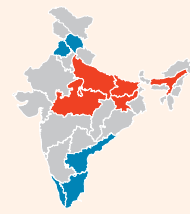

भारत के सबसे कम गरीब बड़े राज्य

1. केरल **0.7**
2. तमिलनाडु **4.9**
3. पंजाब **5.6**
4. हिमाचल प्रदेश **7.6**
5. आंध्र प्रदेश **12.3**

*% आबादी का जो बहुआयामी रूप से गरीब है **

**एमपीआइ स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के अतिव्यापी अभावों को पकड़ता है और इन्हें आय की गरीबी के मापकों से जोड़ता है क्योंकि ये अभावों को सीधे मापता और उनकी तुलना करता है*

हेल्थकेयर में शीर्ष 5 बड़े राज्य

1. केरल
2. तमिलनाडु
3. तेलंगाना
4. आंध्र प्रदेश
5. महाराष्ट्र

हेल्थकेयर में अंतिम 5 बड़े राज्य

19. उत्तर प्रदेश
18. बिहार
17. मध्य प्रदेश
16. राजस्थान
15. उत्तराखंड

स्रोत : नीति आयोग का हेल्थकेयर इंडेक्स 2021

स्कूली शिक्षा से सर्वाधिक वंचित पांच बड़े राज्य

**स्कूली शिक्षा से वंचित आबादी का प्रतिशत*

1. बिहार **26.7***
2. झारखंड **18.32**
3. उत्तर प्रदेश **17.52**
4. राजस्थान **17.1**
5. आंध्र प्रदेश **16.9**

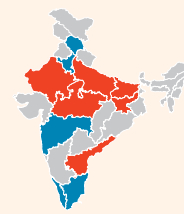

स्कूली शिक्षा से सबसे कम वंचित पांच बड़े राज्य

1. केरल **1.78**
2. हिमाचल प्रदेश **3.78**
3. महाराष्ट्र **6.54**
4. तमिलनाडु **6.61**
5. हरियाणा **7.1**

परिभाषा : एक परिवार के 10 साल से बड़े किसी भी सदस्य ने अगर छह साल तक अगर स्कूली शिक्षा हासिल नहीं की है तो उसे 'वंचित' माना जाएगा

स्रोत : नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2021

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

पिछले साल नवंबर में स्टैंडअप कॉमेडियन वीर दास ने यह कहकर तहलका मचा दिया था कि साफ-साफ दो भारत हैं. भले ही दो भारत का विचार बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन आर्थिक विषमताएं स्पष्ट रूप से ऐसे हालात पैदा कर रही हैं, जो उसी नजरिए का इजहार करता है. इसे आंकड़ों में देखें. जनवरी में समानता पर जारी ऑक्सफेम इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे अमीर 98 भारतीयों के पास उतनी ही संपत्ति (657 डॉलर या 49.15 लाख करोड़ रुपए) है, जितनी करीब 55.5 करोड़ गरीब लोगों के पास है. अर्थशास्त्री तथा वर्ल्ड इनइक्वेलिटी लैब के सह-निदेशक लुकाच चांसेल की अर्थशास्त्रियों टॉमस पिकेटी, इमैनुअल साएज और गैब्रिएल जुकमैन के साथ लिखी गई विश्व विषमता रिपोर्ट 2022 में बताया गया है कि भारत ''दौलतमंद एलीट वर्ग के साथ गरीब और बेहद गैर-बराबरी वाले देश'' के तौर पर सबसे अलग दिखता है, जहां चोटी के 10 फीसद के पास कुल राष्ट्रीय आमदनी का 57 फीसद है वहीं निचले 50 फीसद की हिस्सेदारी सिर्फ 13 फीसद है. इस रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में एक वयस्क आदमी की औसत सालाना राष्ट्रीय आय 2021 में 2,04,200 रु. है

लेकिन निचले पायदान के 50 फीसद की आमदनी सिर्फ 53,610 रुपए है, जबकि चोटी के 10 फीसद की आमदनी 20 गुना ज्यादा (11,66,520 रुपए) है. कोविड महामारी के दौरान यह खाई बेहिसाब बढ़ी है. महामारी की शुरुआत से ही भारत के करीब 84 फीसद परिवारों की आमदनी में गिरावट आई है. थिंक टैंक प्राइस (पीपुल्स रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी) ने खुलासा किया कि 2020-21 में भारत में 20 फीसद सबसे गरीब परिवारों की सालाना आमदनी करीब 53 फीसद घटी है. इसके मुकाबले, चोटी के 20 फीसद परिवारों की आमदनी में इसी अवधि के दौरान करीब 39 फीसदी की वृद्धि हुई.

इसलिए 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट पेश किया तो चुनौती सिर्फ महामारी की चोट खाई अर्थव्यवस्था के साज-संभाल की ही नहीं थी, बल्कि उसे अधिक समावेशी भी बनाना था. मई 2020 में केंद्र सरकार ने कमजोर लोगों को महामारी की मार से बचाने के वास्ते 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज घोषित किया जिसमें 1.7 लाख करोड़ रु. की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पलॉयमेंट गारंटी एक्ट (मनरेगा) के तहत सहायता और एमएसएमई, प्रवासी कामगारों, फुटपाथ के दुकानदारों और कृषि व संबंधित क्षेत्र के लोगों की मदद का प्रावधान था. साथ ही आवास, बिजली, स्वच्छता, रसोई गैस, पेयजल और आर्थिक समावेशन के लिए बैंक खातों समेत पहले से चल रही योजनाओं के तहत भी मदद जारी है.

इन उपायों के बावजूद, अनेक अध्ययनों में दावा किया गया कि भारत में महामारी के दौरान गरीबी में आबादी की हिस्सेदारी में खासी वृद्धि हुई. बीते साल अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी के एक अध्ययन में दावा किया गया कि महामारी के दौरान 23 करोड़ भारतीय गरीबी की खाई में चले गए, जबकि प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट कहती है कि महामारी से जन्मी मंदी के कारण एक साल में भारत में गरीबों की संख्या 6 करोड़ से दोगुनी बढ़कर 13.4 करोड़ हो गई.

इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भारी जोर का मकसद रोजगार बढ़ाना और उपभोग को रफ्तार देना है, लेकिन यह शायद काफी न हो, क्योंकि पिछले दो साल में रहने-खाने का खर्च कई गुना बढ़ गया है. रोजगार के अवसरों की किल्लत ने आमदनी को प्रभावित किया है. किसी परिवार के खर्च के दो मुख्य स्रोत स्वास्थ्य और शिक्षा की मद में काफी इजाफा हुआ है.

ऑक्सफेम की रिपोर्ट के मुताबिक, किसी सुपर-स्पेशिएलिटी निजी अस्पताल में कोविड-19 के इलाज का खर्च आम भारतीय की औसत मासिक आमदनी का 31 गुना हो

बजट का सहारा

खराब प्रदर्शन करने वाले कुछ राज्यों ने हेल्थकेयर और शिक्षा के मानकों में सुधार के लिए इन क्षेत्रों के बजटीय खर्च का आवंटन बढ़ा दिया

हेल्थकेयर पर सर्वाधिक खर्च करने वाले 5 बड़े राज्य

असम	7	7.1
राजस्थान	6.1	7
हिमाचल प्रदेश	6.5	6.7
पश्चिम बंगाल	5.4	6.7
आंध्र प्रदेश	5	6.6

हेल्थकेयर पर सबसे कम खर्च करने वाले 5 बड़े राज्य

तेलंगाना	4.4	3
पंजाब	4.2	4
महाराष्ट्र	4.5	4.4
झारखंड	4.9	5.2
कर्नाटक	4.5	5.3

बजटीय आवंटन में हेल्थकेयर का हिस्सा ■ 2019-20 और ■ 2021-22 के दौरान प्रतिशत में; कोविड के पहले और कोविड के बाद के खर्च को दिखाने के लिए दो कालखंड चुने गए हैं

शिक्षा पर सर्वाधिक खर्च करने वाले 5 बड़े राज्य

असम	22	19
बिहार	19	19
छत्तीसगढ़	19	19
हिमाचल प्रदेश	19	19
राजस्थान	18	19

शिक्षा पर सबसे कम खर्च करने वाले 5 बड़े राज्य

तेलंगाना	10	7
पंजाब	14	12
कर्नाटक	13	13
तमिलनाडु	15	13
उत्तर प्रदेश	15	13

बजटीय आवंटन में शिक्षा का हिस्सा ■ 2015-20 अभियान ■ 2021-22 के दौरान प्रतिशत में; कोविड के पहले और कोविड के बाद के खर्च को दिखाने के लिए दो कालखंड चुने गए हैं

स्रोत : राज्यों के बजट, एमओएसपीआइ

शिक्षा पर सरकारी खर्च वर्ष 2014 से 2019 के दौरान बजट के 3 प्रतिशत के इर्द-गिर्द मंडराता रहा जबकि इसका ऐतिहासिक लक्ष्य जीडीपी का 6 प्रतिशत रखा गया है

असंतुलित आहार

भारत में दुनिया के 25% कुपोषित लोग रहते हैं. सबसे बढ़िया राज्यों में भी इनकी संख्या बड़ी है लेकिन शीर्ष और निचले क्रम के राज्यों में फर्क बहुत ज्यादा है

पोषण में सर्वश्रेष्ठ 5 राज्य

1. केरल **15.29**
2. पंजाब **22.11**
3. तमिलनाडु **24.8**
4. आंध्र प्रदेश **26.38**
5. हिमाचल प्रदेश **27.18**

पोषण से वंचित आबादी का प्रतिशत

पोषण में निचले पायदान के 5 राज्य

1. बिहार **51.88**
2. झारखंड **47.99**
3. मध्य प्रदेश **45.49**
4. उत्तर प्रदेश **44.47**
5. छत्तीसगढ़ **43.02**

स्रोत : नीति आयोग का बहुआयामी गरीबी सूचकांक, 2021

असमान जनसंख्या वृद्धि

प्रजनन दर बीमारू राज्यों में ऊंचे स्तर पर बनी हुई है

कम टीएफआर* वाले बड़े राज्य

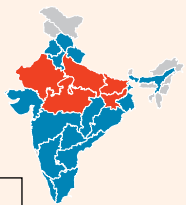

पंजाब, पश्चिम बंगाल — 1.6

आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र — 1.7

ओडिशा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना — 1.8

हरियाणा, उत्तराखंड, असम, गुजरात — 1.9

ज्यादा टीएफआर* वाले बड़े राज्य

बिहार — 3

उत्तर प्रदेश — 2.4

झारखंड — 2.3

मध्यप्रदेश, राजस्थान — 2

*स्रोत : एनएफएचएस-5, * टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट या कुल प्रजनन दर (बच्चे प्रति महिला)*

60% भारतीय पोषक आहार का खर्च वहन नहीं कर सकते, इनमें से ज्यादातर हिंदीभाषी और पूर्व के राज्यों में हैं

1.4 प्रजनन दर है जम्मू-कश्मीर में जो भारत में सबसे कम है

सकता है. सिर्फ कोविड ही नहीं, स्वास्थ्य की मद में जेब से खर्च 5.5 करोड़ लोगों को 2017 में गरीबी की ओर ढकेल ले गया. इसी तरह, पिछले दो साल में दूसरा सबसे बुरी तरह प्रभावित क्षेत्र शिक्षा का है. डिजिटल शिक्षा की ओर अचानक अग्रसर होने से मोबाइल फोन या लैपटॉप खरीदने और इंटरनेट डेटा प्लान खरीदने से खर्च में इजाफा हुआ है.

महामारी की मार से रोजगार में भारी कटौती के वर्ष में, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट आवंटन बढ़ाए जाने की उम्मीद थी. शिक्षा पर सरकारी खर्च 2014 और 2019 के बीच जीडीपी के करीब 3 फीसद के आसपास घूमता है, जबकि ऐतिहासिक लक्ष्य 6 फीसद का है. दूसरे मध्यम आय वाले देश ज्यादा खर्च करते हैं—मसलन, ब्राजील 6.1 फीसद, रूस 4.7 फीसद और दक्षिण अफ्रीका 6.8 फीसद. इन देशों में स्वास्थ्य पर भी भारत के 3.5 फीसद के मुकाबले ज्यादा आवंटन रहा है—ब्राजील 9.5 फीसद, रूस 5.3 फीसद और दक्षिण अफ्रीका 8.2 फीसद. इस बजट में महामारी की हालत के मद्देनजर केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य पर खर्च का बजट आवंटन (2020-21 के मुकाबले) 28 फीसद बढ़ाया है, लेकिन इसी अवधि में शिक्षा मंत्रालय का आवंटन महज 5 फीसद बढ़ा है. दरअसल सरकार के 2020 में नई शिक्षा नीति के ऐलान के बावजूद बजट आवंटन 2020-21 में 99,311.5 करोड़ रु. से घटकर 2021-22 में 93,224.3 करोड़ रु. हो गया है.

फिर भी, कई खराब प्रदर्शन वाले राज्यों ने शिक्षा और स्वास्थ्य की मद में अधिक रकम का आवंटन करके चीजें सुधारने की कोशिश की है. पिछले साल जारी हुए नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक (एमपीआइ) के मुताबिक, बिहार और असम जैसे राज्य शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च कर रहे हैं, जिनकी बहुआयामी गरीब आबादी क्रमश: 52 फीसद और 33 फीसद है. असल में, असम तो बड़े राज्यों में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर सबसे ज्यादा खर्च करने वाला रहा है. इसके नतीजे भी दिख रहे हैं. असम, नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक, 2019-20 में स्वास्थ्य क्षेत्र में खासी प्रगति दिखाने वाला दूसरा राज्य बनकर उभरा है.

इसी तरह, उत्तर प्रदेश ने आधार वर्ष (2018-19) से संदर्भ वर्ष (2019-20) के बीच माध्यमिक स्वास्थ्य परिणाम सूचकांक के प्रदर्शन में खासा सुधार दिखाया है.

लेकिन ऐसी बढ़ोतरी वाले सुधार इसलिए फीके पड़ जाते हैं क्योंकि अव्वल पांच राज्यों और निचले पांच राज्यों के बीच कुल प्रदर्शन का फर्क बड़ी खाई जैसा है. बहुआयामी गरीब बिहार में 52 फीसद हैं तो

केरल में 1 फीसद से भी कम हैं.

गरीबी में यह फर्क इन राज्यों के स्वास्थ्य और शिक्षा की मद में प्रदर्शन में झलकता है. नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 में अव्वल चार राज्य दक्षिण के केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश हैं जबकि निचले चार हिंदी प्रदेश से-उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान हैं. समृद्ध दक्षिण भारतीय राज्यों ने खासकर स्वास्थ्य और शिक्षा में निवेश की विरासत की वजह से अच्छा प्रदर्शन किया है.

इस फर्क को गहरा करने वाला दूसरा पहलू पौष्टिकता का स्तर है. दुनिया की पौष्टिकता में कमी वाली कुल आबादी का एक-चौथाई भारत में है. फूड पॉलिसी जर्नल में प्रकाशित इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट (आइएफपीआरआइ) की कल्याणी रघुनाथन के अक्तूबर 2020 के अध्ययन-पत्र से पता चला कि 60 फीसद भारतीय पौष्टिक आहार नहीं खा पाते. इनमें ज्यादातर आबादी हिंदी प्रदेशों और पूर्वी राज्यों की है. नीति आयोग की एमपीआइ रिपोर्ट के मुताबिक, पांच राज्यों-बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के आंकड़े 43-52 फीसद के बीच हैं. केरल और तमिलनाडु की हिस्सेदारी क्रमशः 15 फीसद और 25 फीसद है. दूसरे सूचकांकों के मामलों में भी यही सही है. केरल में शिशु मृत्यु दर प्रति 1,000 जन्म पर सिर्फ 4.4 है और तमिलनाडु में 18.6 है. इसके विपरीत बिहार और उत्तर प्रदेश में यह क्रमशः 50.4 और 46.8 है. शिक्षा का सूचकांक भी राज्यों के बीच खाई का आईना है. स्कूली शिक्षा से वंचित आबादी की हिस्सेदारी बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 27 फीसद से 17 फीसद के बीच है (एमपीआइ आंकड़े). यह हिस्सेदारी केरल, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में 2 फीसद से 7 फीसद के बीच है.

इन फर्कों को हाल में जारी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस)-5 के संदर्भ में देखने से कई सामाजिक मिथक टूट जाते हैं. कई राज्यों में यह राजनैतिक अफसाना जोरदार है कि ऊंची जनसंख्या वृद्धि के लिए मुसलमान जिम्मेदार हैं. लेकिन विडंबना देखिए कि एनएफएचएस-5 से पता चलता है कि देश में प्रजनन दर-यानी प्रति महिला बच्चे की दर बदलाव स्तर से नीचे 2 पर पहुंच गई है (बदलाव स्तर 2.1 है, जो किसी देश में जन्म और मृत्यु की संख्या में संतुलन के लिए जरूरी आधार-रेखा है). इस दर से जनसंख्या न बढ़ रही है, न घट रही है. वह स्थिर बनी हुई है. 2.1 से नीचे जाने का मतलब है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट नहीं है और भविष्य में इसमें गिरावट देखी जा सकती है. एनएफएचएस-5 से यह भी पता चला है कि 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की आबादी देश में 2015-16 के 28.6 फीसद से गिरकर 2019-20 में 26.5 फीसद पर आ गई है.

सबसे बढ़कर देश में मुसलमान बहुल आबादी वाले इकलौते जम्मू-कश्मीर (जो राज्य से अब केंद्र शासित प्रदेश है) में सबसे कम प्रजनन दर 1.4 दर्ज की गई है. दूसरे नंबर पर ज्यादा मुस्लिम आबादी (34 फीसद) वाले असम में प्रजनन दर 1.9 दर्ज की गई है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है. इसके उलट सबसे ऊंची प्रजनन दर वाले दो राज्य बिहार (3) और उत्तर प्रदेश (2.4) वही हैं, जो स्वास्थ्य और शिक्षा के एमपीआइ सूचकांक में सबसे नीचे हैं.

जानकारों के मुताबिक, समृद्ध राज्यों में शिक्षा के उच्च स्तर और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं से सभी धर्मों में महिलाओं की शादी अधिक उम्र में होती है और नतीजतन प्रजनन दर में गिरावट आती है. मुंबई में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंसेज में डिपार्टमेंट ऑफ बायोस्टैटिस्टिक्स ऐंड इपीडेमियोलॉजी की प्रमुख प्रोफेसर सईदुन निसा कहती हैं, ''प्रजनन का काफी ज्यादा रिश्ता धर्म या जाति के बदले शिक्षा से जुड़ा है.''

भारत की 1.3 आबादी—जिसे कई सामाजिक बुराइयों की जड़ माना जाता है—अब स्थिर हो गई है. लेकिन उसका काफी बड़ा भाग गरीबी में जकड़ा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार गरीबों और वंचितों को आवास, बिजली, रसोई गैस, पानी और वित्तीय समावेशन के जरिए ताकत देने का काम कर रही है. 2005-06 और 2015-16 में बहुआयामी गरीबों की आबादी 54.7 फीसद से गिरकर 27.5 फीसद हो गई. मौजूदा सरकार के लिए चुनौती यह है कि वह उस रुझान को महामारी की वजह से मुड़ने न दे. ■

मदद का हाथ

गरीबों को राहत देने वाली केंद्र सरकार की योजनाएं

योजना का नाम	यह क्या है?	कुल लाभार्थी *
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना	12 रुपए के सालाना प्रीमियम पर 2 लाख रुपए की दुर्घटना बीमा योजना	268,200,000
पीएम श्रम योगी मान-धन योजना	असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना	4,594,095
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना	330 रुपए सालाना के प्रीमियम पर 2 लाख रुपए की जीवन बीमा योजना	119,000,000
प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) **	विभिन्न नकद लाभों को सीधे बैंक खातों में भेजना	2.1 लाख करोड़ रु.
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना	गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाली महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन	89,864,645
अयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना	50 करोड़ लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर	26,136,725
पीएम आवास योजना	गरीबों को मुफ्त आवास	22,372,145
पीएम जन-धन योजना	गरीबों का जीरो बैलेंस बैंक अकाउंट	लागू नहीं
पीएम किसान सम्मान निधि योजना	सभी किसान परिवारों को सालाना 6,000 रु. की आय सहायता	119,518,991

*स्रोतः पीएमओ डैशबोर्ड, 31-01-2022 तक, ** डीबीटी में खातों में भेजी गई रकम का ब्योरा है*

मनरेगा आवंटन कोविड पूर्व समय के स्तर पर पहुंच चुका है

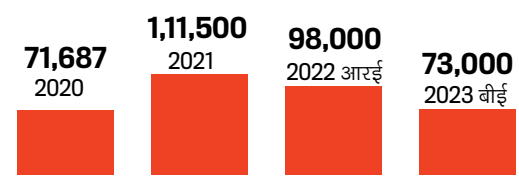

आंकड़े करोड़ रु. में, कालखंड वित्त वर्ष, आरई-रिवाइज्ड एस्टिमेट, बीई-बजट एस्टिमेट

इंडिया टुडे

देश की भाषा में देश की धड़कन

INDIA TODAY GROUP

एआइएस कैडर नियमों पर केंद्र-राज्यों में ठनी
बिहार: बीसी की निगरानी से चिढ़े बांसलर
जगनमोहन रेड्डी: कर्ज लेकर पिला रहे घी
इंडिया टुडे
"मैं कभी हारा नहीं"
अखिलेश यादव की तगड़ी चुनौती और इस तथ्य के मद्देनजर कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री पांच साल पूरे कर सत्ता में नहीं लौटा, योगी आदित्यनाथ और भाजपा की क्या है रणनीति?

विशेषांक
इंडिया टुडे
देश का मिज़ाज सर्वेक्षण
भरोसा बढ़ा... लेकिन
छह महीने पहले के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां बरकरार. अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी?

सबसे भरोसेमंद स्रोतों से, सबसे सटीक जानकारी

सब्सक्राइब करें और पाएं 21% तक की छूट

अखिलेश यादव की तगड़ी चुनौती और इस तथ्य के मद्देनजर कि आजादी के बाद उत्तर प्रदेश का कोई मुख्यमंत्री पांच साल पूरे कर सत्ता में नहीं लौटा, योगी आदित्यनाथ और भाजपा की क्या है रणनीति?

छह महीने पहले के मुकाबले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी लेकिन आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियां बरकरार. अगर आज हुए लोकसभा चुनाव तो किसको कितनी सीटें मिलेंगी?

हां! मैं इंडिया टुडे को सब्सक्राइब करना चाहता/चाहती हूँ

अपनी पसंद के सब्सक्रिप्शन को टिक करें और फॉर्म को इस पते पर भेज दें– **वी केअर, लिविंग मीडिया इंडिया लि. सी–9, सेक्टर–10, नोएडा 201302 (भारत)**

टिक करें	अवधि	कुल अंक	कवर प्राइस (₹)	ऑफर प्राइस (₹)	डिस्काउंट
☐	2 वर्ष	104	~~5200~~	4099	21%
☐	1 वर्ष	52	~~2600~~	2199	15%

कृपया फॉर्म को ब्लॉक लेटर में भरें

मैं चेक/डीडी जमा कर रहा/रही हूँ जिसकी संख्या.....है और इसे दिनांक..... को लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड के पक्ष में ..... (बैंक का नाम).....रुपये की धनराशि (दिल्ली से बाहर के चेक के लिए ₹ 50 रुपये अतिरिक्त जोड़ें, समान मूल्य के चेक मान्य नहीं होंगे) के लिए बनवाया गया है.

नाम..... पता.....

..... शहर..... राज्य..... पिन.....

मोबाइल..... ईमेल.....

सब्सक्राइब करने के लिए यहां स्कैन करें.

ऑफर के विषय में विशेष जानकारी के लिए निम्न माध्यमों से संपर्क भी कर सकते हैं

हमारे टॉल फ्री नंबर पर कॉल करें
18001800100 (0120) 2479900

ईमेल भेजें
wecare@intoday.com

लॉग ऑन करें
subscriptions.intoday.in/indiatoday-hindi

लिविंग मीडिया इंडिया लिमिटेड इस ऑफर या इसके अंश को कभी भी समाप्त करने या आगे बढ़ाने का अधिकार सुरक्षित रखता है. अन्य नियम व शर्तों की जानकारी के लिए कृपया देखें-www.indiatoday.in

सभी फोटोः बंदीप सिंह

संजीव शुक्ल, 54 वर्ष

औचक झटका महामारी से पहले संजीव मुथूट फाइनेंस में एक करोड़ रु. सालाना पा रहे थे. शुरू के महीनों में ही नौकरी चली गई. उसके बाद उनके लिए वैसी नौकरी मिल पाना मुहाल हो गया

ये कैसा सिला दिया!

कभी आर्थिक विकास का इंजन रहा मध्य वर्ग अब महामारी में पिस रहा. बजट 2022 में उसे रत्ती भर भी राहत न मिली

श्वेता पुंज

निर्मला सीतारमण उतनी ही मध्यवर्गीय हैं जितना भारत में कोई मध्यवर्गीय हो सकता है. चेन्नै और तिरुचिरापल्ली से स्कूल की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने तमिलनाडु के सीतालक्ष्मी रामस्वामी कॉलेज से अर्थशास्त्र में बैचलर और फिर जेएनयू से मास्टर्स डिग्री ली. भाजपा प्रवक्ता से मोदी सरकार में बड़े मंत्रालय संभालने तक उनकी तरक्की जितनी भी तेज रही हो, उन्हें भारत के विशाल मध्यवर्गीय खेमे का ही हिस्सा माना जाता है. वही मध्य वर्ग, जिसमें करीब 38 करोड़ या भारत की कुल आबादी के एक-चौथाई लोग हैं. इस फलते-फूलते मध्य वर्ग को 1991 के सुधारों के बाद भारत के असाधारण आर्थिक उभार के प्रतीक के तौर पर देखा जाता रहा है. पर अब नहीं.

अपने तीसरे साल में चल रही कोविड-19 महामारी की तीखी मार भारत के 'मध्य वर्ग' ने खास तौर पर झेली है. अमेरिका के प्यू रिसर्च सेंटर के अनुमान के मुताबिक, 2020 में मध्य वर्ग की तादाद 3.2 करोड़ लोग कम हो गई. उसका यह भी कहना है कि महामारी के बाद भारत में गरीबों की तादाद के दोगुनी हो जाने का अनुमान है जबकि मध्य वर्ग एक तिहाई घट गया. कई सर्वे और अध्ययन महामारी की वजह से मध्य वर्ग पर पड़ने वाली आर्थिक मार की पुष्टि करते हैं. प्यू की मानें तो कोविड से उपजी मंदी के चलते भारत में गरीबों—रोज 150 रु. या उससे कम कमाने वाले—की आबादी 7.5 करोड़ बढ़ने का अनुमान है. दुनिया भर में बढ़ी गरीबी का यह करीब 60 फीसदी है.

हालांकि मिडल क्लास की कई परिभाषाएं हैं—अमूमन 10 लाख रु. से 1 करोड़ रु. सालाना कमाने वाले—लेकिन जिधर देखिए, महामारी के

INDIA TODAY

BREAKING NEWS

JUST A TAP AWAY

DOWNLOAD THE APP NOW

AVAILABLE ON

साक्षी चानना, 36 वर्ष

चुक गया सब कुछ महामारी के शुरुआती महीनों में ही कूव्स में अपनी नौकरी खो देने के बाद चानना ने आत्मनिर्भर बने रहने की बड़ी कोशिश की. पर अंत में बचत चुक जाने पर मजबूर होकर मम्मी-पापा के पास आना पड़ा.

''अपनी बचत का बड़ा हिस्सा मैंने खर्च कर डाला. अपनी एफडी मुझे फिर से बनवानी पड़ेगी. और मेरे करिअर का तो इस समय बाजा ही बज गया है''

जख्मों के निशान साफ दिखाई देते हैं. दिल्ली के 54 वर्षीय संजीव शुक्ल को ही लें. महामारी ने जिस वक्त धावा बोला, कॉर्पोरेट जगत में 30 साल बिता चुके मार्केटिंग प्रोफशनल शुक्ल मुथूट फाइनेंस में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के पद पर सालाना एक करोड़ रुपए कमा रहे थे. दूसरे तमाम लोगों की तरह शुरुआती महीनों में ही उनकी नौकरी चली गई. नौकरी गंवाने वाले कई दूसरों के मुकाबले हालांकि वे ज्यादा संपन्न हैं (उनकी पत्नी अब भी नौकरी में हैं, 30 साल की बचत, दूसरी संपत्तियां वगैरह भी हैं). पर इस परिवार ने भी बड़ी मार झेली. उन्हें कार बेचनी पड़ी और खर्चों में भारी कटौती करनी पड़ी. अब वे महंगे विश्वविद्यालयों में पढ़ते बच्चों की फीस, औचक इलाज और बुढ़ापे में जरूरी पैसों को लेकर परेशान हैं. बजट 2022 ने शुक्ल को कोई राहत नहीं दी. उन्हें ''आयकर के स्लैब में कुछ बदलाव की उम्मीद थी, उससे मदद मिलती.''

हालांकि, सीतारमण ने बजट भाषण में भारत की आर्थिक वृद्धि में मध्य वर्ग का योगदान माना, पर बजट में कइयों को अपने लिए उम्मीद दिखाई नहीं देती. 26 वर्षीय यतिन भारद्वाज ने जनवरी 2020 में दिल्ली में जिम खोला था, पर तभी कोविड की वजह से उनकी आकांक्षाओं पर भी लॉकडाउन लग गया. महीनों तक कमाई लॉकडाउन की भेंट चढ़ गई. दो साल बाद भी आधा ही यानी 15,000 रुपए कमा पाते हैं. ड्राइवर का काम कर रहे उनके पिता की भी नौकरी चली गई. सो उनके कंधों पर मां-बाप समेत चार परिजनों की जिम्मेदारी आ गई. वे कहते हैं, ''मैंने प्रोटीन शेक पीना बंद कर दिया, महीने में 5,000 रुपए उस पर खर्च हो जाते थे. दो साल से अपने लिए एक चीज नहीं खरीदी.'' भारद्वाज बजट से निराश हैं: ''आमदनी में सीधी सहायता से बहुत मदद मिलती. पैसा नहीं दे सकते तो कम से कम काम तो करने दें. सावधानियों के साथ हमें जिम खोलने दें.''

शुक्ल और भारद्वाज सरीखे तमाम मध्यवर्गीय लोगों ने अपनी रोजी-रोटी इसी तरह से मटियामेट होते देखी. इस मुश्किल वक्त से उबारने के लिए बजट 2022 उनकी कोई सीधी मदद नहीं करता, चाहे वह प्रत्यक्ष करों में कमी हो या मनरेगा की तर्ज पर शहरी रोजगार गारंटी योजना. जहां तक नौकरियों के वास्तविक नुक्सान की बात है, सीएमआइई (सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनोमी) के अनुसार, अप्रैल—अगस्त 2020 के बीच करीब 2.1 करोड़ नौकरियां चली गईं.

पिसता-सिकुड़ता मध्य वर्ग

बीते कुछ दशकों के दौरान भारत के मध्य वर्ग का विकास एक असाधारण किस्म की आर्थिक घटना थी. करोड़ों लोग गरीबी से बाहर निकले, आमदनियां बढ़ीं, भारत फोन और गैजेट से लेकर कारों, घरों और इनके बीच आने वाली तमाम उपभोक्ता वस्तुओं का विशाल बाजार बन गया. इस बढ़ती खपत से आर्थिक वृद्धि को उछाल मिला. बढ़ती आमदनी, बढ़ते उपभोग और बढ़ती आर्थिक गतिविधियों का चक्र और मजबूत हुआ. विशेषज्ञों का कहना है कि आज कोविड के तीसरे साल में चिंता की बात यह है कि अगर मध्य वर्ग सिकुड़ गया, तो खपत भी कम होगी, जो आर्थिक तरक्की का सबसे अहम इंजन है. जितने ज्यादा परिवार मध्य वर्ग से गरीबी में उतरेंगे, भारतीय बाजारों में उतने ही कम खरीदार होंगे, कंपनियों की कमाई और तनख्वाहें घटेंगी और आर्थिक वृद्धि के रुझान को नीचे खींचेंगी.

महामारी बहाना बन गई वरना इस समस्या के संकेत पहले से ही थे. अर्थशास्त्री अनिरुद्ध कृष्ण और देवेंद्र बाजपेयी ने आमदनी की बजाए एसेट का विश्लेषण करते हुए पाया कि भारतीय मध्य वर्ग का विस्तार महामारी के कदम पड़ने से पहले ही धीमा पड़ गया था. 2017-18 के आंकड़ों के विश्लेषण पर आधारित एनएसओ (राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय) की 2019 में लीक हुई एक रिपोर्ट से खपत में चार दशक में पहली बार गिरावट का पता चला. एनएसओ के विश्लेषण

महामारी के कदमों तले

भारत का मध्य वर्ग महामारी की बुरी मार से अभी तक कराह रहा है—तनख्वाहों में कटौती, नौकरियों को लेकर असुरक्षा और बढ़ते अंदेशे. बजट 2022 में इस तबके को सीधी मदद से बड़ी राहत मिलती

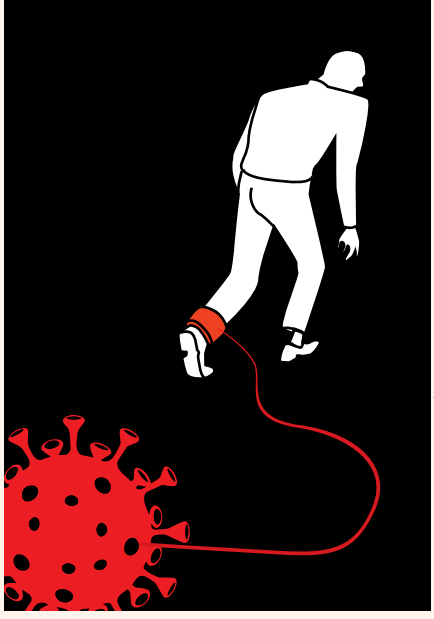

इलस्ट्रेशन: तन्मय चक्रवर्ती

शुरू हुई तबाही महामारी शुरू होने के बाद नौकरियों के बाजार में शुरू हुई तेज गिरावट 2020 के आखिर तक भी संभल न पाई. उसके अगले साल तो और भी बुरे दिन देखने पड़े

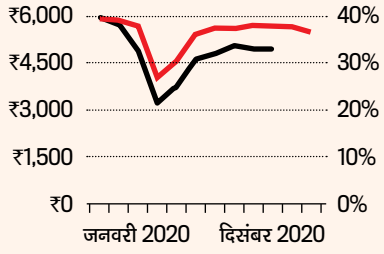

जनवरी 2020 की मूल्य दर पर आमदनी, मौसम के हिसाब से समायोजित

भारत की अर्थव्यवस्था: बड़ी तस्वीर

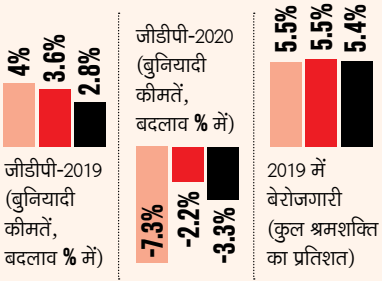

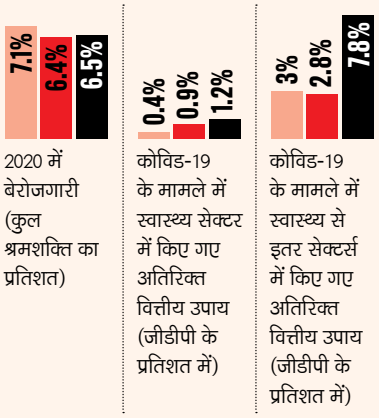
7.1%
6.4%
6.5%
2020 में बेरोजगारी (कुल श्रमशक्ति का प्रतिशत)
0.4%
0.9%
1.2%
कोविड-19 के मामले में स्वास्थ्य सेक्टर में किए गए अतिरिक्त वित्तीय उपाय (जीडीपी के प्रतिशत में)
3%
2.8%
7.8%
कोविड-19 के मामले में स्वास्थ्य से इतर सेक्टर्स में किए गए अतिरिक्त वित्तीय उपाय (जीडीपी के प्रतिशत में)

भारत तुलना वाले देश विश्व

स्रोतः विश्व आर्थिक परिदृश्य के आंकड़े, अप्रैल 2021, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष
(मैत्रीश घटक और राघवन का एक अध्ययन)

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

जद में नौजवान 2020 में 32.8 प्रतिशत युवा श्रमिकों ने नौकरी जाने और लंबे समय तक बेरोजगार होने दोनों की शिकायत की

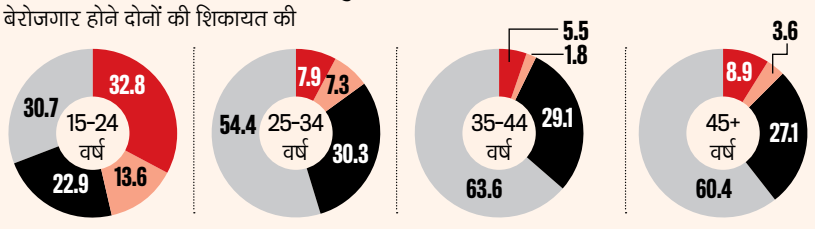

#1: लॉकडाउन में गई नौकरी दिसंबर तक भी बहाल न हुई #2: लॉकडाउन में नहीं पर दिसंबर तक चली गई नौकरी #3: लॉकडाउन में नौकरी गई पर दिसंबर तक बहाल #4: लॉकडाउन में और उसके बाद भी नौकरी बरकरार रही

बदल लिया काम 2019 में वेतनभोगी श्रमिक 2020 में खुद का काम शुरू करते देखे गए

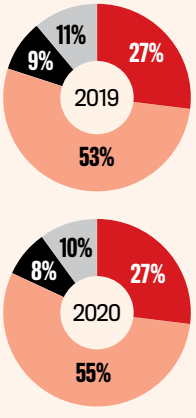

जब खाली हो गई जेब 2020 में खासकर गरीब परिवारों में कर्जदारी तेजी से बढ़ी

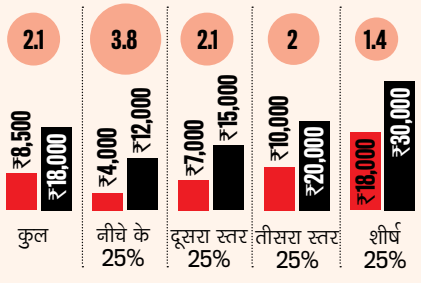

स्रोतः अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया, 2021

के निष्कर्ष के बारे में अब पक्के तौर पर कह पाना मुश्किल है कि 2017 में खपत में गिरावट आई थी या नहीं, फिर भी यह डेटा लंबे वक्त में भारत की आर्थिक वृद्धि की राह तय करने में अहम है. लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में प्रोफेसर मैत्रीश घटक बताते हैं, ''सामान्य रूप से कहें तो कोविड ने फिर आमदनी और खपत में गिरावट वाले उसी सिलसिले को मजबूत किया जो शायद

3.2 करोड़
लोग कम हो गए, मध्य वर्ग के कुल आकार से. प्यू रिसर्च का आकलन

2019 से पहले शुरू हुआ था. बहुत अमीर लोगों को छोड़ दें, जिनकी आमदनी श्रम बाजार से नहीं आती और जिन्हें नौकरी की गारंटी है, तो बाकी 95 फीसद अर्थव्यवस्था पर गिरावट की तगड़ी मार पड़ी है.''

घटक और राम्या राघवन के एक अध्ययन द *कोविड-19 शॉक ऐंड दि इंडियन इकॉनोमी* के अनुसार, 2019 और 2020 के बीच भारत की

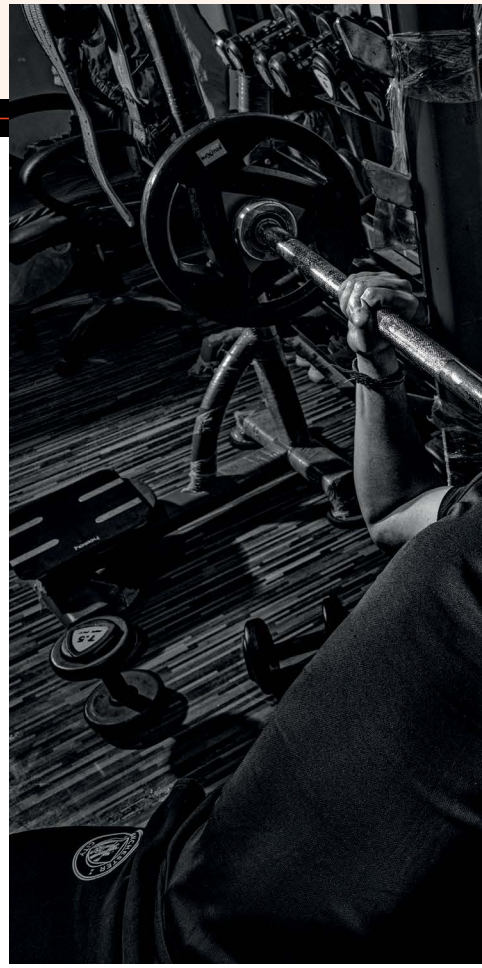

इंद्रनील भौमिक, 42 वर्ष

छा गया अंधेरा फोटो-जर्नलिस्ट भौमिक की 2020 में 80 फीसद आय चली गई. वे कहते हैं, ''शुरू के आठ महीने तो मैं कुछ भी न कर सका. कोई काम ही नहीं था तो मैं करता भी तो क्या?''

''दो साल तक मैंने जागते हुए रातें काटी हैं''

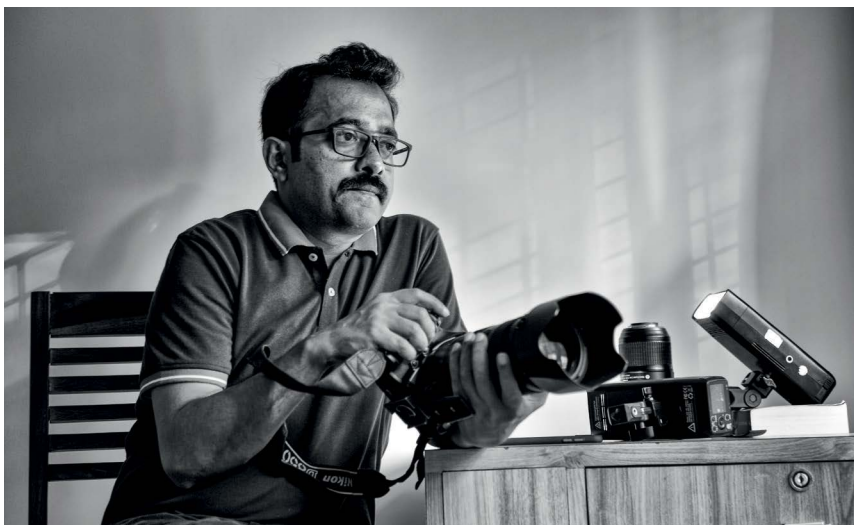

सुबीर हल्दर

राष्ट्रीय आय सही मायनों में आठ फीसद गिरी. प्रति व्यक्ति के लिहाज से यह गिरावट नौ फीसद थी. स्वतंत्र भारत में, 2020 से पहले भारत की राष्ट्रीय आय में केवल चार बार गिरावट आई—1958, 1966, 1973 और 1980 में. अध्ययन कहता है: 'सबसे बड़ी गिरावट 1980 में (5.3 फीसद) आई, जब देशव्यापी सूखे और ईरान में क्रांति की वजह से तेल के वैश्विक दाम के दोगुने होने के कारण अर्थव्यवस्था में खलबली मची थी. आशय ये कि 2020-21 आर्थिक सिकुड़न के लिहाज से भारत के इतिहास का बदतरीन साल है.' प्यू रिसर्च सेंटर के अध्ययन में महामारी के बाद भारत में गरीबों की संख्या दोगुने से ज्यादा होने और मध्य वर्ग में एक-तिहाई कटौती का अनुमान है. अजीम प्रेमजी विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट के शोधकर्ताओं ने 12 भारतीय राज्यों में मध्य-अप्रैल और मध्य-मई 2020 के बीच स्वनियोजित, अनियत और नियमित दिहाड़ी कामगारों पर एक अध्ययन किया. 2020 के इस अध्ययन ने आमदनी में 64 फीसद गिरावट बताई. दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 के बीच किए गए एक और दिल्ली-एनसीआर कोरोनावायरस टेलीफोन सर्वे (एनसीएईआर 2021) ने बताया कि 80 फीसद उत्तरदाताओं ने आर्थिक दुश्वारियों का जिक्र किया, जिनमें वेतन कटौती, नौकरी जाना, काम ढूंढ़ने में मुश्किल, कारोबार ठप होना या कारोबारी आमदनी में गिरावट शामिल थीं. वेतनभोगी कर्मचारियों और छोटे कारोबार मालिकों पर सबसे बुरी मार पड़ी.

2.1 करोड़
नौकरियां गईं अप्रैल-अगस्त 2020 में. सीएमआइई का अनुमान

पंक्चर होते पहिए

दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट एक और इशारा है. सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (एसआइएएम या सियाम) के मुताबिक, वित्त वर्ष '21 की तीसरी तिमाही में 49 लाख दुपहिए बिके थे जबकि वित्त वर्ष 2022 की तीसरी तिमाही में 36 लाख ही दुपहिए बिके.

एमबीए डिग्रीधारी 30 वर्षीय टी. मोहम्मद की मिसाल लें, जो बताती है कि मांग क्यों गिर रही है. बिहार के एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्मे मोहम्मद 15 बरस की उम्र से दिल्ली में रह रहे हैं. 2014 में जामिया मिल्लिया इस्लामिया से एमबीए करने के बाद वे पहले कंसल्टेंट के तौर पर प्राइस वाटर हाउस कूपर्स से जुड़े और फिर ईवाइ इंडिया में आ गए. महामारी ने जिस वक्त धावा बोला, वे नई नौकरी में जाने की प्रक्रिया में थे. लगातार बिगड़ते हालात के चलते कंपनी ने पेशकश वापस ले ली और आर्थिक तौर पर वे मुश्किल में आ फंसे. तब से वे दर्जन भर इंटरव्यू दे चुके हैं लेकिन नौकरी नहीं मिली. बेरोजगार हुए दो साल हो गए, बचत खर्च हो चुकी है. बाइक उन्होंने 11,000 रुपए में बेची और कार लोन तथा पर्सलन लोन चुकाने के लिए हाथ-पैर मारे. वे कहते हैं, ''आमदनी है नहीं, मैंने 17 महीनों से पर्सलन लोन की ईएमआइ नहीं चुकाई है.'' पीएफ की बचत से उन्होंने कार लोन चुका दिया और मकान मालिक इतने रहमदिल निकले कि दो साल से उनसे किराया नहीं ले रहे हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि दुपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट आर्थिक विश्वास में कमी

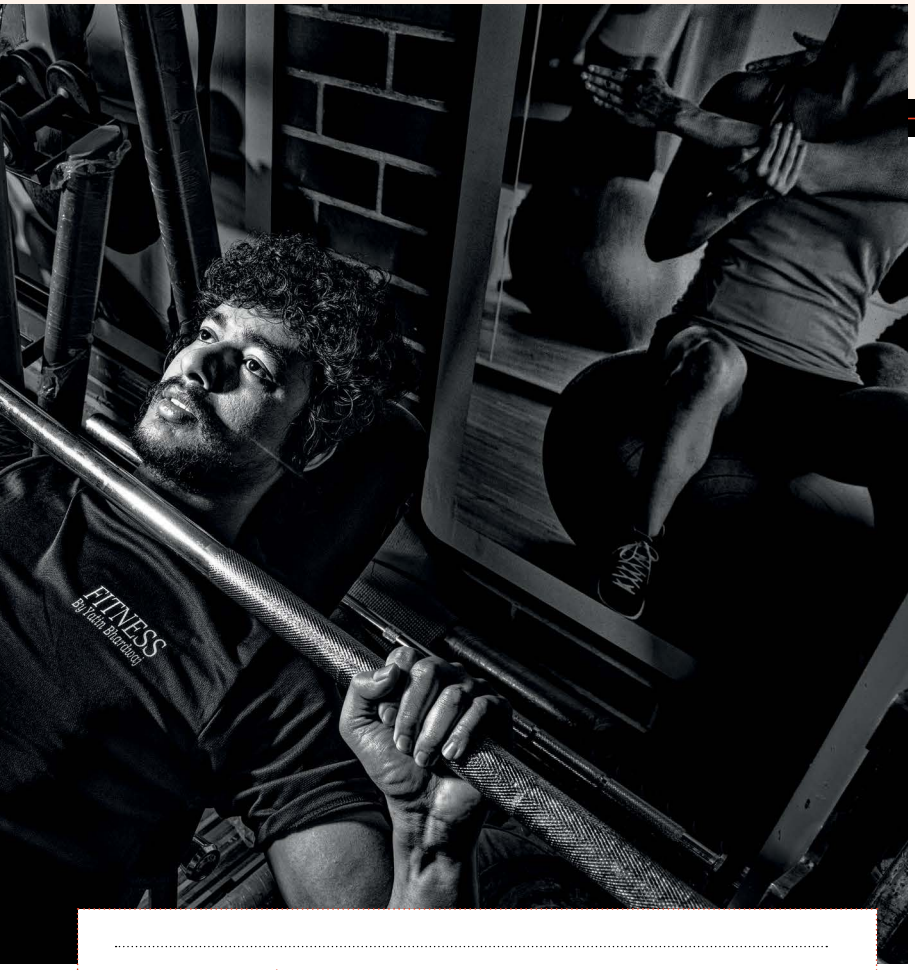

यतिन भारद्वाज, 26 वर्ष

बंद हुए दरवाजे जनवरी 2020 में अपनी बचत लगाकर भारद्वाज ने एक फिटनेस स्टूडियो खोला था. दो महीने बाद देश भर में लॉकडाउन लग जाने पर उनकी आमदनी ठप हो गई. अब किसी तरह 15,000 रुपए महीने की कमाई शुरू हुई है. उन्हें चार लोगों का परिवार संभालना पड़ता है, जिनमें उनके मम्मी-पापा और बहन शामिल हैं.

''मैंने प्रोटीन शेक पीना छोड़ दिया क्योंकि उस पर 5,000 रुपए महीने जाते थे. पिछले दो साल में अपने लिए मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है''

की तरफ इशारा करती है. यह दिखाती है कि उपभोक्ता ऑटो लोन चुकाने के अनिच्छुक या असमर्थ हैं. बीते दो साल में रिजर्व बैंक की कम ब्याज दर की नीति का इस श्रेणी पर कम ही असर पड़े होने का अनुमान है. दुपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट 2018 में शिखर पर पहुंचने के बाद आई, जब मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाने के लिए नोटबंदी, जीएसटी की शुरुआत वगैरह के जरिए सर्जरी शुरू की थी. यह तथ्य बताता है कि उस कोशिश को कामयाब बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है. जब ढांचागत बदलावों से गुजर रही अर्थव्यवस्था को महामारी से होने वाले नुक्सान की बात आती है, तो जेपी मॉर्गन में इमर्जिंग मार्केट इकॉनोमीज के प्रमुख जहांगीर अजीज कहते हैं, ''महामारी से नुक्सान का जो स्थायी निशान पड़ेगा, वह परिवारों और छोटे तथा मझोले उद्योगों की बैलेंस शीट को होने वाला व्यापक नुक्सान है. गरीब ही नहीं, इन तबकों को हुआ नुक्सान भविष्य में भारत की वृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा है.''

दिल्ली की 36 वर्षीया साक्षी चानना, जो कम्युनिकेशंस प्रोफेशनल के तौर पर 10 साल बिता चुकी हैं, बैलेंस शीट को हुए इस नुक्सान की मिसाल हैं. महामारी शुरू होने पर ई-टेलर कूव्ज की उनकी नौकरी चली गई. दूसरी नौकरी का ऑफर मिला ही था कि महामारी से हालात बिगड़ने पर वह भी वापस ले लिया गया. वे कहती हैं, ''मुझे नहीं पता, मेरा करियर किधर जा रहा है.'' नौकरी गंवाने के बाद पहले छह महीने उन्होंने बचत और एफडी वगैरह से जिंदगी चलाई. मकान मालिक ने किराया बढ़ाने का फैसला किया तो कैलाश कॉलोनी में मम्मी-पापा के घर लौट आईं. वे बताती हैं कि पीएफ खाता ही उनका अकेला निवेश है जो बचा हुआ है. ''बचत का बड़ा हिस्सा मैं गंवा चुकी हूं, एफडी मुझे फिर से बनानी पड़ेंगी, मेरा करियर पटरी से उतर गया है. मैं अपनी मानसिक सेहत को लेकर फिक्रमंद हूं.''

नुस्खे नीतियों के

मध्य वर्ग को सहारा देने के लिए अजीज और घटक सरीखे विशेषज्ञ सबसे ज्यादा संकट में फंसे लोगों की आमदनी में सीधे मदद की सिफारिश करते हैं. कुछ दूसरे लोग—और सरकार—बुनियादी ढांचे पर ज्यादा खर्च करने की दलील देते हैं ताकि उसका प्रभाव छलककर पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़े. विशेषज्ञों का कहना है कि कर चुकाने की अवधि में मोहलत, कर राहत या इस तरह की नीतिगत सहायता से मदद मिलेगी, उपभोक्ताओं के हाथ में कुछ ज्यादा नकदी होगी. कुछ विशेषज्ञ आमदनी में सीधी सहायता के लिए 'शहरी मनरेगा' का सुझाव देते हैं. मगर केंद्रीय बजट ने अर्थव्यवस्था को लेकर दीर्घकालिक नजरिया अपनाया. इस प्रक्रिया में उन लाखों लोगों की फौरी तकलीफ को दरकिनार कर दिया गया है जो भारत के मध्य वर्ग का निर्माण करते हैं—जो मांग में तेजी लाते हैं, खपत को रफ्तार देते हैं और कर चुकाते हैं. लोगों और एमएसएमई को सलाह देने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंसी एसपी कपूर ऐंड कंपनी के सीईओ संजीव शिव कपूर कहते हैं: ''मध्य वर्ग के लिए मुझे (बजट में) कुछ दिखाई नहीं देता. कर दरों में कोई फायदा या बदलाव नहीं है. बल्कि सरकार ने तो 50,000 रुपए से ज्यादा के तोहफों पर अब एक फीसद टीडीएस लगा दिया है.''

उम्मीद के मुताबिक जब विपक्ष ने मध्य वर्ग के लिए बजट में कुछ न होने को लेकर सरकार से सवाल किए, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटकर कहा: ''क्या किसानों, एमएसएमई, सस्ते घर के खरीदारों में मध्य वर्ग का हिस्सा नहीं है? हम उनके लिए राहत उपाय लेकर आए. मध्य वर्ग का क्या मतलब है? मध्यवर्गीय किसानों के लिए योजनाएं लाई गई हैं. सस्ते घरों से मध्य वर्ग को फायदा मिलेगा. शेयरों में पैसा लगाने वाले लोगों को फायदा मिलेगा, वे भी तो मध्य वर्ग हैं.'' पर कई लोगों का मानना है कि वित्त मंत्री को और भी बहुत करना होगा, ताकि मध्य वर्ग को यकीन दिला सकें कि वह जल्द ही फिर खुशहाली के रास्ते पर होगा.■

स्वदेशी पर ज्यादा जोर

निजी क्षेत्रों को रिसर्च और डेवलपमेंट में सुविधाएं देने के लिए सरकार खोल रही खजाना. रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण पर ध्यान, लेकिन नीतिगत क्रियान्वयन होगा बड़ी चुनौती

संदीप उन्नीथन

इस बार साल 2022-23 के लिए भारत के रक्षा बजट में 10 फीसद की ठीक-ठाक बढ़ोतरी हुई है और यह 4.78 लाख करोड़ रुपए से 5.25 लाख करोड़ रुपए हो गया है. पिछले साल का रक्षा बजट केवल 1.4 फीसद बढ़ा था. अमेरिका और चीन के बाद भारत का सैन्य बजट दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बजट है, लेकिन क्योंकि इसकी सेना में जनशक्ति अधिक है, इसलिए देश में आधुनिक उपकरणों की तुलना में वेतन और पेंशन पर कहीं अधिक खर्च आता है. भारत के शस्त्रागार में 60 फीसद से अधिक सैन्य हार्डवेयर आयात किया जाता है. निरंतर रक्षा आयात से न केवल बाहरी स्रोतों पर निर्भरता बढ़ती है, बल्कि विदेशी मुद्रा भी बाहर जाती है और विदेशों में उच्च-प्रौद्योगिकी वाली नौकरियों का सृजन भी होता है.

इस साल के रक्षा बजट के रक्षा पूंजी व्यय में एक उछाल देखा गया है—यह 1.35 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 1.52 लाख करोड़ रुपए हो गया है—और यह ऐसा चलन है जो पिछले तीन बजटों से जारी है. सरकार युद्धपोत, लड़ाकू जेट और हॉवित्जर जैसे रक्षा हार्डवेयर खरीदने के लिए खर्च बढ़ा रही है, लेकिन देश में ही खरीदे जाने वाले हार्डवेयर में भी लगातार धीमी वृद्धि कर रही है. पिछले साल, सरकार ने भारतीय उद्योगों से अपनी जरूरतों के 58 फीसद, 70,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीदारी की. इस साल, सरकार की योजना इसे बढ़ाकर 68 फीसद करने की है या रकम के संदर्भ में कहें तो यह 1 लाख करोड़ रूपये होगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 फरवरी को अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से कहा, ''भारत के एमएसएमई सेक्टर को रक्षा पूंजी बजट के लिए 68 फीसद की घरेलू खरीद के आरक्षण से बहुत फायदा होगा.'' घरेलू खरीद से स्थानीय उद्योगों पर बहुत प्रभाव पड़ता है—यह उच्च-प्रौद्योगिकी सेक्टर में रोजगार पैदा करता है, एमएसएमई के लिए माहौल तैयार करता है और देश के भीतर ही अधिक परिष्कृत हार्डवेयर तैयार करने का कौशल विकसित होता है. सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के अध्यक्ष एस.पी. शुक्ला कहते हैं, ''घरेलू उद्योगों के लिए पूंजीगत व्यय से निवेश बना रहेगा और नई क्षमता का निर्माण होगा.'' इस तरह,

आसमान पर नजर

भारतीय स्टार्ट-अप आइडियाफोर्ज की ओर से निर्मित बहुत ऊंचाई पर तैनात होने वाला ड्रोन स्विच. इसे भारतीय सेना ने लद्दाख में तैनात किया है

10% की वृद्धि हुई है रक्षा बजट में बीते साल के मुकाबले. 4.78 लाख करोड़ रु. से बढ़कर यह 5.25 लाख करोड़ रु. हुआ

स्वदेशी पर निगाह

रक्षा के लिए पूंजी परिव्यय का 68 % मेक इन इंडिया के लिए अलग रखा गया

असर: स्थानीय खरीद का स्थानीय उद्योगों, सीडिंग इकोसिस्टम और घरेलू बाजार में रोजगार पैदा करने पर अच्छा असर पड़ता है

रक्षा अनुसंधान एवं विकास बजट का 25 % निजी उद्योगों, स्टार्ट-अप और अकादमिक कार्यों के लिए निर्धारित

असर: प्रौद्योगिकी विकास को आगे बढ़ाने वाले रक्षा स्टार्ट-अप और एमएसएमई के लिए पूंजी तक पहुंच की बाधा दूर होगी

रक्षा प्रणालियों और प्लेटफार्मों के परीक्षण तथा प्रमाणन की स्थापना के लिए नोडल निकाय

असर: रक्षा नवाचारों के तेज प्रोसेसिंग को सक्षम बनाएगा और उपकरणों को योग्य बनाने में निजी अनुसंधान और विकास की व्यवस्था को मदद करेगा

स्वदेशीकरण पर सरकार का जोर बड़े बजटीय लक्ष्यों के साथ पूंजीगत खर्च को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लक्ष्य के लिए मुफीद बैठता है.

वैसे, सरकार की आत्मनिर्भर नीति के लिहाज से अभी भी अगले दशक तक स्वदेशी उत्पादन शुरू करने के लिए स्पष्ट रोडमैप मौजूद नहीं है. रक्षा मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं, ''रक्षा अधिग्रहण परिषद जैसी एजेंसी की ओर से स्वदेशीकरण के लक्ष्यों की कड़ी निगरानी होनी चाहिए.'' फिलहाल, ऐसा कोई निकाय अस्तित्व में नहीं है.

स्वदेशी खरीद का फैसला रक्षा के मामले में आत्मनिर्भर होने पर जोर देने का हिस्सा है जिसे मई 2020 में शुरू किया गया था. प्रधानमंत्री कार्यालय की निगरानी में चल रही इस कोशिश में मौजूदा वक्त में स्वदेशी रक्षा उद्योग के दो स्तंभों को मजबूत किया जा रहा है—सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रम और निजी उद्योग. स्व-चालित तोपखाने और मिसाइलों जैसे बड़े उपकरणों के ऑर्डर को टियर 1 उद्योगों से पूरा किया जा सकता है, लेकिन सरकार को ड्रोन और मानव-रहित सिस्टम जैसे विशिष्ट क्षेत्रों में स्टार्ट-अप को सहारा देने की जरूरत है. इन्हीं क्षेत्रों में बजट ने बड़े कदम उठाए हैं—इसने रक्षा अनुसंधान और विकास संस्थान (डीआरडीओ) के 11,981 करोड़ रुपए के बजट का 25 फीसद हिस्से को निजी उद्योगों, स्टार्ट-अप और अकादमिक क्षेत्रों के लिए अलग रख दिया है. डीआरडीओ के चेयरमैन जी. सतीश रेड्डी कहते हैं, ''देश के अनुसंधान और विकास आधार का विस्तार सभी हितधारकों—अकादमिक, आरऐंडडी संगठन और उद्योग—के साथ समन्वयकारी नजरिए के साथ किया जा सकता है. यह देश के भीतर एडवांस्ड सिस्टम के विकास और निर्यात के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है.'' इस कदम का स्वागत करते हुए भारत फोर्ज के प्रबंध निदेशक बाबा कल्याणी कहते हैं कि इससे ''फ्रंटियर टेक्नोलॉजी और क्षमता विकास में निवेश का मार्ग प्रशस्त होगा.''

सरकार ने रक्षा प्रणालियों और प्लेटफार्मों के परीक्षण और प्रमाणन की स्थापना के लिए एक नोडल निकाय स्थापित करने के अपने इरादों की भी घोषणा की, ताकि निजी डेवलपर्स अपने रक्षा नवाचारों का जल्दी परीक्षण कर सकें. सरकार ने 'मेक' श्रेणी के तहत रक्षा मंत्रालय की खरीद के लिए सैन्य हार्डवेयर प्रोटोटाइप विकसित करने के वास्ते 1,365 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं.

प्रतिरक्षा के क्षेत्र में स्टार्ट-अप को फंड देने का विचार नया नहीं है. तीन साल पहले डीआरडीओ ने 'टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड' स्थापित किया था ताकि प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके. डीआरडीओ ने अब तक 164 करोड़ रुपए का फंड 2,611 कंपनियों के लिए मंजूर किया है, नतीजतन 150 प्रौद्योगिकियों के डिजाइनिंग पर काम चालू है. 2018 में शुरू की गई इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस (आइ-डेक्स) जैसी अन्य पहलें उतनी सफल नहीं रही हैं. आइ-डेक्स का मकसद एमएसएमई स्टार्ट-अप्स, आरऐंडडी संस्थानों और शिक्षाविदों की मदद करना था. चार साल बाद, अभी तक किसी भी अत्याधुनिक तकनीक को सफलतापूर्वक तैनात नहीं किया जा सका है और इसके कोई भी उत्पाद फील्ड परीक्षण स्तर तक नहीं पहुंचा है.

यही वजह है कि डीआरडीओ संचालित मॉडल को सरकार का समर्थन मिला है. शीर्ष रक्षा अधिकारियों का कहना है कि सरकार अमेरिकी रक्षा विभाग की डिफेंस एडवान्स्ड रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी (डीएआरपीए) की तर्ज वाले मॉडल के पक्ष में है. अगर यह मॉडल काम कर जाता है, तो डीआरडीओ उन्नत तकनीकों वाले रक्षा उपकरणों मसलन एयरक्राफ्ट के इंजनों और हाइपरसोनिक हथियारों पर ध्यान केंद्रित करेगा और आला किस्म की प्रौद्योगिकियों को भारतीय उद्योगों पर छोड़ा जाएगा. डीआरडीओ विकास सह उत्पादक साझीदार (डीसीपीपी) पर जोर दे रहा है, इससे निजी क्षेत्र भी मिसाइल सिस्टम के विकास में भागीदार हो सकेगा और साथ ही उसका निर्माण भी कर सकेगा. एजेंसी प्रौद्योगिकी और पेटेंट का हस्तांतरण निजी क्षेत्र को मुफ्त में करेगा और स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देगा.

पांचवी पीढ़ी के एडवान्स्ड मीडियम लड़ाकू जहाजों का डिजाइन डीआरडीओ में तैयार हो रहा है और यह विशेष उद्देश्यों वाला विमान होगा जिसमें डीआरडीओ, एचएएल और दो निजी कंपनियां शामिल हैं और इसमें 75 फीसद फंडिंग सरकार से होगी. रक्षा मंत्रालय में यह बदलाव की बयार है, पर अभी यह देखना बाकी है कि यह कितना असरदार साबित होगा. ■

''देश के अनुसंधान और विकास आधार का विस्तार सभी हितधारकों अकादमिक, आरऐंडडी संगठन और उद्योग के साथ समन्वयकारी नजरिए के साथ किया जा सकता है. देश के भीतर एडवांस्ड सिस्टम का विकास करने और निर्यात के लिहाज से भी यह बहुत महत्वपूर्ण है''

—जी. सतीश रेड्डी

चेयरमैन, डीआरडीओ

1% राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटन में बढ़ोतरी, 2021-22 में 36,576 करोड़ रु. से बढ़ा कर बजट 2022-23 के लिए 37,000 करोड़ रु. किया गया

सेहत को नहीं मिली बूस्टर डोज़

महामारी का दौर जारी रहने और स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती जरूरतों के बावजूद, इस क्षेत्र को कम प्रोत्साहन मिला है

अमरनाथ के. मेनन

दूसरी लहर में 2,00,000 से अधिक मौतों का कारण बनी कोविड महामारी के हमले के मद्देनजर स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लिए जितने धन की अपेक्षा थी, 2022-23 के बजट में इस क्षेत्र के लिए उससे बहुत कम धन दिया गया है. रु. 86,200.65 करोड़ के साथ वित्त वर्ष 2023 के लिए बजट अनुमान पिछले साल के 73,932 करोड़ रुपए के मूल बजट अनुमान से लगभग 12,000 करोड़ रुपए अधिक है, लेकिन यह वित्त वर्ष 2022 के संशोधित अनुमान रु. 86,000.65 करोड़ से सिर्फ 200 करोड़ रुपए अधिक है. सरकारी बजट में स्वास्थ्य सेवा को दी गई प्राथमिकता के आधार पर भारत दुनिया के 189 देशों में 179वें स्थान पर है.

बजट प्रस्तावों का उज्ज्वल पक्ष यह है कि नेशनल इंस्टीट्यूट आफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस, बेंगलूरू के माध्यम से एक राष्ट्रीय टेलीमेंटल स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू किया जाएगा. एशियन फेडरेशन ऑफ साइकियाट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉ. जी. प्रसाद राव कहते हैं, ''महामारी (कोविड) के कारण पैदा हुई प्रच्छन्न वैश्विक मानसिक स्वास्थ्य महामारी को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए 23 केंद्रों वाले राष्ट्रीय नेटवर्क की स्थापना की बात स्वागत योग्य कदम है.'' विशिष्ट स्वास्थ्य पहचान सहित डिजिटल स्वास्थ्य पहलों को प्रोत्साहन देने के लिए, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को एक खुले मंच के रूप में स्थापित किया जाएगा. इसमें स्वास्थ्य सुविधाओं की डिजिटल रजिस्ट्रियां होंगी.

हालांकि स्वास्थ्य देखभाल पर सार्वजनिक व्यय अपेक्षाओं से बहुत कम है. वर्ष 2022-23 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए आवंटन केवल एक प्रतिशत बढ़ाकर 37,000 करोड़ रुपए किया गया. सिंगल स्पेशियलिटी हेल्थकेयर पर केंद्रित एक ऑपरेटिंग और निवेश प्लेटफॉर्म, एशिया हेल्थकेयर होल्डिंग्स के कार्यकारी अध्यक्ष विशाल बाली कहते हैं, ''स्वास्थ्य पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि के बारे में बजट में कुछ नहीं कहा गया है जबकि भारत भर में स्वास्थ्य सेवा में सुधार के लिए इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है.''

कॉन्टिनेंटल हॉस्पिटल्स, हैदराबाद के चेयरमैन और एमडी, डॉ. गुरु एन. रेड्डी के अनुसार, भारत लंबे समय से स्वास्थ्य सेवाओं पर जरूरत से कम खर्च कर रहा है. उनका कहना है कि ''इस दौर में सकल घरेलू उत्पाद के 3 प्रतिशत से जरा भी कम आवंटन तकलीफदेह साबित होगा. जाहिर है हम कष्ट उठाते रहेंगे. स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए मामूली बजटीय आवंटन के साथ कोई भी विकासशील देश विकसित नहीं हो सका.'' रेड्डी का सुझाव है कि सभी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशनों को अनुभवी निजी निकायों को सौंपा जाए और प्रभावी कार्यान्वयन के लिए विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए.

चिकित्सा उपकरण क्षेत्र इस बात से निराश है कि सरकार ने जिन सुधारों का वादा किया था, उन पर आगे नहीं बढ़ी है. एसोसिएशन ऑफ इंडियन मेडिकल डिवाइस के फोरम कोऑर्डिनेटर राजीव नाथ कहते हैं, ''(उपकरणों के लिए)80-85 प्रतिशत आयात निर्भरता और भारत के लगातार बढ़ते आयात बिल को समाप्त करने में मदद करने वाले किसी उपाय की घोषणा नहीं की गई है.''

स्वास्थ्य देखभाल की बढ़ती लागतों को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि राज्य संचालित स्वास्थ्य योजनाओं से बाहर के वर्गों में आने वालों और नागरिकों को सब्सिडी के जरिये निजी बीमा के तहत लाना चाहिए. हर कर्मचारी के लिए बीमा कवर अनिवार्य कराने की जरूरत है.■

ग्राफिकः तन्मय चक्रवर्ती

स्वास्थ्य पर खर्च

सार्वजनिक स्वास्थ्य खर्च (केंद्रीय व राज्यों का कुल व्यय) 2008-09 से सकल घरेलू उत्पाद के 1.2 फीसद से 1.6 फीसद के बीच बना हुआ है. साल दर साल इसमें मामूली बढ़ोतरी ही देखी गई है

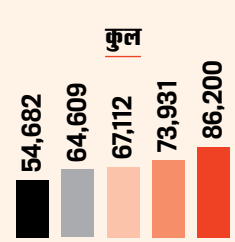

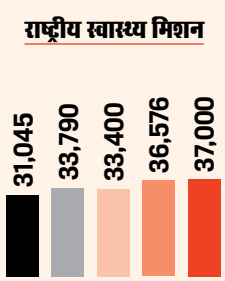

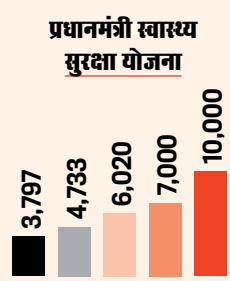

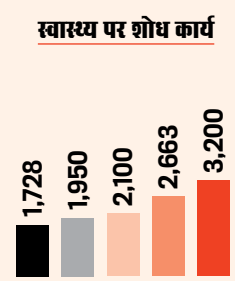

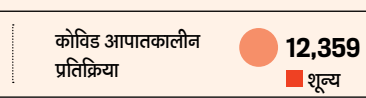

वास्तविक 19 संशोधित अनुमान 20 बजट अनुमान 21 बजट अनुमान 22 बजट अनुमान 23

**सभी आंकड़े करोड़ रु. में, स्रोतः बजट दस्तावेज*

उर्वर भूमि
अमृतसर में सरसों का खेत

एएफआइ

3.1%

हिस्सा कुल बजट का, कृषि को आवंटित किया गया है

422%

वृद्धि हुई है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के आंवटन में

कृषि पर हल्का हाथ

कृषि आय दोगुनी करने की अब कोई चर्चा नहीं, हरित खेती पर जोर देना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य के स्पष्ट रोडमैप के बगैर इस क्षेत्र को रियायतें जारी रहेंगी

अनिलेश एस. महाजन

जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी कृषि सुधारों को कानून वापसी के साथ पीछे हटना पड़ा, तो हर किसी को उम्मीद थी कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस दिशा में बजट के जरिए नई कोशिश करेंगी. बहरहाल, वित्त मंत्री के बजट भाषण में कृषि में सुधार के लिए तकनीक के प्रयोग की चर्चा थी, जिसमें ड्रोन का इस्तेमाल और रसायनमुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाना शामिल था और खास जोर गंगा के साथ लगे पांच किलोमीटर के दायरे के गलियारों पर था—लेकिन, उन्होंने किसानों की आय दोगुनी करने की बात को दोहराया नहीं.

हालांकि, बजट के कृषि प्रस्ताव बेहतर लग सकते हैं, लेकिन उनका असर देश के 20 करोड़ किसानों में से एक फीसद से भी कम पर पड़ने वाला है. दूसरी बात, किसानों की मदद के लिए बनीं सरकारी एजेंसियों में संस्थागत सुधारों की कमी के कारण पहले से ही जैविक और प्राकृतिक खेती का उपयोग करने वाले किसान अभी भी संघर्ष कर रहे हैं. खेती विरासत मंच के कार्यकारी निदेशक उमेंद्र दत्त कहते हैं, ''इन घोषणाओं के पीछे नीयत अच्छी है लेकिन संस्थाओं को किसानों, वैज्ञानिकों, कार्यकर्ताओं और अन्य संबंधित हितधारकों के बीच संवाद विकसित करना चाहिए.''

अपने बजट भाषण में, वित्त मंत्री सीतारमण ने कुल खर्च का 3.1 फीसद हिस्सा—1.24 लाख करोड़ रुपए—कृषि और किसान कल्याण विभाग को आवंटित किया है. इनमें तीन योजनाओं की लागत करीब 1.03 लाख करोड़ रुपए है—पीएम किसान (करीब 68,000 करोड़ रुपए), अल्पकालिक ऋणों पर ब्याज की मदद (करीब 19,500 करोड़ रुपए) और फसल बीमा (15,500 करोड़ रुपए) है. सीतारमण ने राज्य सरकारों को कृषि विश्वविद्यालयों को प्राकृतिक जीरो-बजट और ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने के लिए पाठ्यक्रमों में सुधार करने को भी कहा है. परंपरागत कृषि विकास योजना को, जिसका मकसद ऑर्गेनिक किसानों को मदद उपलब्ध कराना है, इस साल अधिक बजट नहीं मिल पाया है, फिर भी वित्त मंत्री ने करीब 198 करोड़ रुपए पूर्वोत्तर भारत में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए आवंटित किए हैं.

इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, बजट निजी निवेश के लिए कोई रोडमैप नहीं पेश करता. कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड में भी कटौती की गई है, जिसका मकसद खेती से जुड़े बुनियादी ढांचे का विकास था. साल 2021-22 में, केंद्र ने इस मद में 900 करोड़ रु. का आवंटन किया था और 2022-23 में सीतारमण ने इसके लिए 500 करोड़ रुपए ही दिए हैं. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के आवंटन में 422 फीसद का इजाफा हुआ है और इसे 2,000 करोड़ रु. से बढ़ाकर 10,433 करोड़ रुपए कर दिया गया है. यह योजना राज्य सरकारों को इस बात की आजादी देती है कि वे इस योजना के तहत वृहत आवंटनों में अपनी प्राथमिकताएं तय कर सकें और इससे राज्य सरकारें स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर बदलाव कर सकती हैं. हाल के वर्षों में केंद्र इस योजना में आवंटन कम कर रहा था, लेकिन इस साल मामला उलट गया.

इसी तरह, 7,183 करोड़ रुपए के बजट के साथ कृषि उन्नति योजना को फिर से शुरू किया गया है. साल 2016-17 में, इसमें 7,580 करोड़ रुपए के बजट के साथ 10 योजनाएं शामिल थीं. इस साल के बजट में इसमें 10 अलग योजनाओं को शामिल किया गया है. वनस्पति तेलों के घरेलू उत्पादन और प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के मकसद से इस फंड का करीब 21 फीसद हिस्सा पाम, तिलहन और खाद्य तेलों के लिए रखा गया है. ■

आसमां के नीचे
दिल्ली में एक पुल के तले चलती गरीब बच्चों की क्लास

अमरजीत कुमार सिंह/गेट्टी इमेजेज

उजियारा फैलाने के कुछ बड़े उपाय

शिक्षा बजट में ई-विद्या स्कीम पर खासा जोर दिया गया है. पर क्या इससे समर्थ-असमर्थ के बीच की खाई पट सकेगी?

शैली आनंद

शिक्षा क्षेत्र के लिए बजट 2022-23 की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्वीकारा कि महामारी के असर से स्कूल बंद होने के कारण विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर तबके के बच्चे दो साल से औपचारिक शिक्षा नहीं पा सके हैं. उन्होंने ऐलान किया कि ''सभी तक शिक्षा पहुंचाने का लचीला तंत्र बनाने के लिए पीएम ई-विद्या स्कीम के 'एक कक्षा-एक टीवी चैनल' कार्यक्रम को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनलों तक ले जाया जाएगा. इससे सभी राज्य कक्षा 1 से 12 तक की पूरक शिक्षा क्षेत्रीय भाषाओं में मुहैया करने में सक्षम होंगे.''

तालीम में एक बड़ी खाई को पाटने के लिए डिजिटल शिक्षा को संभव बनाने पर विशेष जोर देते हुए वित्त मंत्री ने शिक्षा क्षेत्र के लिए वित्तीय आवंटन में 11.9 फीसद वृद्धि का ऐलान किया. इससे 2021-22 में 93,234 करोड़ रु. का बजट 2022-23 में 1.04 लाख करोड़ रुपए का हो गया. वित्त मंत्री ने गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक शिक्षा और स्किल्ड ई-प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किए जाने की भी घोषणा की.

1.04 लाख करोड़ रु.
आवंटित किए गए हैं 2022-23 के बजट में, शिक्षा क्षेत्र के लिए. पहले से 11.9% ज्यादा

10,233.7 करोड़ रु.
का फंड 2022-23 में पीएम पोषण (मिड-डे मील का बदला नाम) योजना के लिए आवंटित. यह पिछले साल के मुकाबले 750 करोड़ रुपए कम है

बजट में 'एक कक्षा, एक टीवी चैनल' कार्यक्रम का विस्तार करने के फैसले ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा है. मूल रूप से मई 2020 में शुरू की गई इस पहल को विस्तार दिए जाने से हर राज्य समर्पित टीवी चैनलों के जरिए क्षेत्रीय भाषाओं में कक्षाएं आयोजित कर सकेगा. इन चैनलों पर पूरे पाठ्यक्रम को स्कूल की तरह ही कवर किया जाएगा और हर विषय की कक्षा की अपनी टाइमिंग और क्यूआर-कोडेड किताबें होंगी. अभी एनसीईआरटी और अन्य शैक्षणिक एजेंसियों की ओर से तैयार 12 चैनल (1 से 12 तक हर कक्षा के लिए) हिंदी और अंग्रेजी में पाठ्यक्रम-आधारित शैक्षिक सामग्री का प्रसारण करते हैं. इनके लिए छात्रों को इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है और वे अन्य टीवी चैनलों की तरह ही इस सामग्री को देख-सुन सकते हैं.

बुनियादी ढांचे के रूप में इंटरनेट सुविधाओं की कमी और डिजिटल प्रौद्योगिकी से शिक्षकों-छात्रों के अल्प परिचय को देखते हुए महामारी भारत की शिक्षा व्यवस्था के लिए बड़ा झटका साबित हुई है और स्कूल जाने वाले, खासकर ग्रामीण इलाकों के बच्चे इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं. सुचित्रा अकादमी के संस्थापक तथा फिक्की अराइज के सह-अध्यक्ष प्रवीण राजू कहते हैं, ''ई-विद्या कार्यक्रम का सबसे सराहनीय हिस्सा उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा सामग्री है, जो टीवी के अलावा मोबाइल फोन, लैपटॉप और रेडियो से भी ग्रहण की जा सकती है. इससे उन अविकसित क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों को लाभ होगा जहां ऑनलाइन शिक्षा अभी भी एक सपना है. किसी भी छात्र को न छोड़ने के आदर्श वाक्य के साथ सभी भाषाओं में ई-सामग्री को छात्रों तक पहुंचाया जाएगा.

बजट की कुछ आलोचना भी हुई है. लड़कियों को प्रोत्साहित करने की राष्ट्रीय योजना तथा अनुसूचित जाति/जनजाति समुदायों और ग्रामीण क्षेत्रों की छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति योजना को इस वर्ष कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है. इसी तरह, वयस्कों की बुनियादी साक्षरता योजना, 'पढ़ना लिखना अभियान' को भी कोई रकम नहीं दी गई है. इससे भी बड़ी बात, प्रधानमंत्री पोषण (मिड-डे मील योजना का नया नाम) योजना की रकम में भी कटौती हुई है. इस मद में पिछले साल की तुलना में 750 करोड़ रु. कम, कुल 10,233.7 करोड़ रु. ही दिए गए हैं.■

कुंदन
नंदवानी

क्रिप्टो को मिली कुछ मान्यता

महीनों की शंका-आशंकाओं के बाद क्रिप्टोकरेंसी ने आखिरकार बजट 2022 में पहुंचने का रास्ता बना ही लिया. जाहिर है, इसने मिली-जुली प्रतिक्रियाओं को न्यौता दिया है. भारत ने क्रिप्टो को अपनाने में हाल में काफी उछाल आता देखा और इस मामले में वह वैश्विक अगुआ बन गया. मगर फिर भी अभी कई ऐसे धुंधलके हैं जिनसे निवेशकों को चौकन्ना रहना चाहिए.

सरकार ने एक नया परिसंपत्ति वर्ग परिभाषित किया है—वर्चुअल डिजिटल एसेट—जिसमें क्रिप्टोकरेंसी और नॉन-फंजिबल टोकन (एनएफटी) शामिल हैं. इसके दो प्रमुख निहितार्थ हैं. पहला क्रिप्टोकरेंसी को अलग से परिभाषित न करके केंद्र ने करेंसी या मुद्रा के रूप में उसके गुण-दोषों पर विचार नहीं किया. मगर करेंसी होना ही तो वह प्राथमिक कारण था जिससे बिटकॉइन सरीखे टोकन बनाए गए थे. सरकार ने साफ कर दिया है कि वह क्रिप्टोकरेंसी को भारतीय रुपए के समकक्ष हैसियत नहीं दे सकती. दूसरा यह कि वर्चुअल डिजिटल एसेट या परिसंपत्ति की परिभाषा इतनी व्यापक है कि इसमें टोकन, कॉइन, रिवार्ड पॉइंट, क्रेडिट कार्ड पॉइंट, फंजिबल टोकन वगैरह आ सकते हैं. मसलन क्रेड अपने यूजर को क्रेड पॉइंट के जरिए प्रोत्साहन लाभ देने के लिए मशहूर हैं. सरकार की परिभाषा के हिसाब से चलें, तो इन्हें भी वर्चुअल डिजिटल एसेट की श्रेणी में रखा जा सकता है.

सरकार ने तमाम वर्चुअल डिजिटल एसेट पर, उनका स्वरूप छोटे वक्त का हो या लंबे वक्त का, 30 फीसद कर वसूलने का फैसला किया है. यही नहीं, उसने स्पष्ट किया है कि क्रिप्टोकरेंसी पर होने वाले घाटे की भरपाई किसी अन्य परिसंपत्ति या कारोबार के मुनाफे से नहीं की जा सकती. अगर आप नियमित स्टॉक मार्केट ट्रेडर हैं, तो सामान्यत: एक शेयर से हुए घाटे की भरपाई दूसरे शेयर पर हुए मुनाफे से कर सकते हैं. पेशेवर ट्रेडर होने के नाते आप बाजार से होने वाले घाटे की भरपाई ऐसे किसी दूसरे कारोबार से कर सकते हैं जिसके आप मालिक हों. क्रिप्टोकरेंसी के मामले में सरकार ने ऐसी लिखत-पढ़त के दरवाजे बंद कर दिए हैं. लोगों से उम्मीद की जाती है कि घाटे सहें और वह भी उनके अगले मुनाफे से घाटा की भरपाई के विकल्प के बगैर. यह और इसके साथ कर की ऊंची दर कुछ निवेशकों को हतोत्साहित करने के लिए काफी है.

दूसरा अवरोधक कारक एक फीसद टीडीएस

हालांकि अब ट्रेडिंग पर टैक्स लगाया जा रहा है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि क्रिप्टोकरेंसी वैध हो गई. प्रस्तावित क्रिप्टो बिल में यह साफ कर दिया जाएगा

है जो तमाम लेन-देन पर वसूला जाएगा—यहां तक कि अगर आप एसेट एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ले जा रहे हों तब भी कीमत चुकानी होगी. डिजिटल एसेट की मुख्य खूबी यह है कि लेन-देन मुफ्त और तुरत-फुरत है, पर टीडीएस की वजह से लोग लेन-देन करते हुए दो बार सोचेंगे. कर लगने से हो सकता है कुछ छोटे निवेशक क्रिप्टो के काफिले में शामिल होने से बिदक जाएं, जबकि दूसरों के लिए कई चीजें साफ होंगी. संभावना यह भी है कि लोग टैक्स से बचने के रास्ते खोज लें, जिससे और परेशानियां पैदा हों.

बहुत सारे लोग यह सोचकर उछल पड़े कि क्रिप्टोकरेंसी पर कर लगने से इस एसेट को कानूनी वैधता मिल गई. क्रिप्टोकरेंसी को वैध या आपराधिक ठहराने वाला क्रिप्टो विधेयक अभी नहीं आया है, लेकिन इससे कर लगाने का सरकार का अधिकार नहीं छिन जाता. असल में, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी सरकार को गैरकानूनी आमदनी पर कर लगाने दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ कहा कि वर्चुअल एसेट पर कर लगाने का यह जरा भी मतलब नहीं कि उन्हें वैधता दे दी गई है. वैधता के मुद्दे से प्रस्तावित क्रिप्टोकरेंसी विधेयक में निबटा जाएगा. भारतीय रिजर्व बैंक का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि करेंसी या मुद्रा केवल केंद्रीय बैंक ही जारी कर सकता है, फिर भले वह क्रिप्टोकरेंसी ही क्यों न हो. निजी क्षेत्र में जारी टोकन, भले ही उन्हें करेंसी कहा जाता हो, इस वजह से करेंसी नहीं हो जाते. उन्होंने साफ किया कि खरीद-फरोख्त हो ही रही थी और क्रिप्टोकरेंसी से मुनाफा कमाया जा रहा था, तो उन्हें कर तो लगाना ही था.

सरकार ने ऐलान किया है आरबीआइ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित डिजिटल मुद्रा लाएगा. आरबीआइ की तरफ से जारी डिजिटल मुद्रा की प्रेरणा कहां से मिली, यह अब भी साफ नहीं है. ऐसी मुद्रा भारतीय पारितंत्र में कोई मूल्य संवर्धन नहीं भी कर सकती है. इसकी दो वजहें हैं. पहली, अगर मुद्रा केंद्रीयकृत और आरबीआइ के हाथों नियंत्रित होगी, तो इसे क्रिप्टोकरेंसी नहीं कहा जा सकता. क्रिप्टोकरेंसियों की पहचान ही यह है कि वे विकेंद्रीकृत हैं. उसे कोई एक पक्ष नियंत्रित नहीं कर सकता. दूसरे, अगर डिजिटल मुद्रा का मकसद डिजिटल भुगतान का विकल्प देना है, तो नई मुद्रा लॉन्च करना जरूरी नहीं है—वह तो यूपीआइ के जरिए किया ही जा रहा है और पेटीएम, गूगल पे, फोनपे वगैरह उसे बढ़ा रहे हैं. लिहाजा भारत की अपनी डिजिटल मुद्रा के बारे में अभी काफी स्पष्टता आना बाकी है.

कुंदन नंदवानी यूट्रेड सॉल्यूशंस के सह-संस्थापक और सीईओ हैं

विधानसभा चुनाव 2022

उत्तर प्रदेश

चेहरा बदलती मुस्लिम सियासत

ध्रुवीकरण रोकने की कोशिश में सियासी दलों ने इस बार विवादास्पद नेताओं से परहेज करते हुए नए और युवा चेहरों को बनाया उम्मीदवार. इससे समुदाय के भीतर नए सियासी रहनुमा उभरने की उम्मीद

आशीष मिश्र

रामपुर में जिला जेल के पीछे मौजूद मौलाना अबुल कलाम आजाद पार्क के बगल से जाने वाली संकरी गली सफेद रंग की कोठी की तरफ ले जाती है. कोठी के मालिक रामपुर के सांसद समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान विभिन्न मामलों में दर्ज तीन दर्जन से अधिक मुकदमों के चलते पिछले 23 महीने से जेल में बंद हैं. यह पहला मौका है जब आजम खान जेल में रहकर रामपुर से सपा प्रत्याशी के तौर पर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं. आजम के जेल में रहने के बावजूद कड़कती सर्दी और कोहरे को भेदते हुए समर्थक सुबह आठ बजे से कोठी के बाहर जमा होने लगते हैं. कोठी की बगल में एक बड़े हॉल को 'बैठक' नाम दिया है. 'बैठक' की दीवारें आजम खान की तस्वीरों से पटी पड़ी हैं. सुबह ठीक दस बजे अब्दुल्लाह आजम खान 'बैठक' में पहुंचते हैं और अपने वालिद की तरह एक-एक समर्थक के पास जाकर उसका हाल-चाल पूछते हैं. 31 साल के इंजीनियर अब्दुल्लाह भी अपने वालिद के साथ जेल में बंद थे और दो हफ्ते पहले ही रिहा हुए हैं. सपा ने रामपुर की स्वार टांडा सीट से अब्दुल्लाह को उम्मीदवार बनाया है. उन्होंने अपनी विधानसभा सीट के साथ अपने वालिद के चुनाव क्षेत्र में प्रचार की कमान संभाल ली है. कोठी में कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद अब्दुल्लाह रोज दोपहर 12 बजे रामपुर में बाब-ए-इल्म रोड पर मौजूद सपा कार्यालय पहुंच जाते हैं. आजम खान ने दारुल अवाम के नाम से मशहूर हाइटेक सपा कार्यालय का निर्माण 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले कराया था. पार्टी कार्यालय के हर कमरे में उन्हें और उनके परिवार को साजिश के तहत जेल में बंद किए जाने और उन्हें रिहा करने की मांग करते बड़े-बड़े पोस्टर नुमायां हैं. अब्दुल्लाह के सपा कार्यालय पहुंचते ही सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता उन्हें घेर लेते हैं. कई लोगों के हाथों में गुलाबी रंग के कागज में भेजी गई नोटिस है. प्रशासन ने भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 149 के तहत जारी 'रेड कार्ड' के जरिए इन लोगों पर चुनाव के दौरान गड़बड़ी की आशंका जाहिर की है. आजम खान की तरह अब्दुल्लाह भी कार्यकर्ताओं से अपना रिश्ता जोड़ते हुए उन्हें प्रशासन की इस एकतरफा कार्रवाई का विरोध करने का भरोसा दिलाते हैं. वे तुरंत कार्यालय में मौजूद स्टाफ को प्रशासन की विद्वेष पूर्ण कार्रवाई की जानकारी देता शिकायती पत्र तैयार करने का निर्देश देते हैं ताकि उसे फौरन चुनाव आयोग को भेजा जा सके. अब्दुल्लाह आरोप लगाते हैं, ''मुरादाबाद के कमिशनर आंजनेय कुमार सिंह ने रामपुर का जिलाधिकारी रहते हुए आजम साहब और परिवार को झूठे मुकदमों में फंसाया और अब चुनाव के दौरान सपा कार्यकर्ताओं को परेशान करने के पीछे उनका ही हाथ है.'' करीब एक घंटा सपा कार्यालय में रहने के बाद अब्दुल्लाह अपने चुनाव क्षेत्र

आजम खान और नाहीद हसन जैसे लोकप्रिय नेता विभिन्न मुकदमों में जेल में बंद हैं. उनके समर्थकों का मानना है कि उन्हें बेजा परेशान किया जा रहा है

सभी फोटोः मनीष अग्निहोत्री

नई नस्ल आजम खान के बेटे अब्दुल्लाह आजम खान (बाएं), और रामपुर की स्वार टांडा विधानसभा सीट से अपना दल (एस) उम्मीदवार हमजा मियां लखीमपुर गांव में सभा करते हुए

स्वार टांडा की ओर निकल पड़ते हैं. अपने चुनाव क्षेत्र में छह घंटे जनसंपर्क करने के बाद वे रामपुर लौट आते हैं और रात 12 बजे तक मतदाताओं के दरवाजे जाकर उनसे अपने वालिद के लिए वोट मांगते हैं. मुस्लिम आबादी बहुल रामपुर में मतदाता अब्दुल्लाह में आजम खान का अक्स देखते हैं और भारी बहुमत से जिताने का भरोसा भी दिलाते हैं.

रामपुर में आजम खान की गैरमौजूदगी में अब्दुल्लाह आजम के रूप में एक युवा सियासी चेहरे का उभार हो रहा है तो यहां से साढ़े तीन सौ किलोमीटर दूर शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट पर एक बहन अपने भाई की राजनैतिक विरासत बचाने मैदान में कूद पड़ी है. यह हैं 28 वर्षीया इकरा हसन जो जेल में बंद और कैराना विधानसभा सीट से सपा उम्मीदवार नाहीद हसन के चुनाव प्रचार में दिन-रात एक किए हुए हैं. इकरा कैराना से सांसद रहे मरहूम मुनव्वर हसन की बेटी और दो बार विधायक रहे नाहीद की बहन हैं. इकरा दिल्ली के लेडी श्रीराम कॉलेज से कानून की पढ़ाई करने के बाद इंटरनेशनल लॉ का अध्ययन करने लंदन चली गई थीं. दिसंबर, 2019 में लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग के सामने नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) का विरोध करके वे चर्चा में आई थीं. इकरा पश्चिमी यूपी के एक बड़े राजनैतिक खानदान से ताल्लुक रखती हैं. 1984 के लोकसभा चुनाव में इकरा के दादा अख्तर हसन ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने वाली वर्तमान में बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती को दो लाख से अधिक मतों से हराया था. अख्तर हसन के बेटे और इकरा के पिता मुनव्वर हसन ने पश्चिमी यूपी की मुस्लिम राजनीति में बड़ा नाम कमाया. वे लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधानपरिषद, चारों सदनों के सदस्य रहे. 2008 में एक हादसे

विधानसभा में कमजोर हुई मुस्लिम नुमाइंदगी

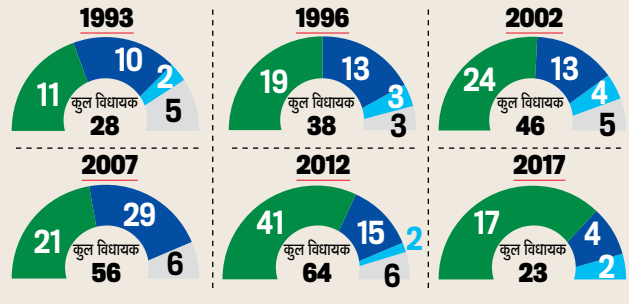

नोटः स्रोत-निर्वाचन आयोग. 1993 से अबतक हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी के पास कोई भी मुस्लिम विधायक नहीं रहा है. वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने 99, सपा ने 57, कांग्रेस ने 22 मुस्लिम उम्मीदवारों को उतारा था.

ग्राफिकः असित रॉय

में मुनव्वर हसन की मौत होने के बाद इकरा की मां तबस्सुम हसन सांसद बनीं. फिर उनके बेटे नाहीद हसन दो बार कैराना से विधायक बने. वर्ष 2015 में इकरा शामली में जिला पंचायत सदस्य भी निर्वाचित हुई थीं. नाहीद पर 17 मुकदमे दर्ज हैं. उन्हें गैंगस्टर ऐक्ट के मुकदमें में उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया जब वे 2022 के विधानसभा चुनाव में कैराना सीट से नामांकन करके लौट रहे थे. भाई की खातिर घर-घर प्रचार करने के लिए इकरा ने दस टोलियां बनाई हैं. एक टोली का नेतृत्व वे स्वयं कर रही हैं. वे बताती हैं, ''नाहीद पर कार्रवाई राजनैतिक द्वेष से प्रेरित है. जनता यह समझ रही है.''

यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव मुस्लिम राजनीति के लिहाज से एक नई शुरुआत करने जा रहा है. पिछले कई चुनावों में अपनी धमक दिखाने वाले मुस्लिम चेहरे इस बार नदारद हैं तो नए युवा नेता इनकी जगह लेने की भरसक कोशिश कर रहे हैं. आजमगढ़ के प्रतिष्ठित शिबली नेशनल कॉलेज के सेवानिवृत्त प्राचार्य ग्यास असद खान बताते हैं, ''भाजपा का विरोध करने वाले राजनैतिक दलों विशेषकर समाजवादी पार्टी ने ऐसे मुस्लिम नेताओं को चुनाव में उतारने से परहेज किया है जो पूर्व में अपने भड़काऊ बयान के चलते विवादों में घिरे थे. राजनैतिक पार्टियों को लगता है कि पूर्व के चुनावों में इनके विवादास्पद बयानों ने ही मुसलमानों के विरोध में हिंदुओं के ध्रुवीकरण की नींव तैयार की थी. इस बार चुनाव में बड़ी संख्या में नए मुस्लिम युवा नेता राजनीति में सक्रिय हुए हैं जो समाज के हर तबके का समर्थन पाने का प्रयास कर रहे हैं. यह मुस्लिम राजनीति में एक बड़ा बदलाव है. इस तरह, 2022 का विधानसभा चुनाव प्रदेश में नई 'मुस्लिम लीडरशिप' को भी जन्म देगा.'' वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही राजनैतिक दलों ने एक बड़ा बदलाव करते हुए नए चेहरों को पार्टी की मुस्लिम सियासत की कमान सौंप दी थी. (देखें बॉक्स)

दिग्गजों के सामने राजनैतिक संकट

विवादों में रहने वाले मुस्लिम नेताओं से राजनैतिक पार्टियों की दूरी ने कई दिग्गजों (देखें बॉक्स) के सामने सियासी संकट भी खड़ा कर दिया है. सहारनपुर में मुस्लिम राजनीति की धुरी रहे इमरान मसूद ने 2014

इस बार दरकिनार हैं ये सियासतदां

इमरान मसूद, 50 वर्ष

पश्चिमी यूपी खासकर सहारनपुर में खासा प्रभाव रखने वाले इमरान मसूद कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष थे. 11 जनवरी को इमरान ने कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल होने की घोषणा की थी. सपा से टिकट नहीं मिलने के बाद इमरान सहारनपुर और शामली में पार्टी का प्रचार कर रहे हैं. वर्ष 2007 में विधायक बने इमरान इसके बाद से कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं

कादिर राणा, 60 वर्ष

वर्ष 2009 के लोकसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर मुजफ्फरनगर से सांसद चुने गए कादिर राणा के कार्यकाल में ही मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था. दंगे के आरोपी कादिर राणा ने पिछले वर्ष अक्तूबर में सपा ज्वाइन की थी. वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा ने कादिर राणा से दूरी बना रखी है. इनके परिवार का कोई सदस्य चुनाव मैदान में नहीं है

याकूब कुरैशी, 63 वर्ष

मेरठ जिले के रहने वाले याकूब कुरैशी पश्चिमी यूपी की मुस्लिम राजनीति में काफी प्रभावी हैं. वर्ष 2002 और 2007 में मेरठ से चुनाव जीतकर कुरैशी विधायक बने थे. 2014 के लोकसभा चुनाव में मुरादाबाद और 2019 में मेरठ से लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन सफलता नहीं मिली. याकूब कुरैशी ने इस बार चुनाव न लड़ने की घोषणा की है

नसीमुद्दीन सिद्दीकी, 62 वर्ष

कभी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के बेहद करीबी होने के कारण वे पार्टी का मुस्लिम चेहरा हुआ करते थे. लोकसभा और विधानसभा चुनाव में टिकट वितरण से लेकर मुसलमानों को बसपा के पक्ष में लामबंद करने की जिम्मेदारी नसीमुद्दीन पर ही थी. अब बसपा छोड़ यूपी कांग्रेस में मीडिया सेल के चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल रहे

शाहिद अखलाक, 52 वर्ष

मेरठ में बसपा के टिकट पर वर्ष 2000 में मेयर और उसके बाद 2004 का लोकसभा चुनाव जीतने वाले शाहिद अखलाक चुनावी रण से दूर हैं. बसपा के टिकट पर मेरठ सीट से 2014 का लोकसभा चुनाव हारने के बाद शाहिद अखलाक ने सपा से नजदीकियां बढ़ाई थीं. परिणामस्वरूप बसपा से निकाल दिए गए थे. फिलहाल किसी पार्टी में नहीं

अहमद हसन, 87 वर्ष

समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के नजदीकी अहमद हसन यूपी विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष हैं. आंबेडकर नगर के रहने वाले अहमद हसन ने पूर्वांचल के मुस्लिम समुदाय में पकड़ रखने के कारण पिछले चुनावों में सपा उम्मीदवारों के चयन में खासी भूमिका निभाई थी. बीमारी के कारण इस बार चुनाव में सक्रिय नहीं

नए कंधों पर मुस्लिम राजनीति का भार

↗ इकबाल कादरी, 64 वर्ष

लखनऊ में प्रतिष्ठित मदरसा बारसिया की स्थापना करने वाले इकबाल कादरी को सपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. जालौन जिले के रहने वाले इकबाल कादरी अखिलेश यादव सरकार में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री थे

↗ शकील नदवी, 51 वर्ष

लखनऊ के प्रतिष्ठित नदवा कॉलेज के छात्र रहे शकील नदवी सपा अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं. उन्नाव जिले के रहने वाले शकील पिछली समाजवादी पार्टी सरकार में राज्य भंडारण निगम के अध्यक्ष थे.

↗ इमरान प्रतापगढ़ी, 45 वर्ष

कांग्रेस कमेटी के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन की जिम्मेदारी शायर इमरान प्रतापगढ़ी को सौंपी गई थी. वे 2019 में कांग्रेस के टिकट पर मुरादाबाद से लोकसभा चुनाव लडे थे

↗ शाहनवाज आलम, 40 वर्ष

यूपी कांग्रेस के अल्पसंख्यक विभाग के चेयरमैन शाहनवाज आलम ने राजनीति की शुरुआत 'आइसा' से की थी. शाहनवाज, फर्जी मुकदमों में जेल में बंद मुसलमानों की रिहाई के लिए बने संगठन 'रिहाई मंच' के मीडिया प्रभारी थे

↗ फैजान खान, 38 वर्ष

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्रनेता रहे फैजान खान को बसपा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया है. वे बसपा का युवा मुस्लिम चेहरा हैं. गाजीपुर के रहने वाले फैजान लखनऊ मंडल में बसपा के कोऑर्डिमनेटर भी हैं

↗ मुनकाद अली, 52 वर्ष

बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पश्चिमी यूपी में पार्टी का मुस्लिम चेहरा रहे मुनकाद अली को विधानसभा चुनाव की घोषणा से पहले मेरठ मंडल का सेक्टर प्रभारी बनाया गया. वे आगरा, फैजाबाद और देवीपाटन मंडल के सेक्टर प्रभारी भी हैं

↗ शकील मलिक, 40 वर्ष

आम आदमी पार्टी (आप) के प्रदेश सहप्रभारी की भूमिका निभाने वाले शकील मलिक को पार्टी की अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का पहला अध्यक्ष बनाया गया है. जुझारू तेवर के कारण पश्चिमी यूपी के मुसलमानों में लोकप्रिय शकील मलिक आप के स्टार प्रचारक हैं

↗ बासित अली, 41 वर्ष

मेरठ जिले के रहने वाले बासित अली को भाजपा ने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है. इन्हें उर्दू अकादमी का सदस्य बनाया गया था. बासित नेशनल मुस्लिम फोरम के राज्य संयोजक भी हैं

के लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के तत्कालीन उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक भड़काऊ बयान दिया था. इस बार इमरान ने कांग्रेस छोड़कर सपा में शामिल होने की घोषणा की, उनका पूर्व का बयान एक बार फिर सोशल मीडिया पर छा गया. नतीजतन, सपा ने इमरान मसूद पर दांव लगाने से हाथ पीछे खींच लिए. सूत्रों के मुताबिक, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में सरकार बनने पर इमरान मसूद को सम्मानजनक तरीके से 'एडजस्ट' करने का भरोसा दिया है. मेरठ और आसपास के जिलों में मुस्लिम राजनीति की धुरी रहे याकूब कुरैशी भी इस बार चुनावी मैदान से बाहर हैं. कुरैशी वर्ष 2006 में उस वक्त चर्चा में आए थे जब उन्होंने डेनमार्क के कार्टूनिस्ट का सिर कलम करने वाले को 51 करोड़ रुपए देने की घोषणा की थी. सांप्रदायिक रूप से बेहद संवेदनशील मुजफ्फरनगर जिले में 2013 के बाद हुए दंगे ने ध्रुवीकरण की नींव तैयार कर दी थी. पिछले तीन चुनाव में यह ध्रुवीकरण स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ा था. किसान आंदोलन से दोबारा स्थापित हुई जाट-मुस्लिम एकता को बरकरार रखने और ध्रुवीकरण रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) गठबंधन ने मुजफ्फरनगर में एक नया प्रयोग किया है. एक समय था जब एक ही मुस्लिम परिवार कैराना और मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करता था. इस परिवार में लताफत अली मुजफ्फरनगर से सांसद थे तो उनके बहनोई गय्यूर अली खान कैराना से सांसद थे. इस बार चुनाव में तस्वीर अलग नजर आ रही है. मुजफ्फरनगर के बड़े चेहरों को राजनैतिक पार्टियों ने घर बिठा दिया है. मुजफ्फरनगर निवासी पूर्व राज्यसभा सदस्य अनीर आलम खान के पुत्र पूर्व विधायक नवाजिश आलम बुढ़ाना या चरथावल सीट से गठबंधन उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते थे लेकिन उनकी हसरत अधूरी रह गई. पूर्व विधान परिषद सदस्य चौधरी मुश्ताक के पुत्र नदीम चौधरी और चरथावल से बसपा के टिकट पर विधायक रह चुके नूर सलीम राणा, पूर्व विधायक हाजी लियाकत अली भी मीरापुर विधानसभा सीट से सपा-रालोद गठबंधन से टिकट मांग रहे थे, इन्हें भी निराशा हाथ लगी.

'नवाब' बनाम रियाया

रामपुर में नवाब खानदान और आजम खान के बीच छत्तीस का आंकड़ा रहा है. आजम खान रामपुर से नौ बार विधायक रहे हैं. लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में पहली बार आजम परिवार का सीधा मुकाबला नवाब

हर चरण में महत्वपूर्ण हैं मुस्लिम मतदाता

● 20-29 प्रतिशत तक मुस्लिम आबादी वाली सीटें ● 30 प्रतिशत से अधिक मुस्लिम आबादी वाली सीटें

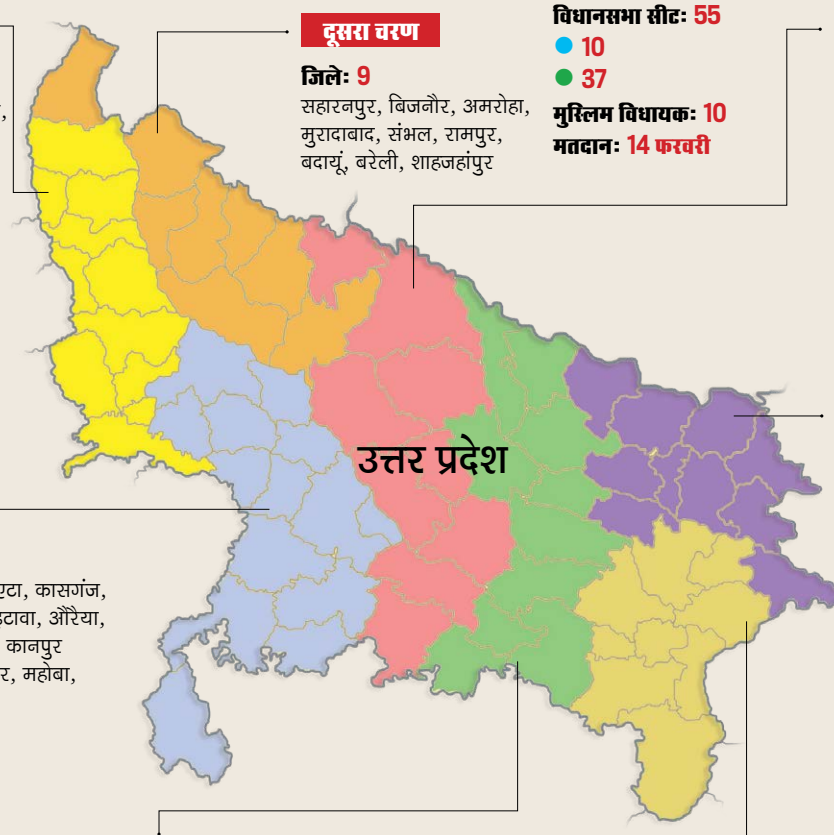

पहला चरण

जिले: 11
शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर, मथुरा, अलीगढ़, आगरा

विधानसभा सीटः 58
● 10 ● 17

मुस्लिम विधायकः 3

मतदानः 10 फरवरी

दूसरा चरण

जिले: 9
सहारनपुर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बदायूं, बरेली, शाहजहांपुर

विधानसभा सीटः 55
● 10
● 37

मुस्लिम विधायकः 10

मतदानः 14 फरवरी

चौथा चरण

जिले: 9
पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, हरदोई, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा

विधानसभा सीटः 60
● 19 ● 1

मुस्लिम विधायकः 0

मतदानः 23 फरवरी

छठा चरण

जिले: 10
बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, आंबेडकरनगर, संतकबीरनगर, गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया

विधानसभा सीटः 57
● 8 ● 7

मुस्लिम विधायकः 0

मतदानः 3 मार्च

तीसरा चरण

जिले: 16
हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा, औरैया, कन्नौज, कानपुरनगर, कानपुर देहात, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर

विधानसभा सीटः 59
● 5 ● 1

मुस्लिम विधायकः 0

मतदानः 20 फरवरी

पांचवां चरण

जिले: 11
बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा, बाराबंकी, अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, चित्रकूट, प्रयागराज

विधानसभा सीटः 60
● 14
● 6

मुस्लिम विधायकः 4

मतदानः 27 फरवरी

सातवां चरण

जिले: 9
आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, संत रविदास नगर

विधानसभा सीटः 54
● 4
● 2

मुस्लिम विधायकः 6

मतदानः 7 मार्च

नोटः जनसंख्या के आंकड़े जनगणना-2011 से लिए गए हैं.

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी में मुसलमानों की कुल आबादी 19.26% है

रामपुर (50.57%), मुरादाबाद (47.1%), बिजनौर (43.0%) मुस्लिम आबादी के लिहाज से तीन प्रमुख जिले हैं

प्रदेश के कुल 75 जिलों में से 29 ऐसे हैं जहां मुस्लिम आबादी यूपी में अपनी औसत आबादी से अधिक है

पहले दो चरणों के चुनाव की कुल 113 विधानसभा सीटों में से 54 में मुस्लिम आबादी 30 प्रतिशत से अधिक है

पहले दो चरणों के चुनाव की कुल सीटों में से करीब तीन दर्जन सीटों पर जाट-मुस्लिम मतदाता गठजोड़ कुल मतदाता के 40 प्रतिशत से अधिक है

पहले चरण की 58 विधानसभा सीटों पर बसपा ने 15, सपा-रालोद गठबंधन ने 10 और कांग्रेस ने 10 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं

दूसरे चरण की 55 विधानसभा सीटों पर बसपा ने 24, सपा-रालोद गठबधंन ने 19 और कांग्रेस ने 21 सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवार उतारे हैं.

ग्राफिकः चंद्रमोहन ज्योति

सब साथ-साथ हैं

शामली जिले की कैराना विधानसभा सीट पर जेल में बंद अपने भाई नाहीद हसन के समर्थन में सभा करतीं इकरा हसन

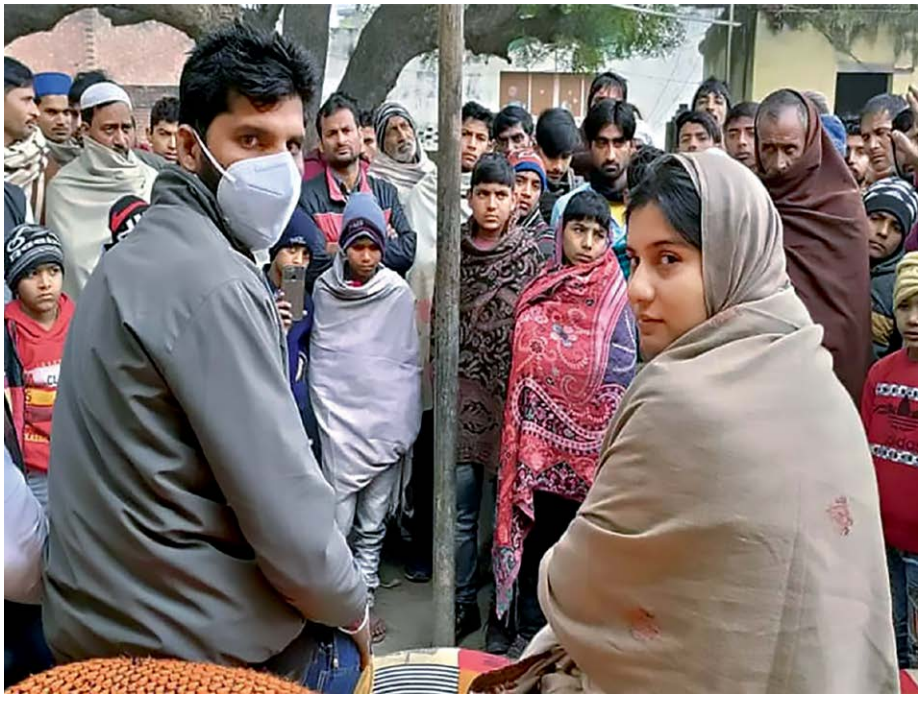

खानदान से है. रामपुर शहर सीट से कांग्रेस के टिकट पर नवाब खानदान के नावेद मियां सपा उम्मीदवार आजम खान के सामने चुनाव मैदान में हैं तो नावेद मियां के बेटे हैदर अली खां उर्फ हमजा मियां भाजपा के सहयोगी अपना दल (एस) उम्मीदवार के रूप में स्वार टांडा विधानसभा सीट पर अब्दुल्लाह को चुनौती दे रहे हैं. यह पहला मौका है कि जब भाजपा या उसके किसी सहयोगी दल ने विधानसभा चुनाव में किसी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट दिया हो. हमजा मियां ने 2019 में कांग्रेस की सदस्यता ली थी. बाद में उनकी विचारधारा बदल गई और अब वे अपना दल के उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में हैं. हमजा बताते हैं, ''आजम खान ने रामपुर की पहचान को नष्ट कर दिया है. रजा लाइब्रेरी से नवाब खानदान को बेदखल कर दिया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार के कोटे से मुझे रजा लाइब्रेरी का सदस्य नामित किया है.''

दरगाह आला हजरत की अलग राह

एक दौर था जब बरेलवी मुसलमानों के मरकज बरेली स्थित दरगाह आला हजरत के दरवाजे पर सियासतदां सिर झुकाने पहुंचा करते थे. संभवत: यह पहली बार है कि दरगाह से जुड़े दिग्गज खुद पार्टियों को समर्थन की पेशकश कर रहे हैं. नबीरे आला हजरत मौलाना अदनान रजा खां उर्फ अदनान मियां लखनऊ जाकर समाजवादी पार्टी को समर्थन दे चुके हैं. जमात रजा मुस्तफा दरगाह आला हजरत का प्रमुख संगठन है जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष असजद रजा खां भी नबीरे आला हजरत हैं. जमात में उपाध्यक्ष के पद पर असजद मियां के दामाद सलमान मियां काबिज हैं जिनकी एक गोपनीय मुलाकात 2021 के जुलाई महीने में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई थी. इस मुलाकात की फोटो वायरल होने के बाद जब दरगाह परिवार में विवाद बढ़ा तो सलमान मियां ने सफाई दी कि वे मुख्यमंत्री योगी से मुसलमानों के मसलों पर मुलाकात करने गए थे.

नबीरे आला हजरत और इत्तेहाद-ए-मिल्लत काउंसिल (आइएमसी) के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां भी विधानसभा चुनाव से सपा से तालमेल की कोशिश में थे. सपा से किसी प्रकार के समझौते पर दिलचस्पी न दिखाए जाने पर तौकीर ने अचानक कांग्रेस को बिना शर्त समर्थन देने की घोषणा कर दी. इस वक्त तौकीर पश्चिमी यूपी में कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं. अब उनके निशाने पर समाजवादी पार्टी है. तौकीर कहते हैं, ''अगर प्रदेश में दोबारा समाजवादी पार्टी आई तो फिर से दंगे शुरू हो जाएंगे.''

दरगाह आला हजरत परिवार से अलग-अलग राजनैतिक दलों को समर्थन देने के बीच में ही दरगाह प्रमुख मौलाना सुब्हान रजा खां उर्फ सुब्हानी मियां के दामाद सैयद आसिफ मियां ने बतौर एआइएमआइएम प्रत्याशी के तौर पर उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा सीट से नामांकन कर दिया है. बताया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से टिकट लेने से पहले आसिफ मियां ने कांग्रेस और सपा से टिकट लेने का प्रयास किया था लेकिन बात नहीं बनी. आसिफ के चुनाव लड़ने से पैदा हुए विवाद को थामने के लिए उनसे दरगाह के सारे पद छीन लिए गए हैं. साथ ही आसिफ को दरगाह के किसी पद पर इस्तेमाल न करने की सख्त हिदायत भी दी गई है.

यूपी में बदल रही मुस्लिम सियासत का असर बरेली में दरगाह आला हजरत की अंदरूनी राजनीति पर भी पड़ा है. आने वाले समय में दरगाह के भीतर सियासी प्रतिद्वंद्विता बढ़ेगी

दरगाह आला हजरत परिवार की बहू रहीं और बरेली में तीन तलाक पीड़ित महिलाओं के लिए काम कर रहीं निदा खान ने भाजपा का दामन थाम लिया है. निदा को मुस्लिम महिलाओं के बीच भाजपा की नीतियों का प्रचार करने की जिम्मेदारी मिली है. बरेली के वरिष्ठ वकील अजीजुल हलीम कहते हैं, ''यूपी में बदल रही मुस्लिम राजनीति का असर दरगाह आला हजरत की अंदरूनी सियासत पर भी पड़ रहा है. आने वाले दिनों में दरगाह आला हजरत से जुड़े परिवारों के बीच राजनैतिक प्रतिद्वंद्विता और बढ़ेगी.''

बहरहाल, 2022 के विधानसभा चुनाव में बड़े और विवादास्पद चेहरों से दूर मुस्लिम राजनीति की तपिश वैसी नहीं दिख रही जैसी पिछले चुनावों में दिखती आई है. सहारनपुर के देवबंद में मजलिस-इत्तेहाद-ए-मिल्लत नाम से सामाजिक संस्था चलाने वाले मुफ्ती तारिक काजमी बताते हैं, ''मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुसलमानों के प्रति तीखे बयानों ने भाजपा के विरोध में मुस्लिम ध्रुवीकरण को ही बढ़ावा दिया है. मुस्लिम मतदाता उस पार्टी के पक्ष में लामबंद होता दिख रहा है जो भाजपा को हराने की क्षमता रखता हो. इसने ही यूपी विधानसभा चुनाव में सपा-रालोद गठबंधन और भाजपा के बीच सीधे मुकाबले की नींव रखी है.'' ■

मनीष अग्निहोत्री

विधानसभा चुनाव 2022

उत्तर प्रदेश

वफादारी की जंग

शिनाख्त या आजीविका? इन दो ध्रुवों के बीच झूल रहे पश्चिमी उप्र के मतदाता गहरी दुविधा में हैं. हमारे दौर के सबसे ज्वलंत मुद्दों के केंद्र से एक ग्राउंड रिपोर्ट

प्रशांत श्रीवास्तव

यमुना के पूर्वी तट पर कैराना से देखें तो नदी के दूसरी तरफ पानीपत पड़ता है—सीमा पार करके एक घंटे में हरियाणा पहुंचा जा सकता है. गन्ने और आक्रोशित लोगों से भरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में नदी के किनारे का यह मैदानी इलाका हमारे दौर का ऐतिहासिक युद्धक्षेत्र साबित हो सकता है. यह विचारों—दिमाग—की जंग है और अभी भी करोड़ों लोगों के दिमाग में उमड़ रही होगी क्योंकि यह इलाका 10-14 फरवरी को पहले दो चरणों के चुनाव के लिए तैयार है. यह हमारे दौर के सबसे ज्वलंत मुद्दों का केंद्र रहा है. ये इलाका न केवल पिछले साल के किसान आंदोलन का केंद्र रहा बल्कि यह पिछले करीब एक दशक से अधिक समय से हिंदुत्व की प्रयोगशाला रहा है. इनके साथ-साथ दोआब क्षेत्र के जटिल सामुदायिक ताने-बाने के साथ यहां बहुत गहरी और प्रतिस्पर्धी वफादारियां बनती हैं. हर मतदाता इन मसलों को कैसे हल करता है, इससे उत्तर प्रदेश की 403 सीटों में से एक-चौथाई के नतीजे तय होंगे—जो दक्षिण में मंदिरों के शहर मथुरा से लेकर उत्तर में तराई के इलाके सहारनपुर तक फैला हुआ है.

इस इलाके की 50 सीटों पर जाट समुदाय हावी है और बाकी सीटों पर भी उनका असर है. जाट तबका इस जंग के केंद्र में है. हाल तक यह तबका भगवा रंग में रंगा था, लेकिन कृषि संकट ने इसे अपने धार्मिक पहचान से इतर जाकर रक्षात्मक रूप से एकजुट होते हुए देखा है. सत्तारूढ़ भाजपा स्वाभाविक रूप से इसे रोकना चाहती है. यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहां घर-घर जा रहे थे और उन्हें कैराना में 2014-16 के पलायन की याद दिला रहे थे और यहां तक कि मुगलों के पुराने पड़ चुके संदर्भों का भी हवाला दे रहे थे. यह एक ऐसी समृद्ध कड़ी है जिसे भाजपा ने अतीत में सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया है और यह फिर काम कर सकती है—कम से कम उनके

वोटों को नुक्सान न पहुंचाने वाले हिस्सों में बांट सकती है.

जाटों के आइकन और पूर्व प्रधानमंत्री चरण सिंह के पोते तथा राष्ट्रीय लोक दल (रालोद) के युवा नेता जयंत चौधरी के लिए भाजपा के दरवाजे खुले हैं, -शाह का यह बयान जाटों की नाराजगी को कम करने की कोशिश भर है. भाजपा के एक पदाधिकारी ने *इंडिया टुडे* से कहा, ''चौधरी साहब (अजित सिंह) के निधन के बाद जाटों में जयंत के प्रति सहानुभूति है. वे जयंत को अपने सियासी चेहरे के रूप में देखना चाहते हैं, इसलिए जयंत के बजाए हम समाजवादी गठबंधन पर निशाना साध रहे हैं. हमें अभी भी उम्मीद है कि आधा से अधिक जाट समुदाय भाजपा को वोट करेगा.''

जयंत पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है—वे भाजपा की मुख्य विपक्षी समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं. सपा-रालोद का मुख्य जोर अपने-अपने वोट आधार को एकजुट करते हुए जाट-मुस्लिम-यादव वोटबैंक के निर्माण पर है. उनके गठबंधन से सैद्धांतिक रूप से यही नतीजा निकल रहा है. ठीक इसी दौरान वे अपने खेमे में नुक्सान के प्रति भी सचेत हैं और आगे बढ़ते हुए नई संभावनाएं भी तलाश रहे हैं. यही वजह है कि पिछली शताब्दी का प्रभावी मेल, जो चुनावी पर्यवेक्षकों का मुख्य आधार था, नए क्रमपरिवर्तन के साथ फिर से चलन में आ गया है. पुराने 'अजगर' की जगह इस बार बात 'गजब' फॉर्मूले की है. इसे समझने के लिए उन पुराने दिनों में जाना होगा जब कांग्रेस ने अपने स्वर्णिम दौर में ब्राह्मणों, दलितों और मुसलमानों को एकजुट करके सत्ता पर एकाधिकार कर रखा था. उसे चुनौती देते हुए 1960 के दशक में चरण सिंह ने पश्चिमी यूपी में महत्वपूर्ण संख्या रखने वाली गैर-ब्राह्मण और गैर-दलित जातियों का गठबंधन तैयार किया था. उस अजगर फॉर्मूले—जिसका तात्पर्य अहीरों, जाटों, गुर्जरों और राजपूतों से है—ने उन्हें मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचाया और उससे भी आगे बढ़कर इसने भारत में गैर-कांग्रेस राजनीति के रास्ते खोले.

अजगर फॉर्मूला अब काम नहीं करेगा. अहीर यानी यादव सपा प्रमुख अखिलेश यादव का मजबूत खेमा है, लेकिन राजपूतों को पूरी तरह से भाजपा का वफादार माना जा रहा है. ऐसे में उन्होंने अपनी नई ताकत का फॉर्मूला बनाया है—'गजब' (जीएजेएबी). इसमें गुर्जर, अहीर, जाट और नए हिस्से के रूप में ब्राह्मण को शामिल किया गया है. सपा अनिवार्य रूप से राजपूत वोटों की अनुपस्थिति की भरपाई ब्राह्मणों से करना चाहती है. हालांकि मंडल मसीहा मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश के लिए यह कितना भी विपरीत लगे, लेकिन यूपी के संदर्भ में मुफीद नजर आ रहा है—जहां योगी आदित्यनाथ के 'ठाकुर राज' में दरकिनार कर दिए जाने की वजह से ब्राह्मणों को हमेशा नाराज बताया जाता है. इसलिए, ब्राह्मणों की उपेक्षा का विलाप कर रहे सपा नेताओं का मंजर अप्रत्याशित नहीं है. हालांकि 'गजब' फॉर्मूले को साध पाना अभी भी इतना आसान नहीं है. जाटों के गठबंधन वाले पैकेज में गुर्जर आसानी से फिट नहीं किए जा सकते. वहीं, जाट-मुस्लिम वैमनस्य की चिनगारी कितनी बची है, यह भी ध्यान देने वाली बात है.

शाह के यात्रा कार्यक्रम में मथुरा एक अहम हिस्सा था और यह भी उसी प्रयोग का एक हिस्सा है. यहां भाजपा कृष्ण जन्मभूमि मुद्दे को धीरे-धीरे उठा रही है और आपात परिस्थितियों के लिए इसे तैयार रखेगी. वैसे, एक स्थानीय संत राम दास ऐसी कवायद को खारिज करते हुए कहते हैं, ''मथुरा प्रेम और शांति का शहर है. यहां नफरत के लिए कोई जगह नहीं.''

सपा-रालोद गठबंधन की मुख्य चुनौती अपने कार्यकर्ताओं के बीच की नाराजगी को कम से कम करना है ताकि एक-दूसरे के उम्मीदवारों को सफलतापूर्वक वोट हस्तांतरित किए जा सकें. कई सीटों के आवंटन पर मतभेद उभर आए हैं—मिसाल के तौर पर जाट बहुल मांट विधानसभा सीट पर रालोद के योगेश नौहवार को सपा के हरियाणा से आयातित संजय लाठर के लिए रास्ता छोड़ना पड़ा. इससे जमीनी स्तर पर बेचैनी बढ़ी है. मेरठ में सिवालखास में जाटों ने हंगामा कर दिया जब सपा ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार को रालोद के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाने के लिए उतारा. इससे रालोद के वरिष्ठ नेता राज कुमार सांगवान की संभावनाएं खत्म हो गईं. एकजुटता के प्रति जयंत की दृढ़ता और जमीनी स्तर पर सभी 'समन्वय समितियों' के बावजूद एक पुराने रुझान के फिर से उभरने का खतरा है: मुस्लिम जाट उम्मीदवारों को समर्थन दें, लेकिन जाट खेमा बदले में उन्हें समर्थन देने को उत्सुक न रहे, खासकर उन सीटों पर जहां भाजपा ने भी जाट उम्मीदवार उतारे हैं. यही वफादारी की अंदरूनी कशमकश है. ■

मैदान में आमने-सामने

श्रीकांत शर्मा
उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री, मथुरा से लड़ रहे हैं

पंकज सिंह
केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे, नोएडा से लड़ रहे हैं

बेबी रानी मौर्य
भाजपा की दलित नेता के तौर पर प्रचारित, आगरा (ग्रामीण) से लड़ रही हैं.

आजम खान
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, फिलहाल जेल में हैं और रामपुर सदर सीट से चुनाव मैदान में हैं. उनके बेटे अब्दुल्लाह उसी जिले के स्वार सीट से लड़ रहे हैं

जयंत चौधरी
जाट आइकन, इस चुनाव में चौधरी का प्रदर्शन उनका सियासी भविष्य तय करेगा

पिछली बार का प्रदर्शन

पहला चरण: 58 सीटें

दूसरा चरण: 55 सीटें

● भाजपा ● सपा ● बसपा ● रालोद ● कांग्रेस

ग्राफिक: असित रॉय

विधानसभा चुनाव 2022

गोवा

मांडवी के तट पर मंडल राग

निजी और दलगत प्रतिद्वंद्विता के बीच, एक नया कारक—पिछड़ी जाति की राजनीति—गोवा का चुनावी माहौल बदल रहा

किरण डी. तारे

जनवरी के मध्य में उत्तरी गोवा के पुराने और भीतर की ओर बसे शहर सांखली में यह एक सुखद सुबह थी. दिन भर के चुनावी अभियान के लिए अपने घर से निकलने से पहले 49 वर्षीय आयुर्वेदिक डॉक्टर और मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उस खूबसूरत लैंडस्केप में खोए हुए दिखते हैं.

इस इलाके में राजनेताओं के बदन पर भारतीय नेताओं का ट्रेडमार्क खादी का लिबास नहीं दिखता, बल्कि भारत के 'आम आदमी' का लुक ही इस गोवा प्रजाति की अलग पहचान होता है. सावंत भी कोई अपवाद नहीं हैं—जब वे नंगे पांव अपने पोर्च में आते हैं तो सफेद कमीज, धूसर पतलून और सफेद एन-95 मास्क के बीच उनकी कलाई पर बंधी काले डायल की राडो घड़ी उनके समृद्ध होने का एकमात्र संकेत देती है. कतार में खड़ी भीड़ से मुख्यमंत्री को अलग करने वाली एक ही चीज है, प्लास्टिक की एक कुर्सी. आखिरी लिखित आवेदन जमा होने के बाद ही सावंत अंदर जाते हैं और काले कट शूज पहनकर वापस आते हैं और अपनी सफेद इनोवा क्रिस्टा में ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठकर प्रचार के लिए निकल जाते हैं.

भाजपा लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के लिए सावंत से उम्मीद लगाए हुए है. इन्फ्रास्ट्रक्चर और सामाजिक कल्याण—उन्हें लगता है कि उन्होंने दोनों मोर्चों पर अच्छा प्रदर्शन किया है. उन्हें यकीन है कि 14 फरवरी को गोवा की कुल 40 सीटों के लिए होने वाले मतदान में भाजपा के 22 से अधिक सीटें जीतने पर इसका असर दिखेगा. सावंत *इंडिया टुडे* से कहते हैं, ''सड़कों और पुलों के व्यापक नेटवर्क, सेवाओं की ऑनलाइन उपलब्धता... गोवा में ऐसा कभी पहले नहीं हुआ था.''

उनकी आशावादिता के बावजूद शायद गोवा के विवादास्पद कैसिनो में दांव लगाने वाला सबसे महत्वाकांक्षी जुआरी भी राज्य के आधे निर्वाचन क्षेत्रों पर किसी एक पार्टी का कब्जा होने की बात पर भरोसे के साथ सट्टा नहीं लगाएगा. गोवा का राजनैतिक नक्शा असल में द्विध्रुवीय हुआ करता था—छोटे दल कांग्रेस या भाजपा के इर्दगिर्द जुड़ते थे. पर अब नहीं. आम आदमी पार्टी (आप) और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) जैसी पार्टियों के मैदान में होने के कारण इस बार मुकाबला अधिक विखंडित, जटिल और अनुमान लगाने के लिहाज से मुश्किल भी है.

यह छीना-झपटी वाली सियासत का एक रोमांचक खेल था जिससे येन-केन-प्रकारेण भाजपा 13 विधायकों से 27 के अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई. सावंत ने पूर्ण बहुमत का अच्छा, उत्पादक ढंग के इस्तेमाल किया—कम से कम सियासी तौर पर. वे कहते हैं, ''हमने सभी जिला परिषद और नगर निगम के चुनाव भारी बहुमत से जीते क्योंकि लोगों ने हम पर भरोसा जताया.'' बहरहाल, इस बात से भी वे तीन ज्वलंत मुद्दों पर जनता के गुस्से से बच नहीं पा रहे—और तीनों ही पर्यावरण, रोजगार और मैक्रो-इकोनॉमिक्स के बीच उस कठिन संतुलन से जुड़े हैं. एक, लौह अयस्क खनन, जो अभी भी सर्वोच्च न्यायालय की

साथी फोटो: मंदार देवधर

तेवर अपने-अपने
आप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अमित पालेकर, सांखली में प्रचार करते गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत और पणजिम में निर्दलीय उम्मीदवार उत्पल पर्रीकर

ओर से प्रभावी रूप से प्रतिबंधित है; दूसरा, गोवा की कोयला ढोने वाली सुविधाओं को दोगुना करने का प्रस्ताव, तट से घाटों तक प्राकृतिक संरचनाओं को बदलना; और तीसरा, मेलौली में प्रस्तावित आइआइटी परिसर को लेकर पर्यावरणीय चिंताएं. राज्य के बेताब पर्यावरणवादी लौह अयस्क पर स्थगन को बेशक राहत के रूप में देखते हैं, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था पर असर पड़ना लाजिमी था—खनन गोवा का सबसे बड़ा उद्योग है. अनुमान है कि इस प्रतिबंध से 2018 के बाद से 6,000 करोड़ रुपए का सालाना आर्थिक नुक्सान हुआ है, जिससे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 2,50,000 लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है. इसलिए सावंत कोयला-ढुलाई की परियोजना पर दृढ़ रुख अपनाए रहे, जबकि कैंपस के लोकेशन पर उन्होंने कदम पीछे कर लिए. आर्थिक तर्कों को आखिरकार, लोगों की परीक्षा पास करनी होती है. खासकर तब जब और भी नेता मौजूद हों जो ऐसे मुद्दों पर बखेड़ा खड़ा कर सकते हों.

ऐसे नेताओं में एक हैं फर्श से अर्श पर पहुंचने वाले माइकल लोबो. वे कलंगुट सीट के कंडोलिम में हाथ जोड़कर घर-घर दौरा कर रहे हैं. अपने किशोर जीवन में लोबो एक रेस्तरां में बरतन धोते थे लेकिन अब वे दो रिजॉर्ट, दो रेस्तरां और एक दर्जन बंगलों के मालिक हैं. अपनी सियासी पैंतरेबाजी के कौशल के लिए मशहूर लोबो, 17 साल भाजपा में बिताने के बाद कांग्रेस में लौट आए हैं और उन्होंने कांग्रेस में नई जान फूंक दी है. वे कांग्रेस के बारे में कहते हैं कि यह पार्टी ''लोगों में जाति और धर्म के आधार पर भेद नहीं करती.''

लोबो के आने से कांग्रेस में जान आ गई है. उन्होंने दल-बदलुओं पर सख्ती शुरू कर दी है. इस तरह को फैसले की तारीफ हो रही है. यही नहीं, राज्य में तेज सत्ताविरोधी रुझान के मद्देनजर कांग्रेस नए चेहरों को मैदान में उतार कर बड़ा दांव खेल रही है.

लेकिन पार्टी का आत्मविश्वास गठबंधन बनाने के मामले में बाधक है: उसने गोवा फॉरवर्ड पार्टी (जीएफपी) के प्रमुख विजय सरदेसाई को थामने की कोशिश की और उनकी 12 सीटों की मांग के जवाब में उन्हें महज तीन सीटों की पेशकश की. लेकिन इस बात की झलक सबसे ज्यादा उस ठसक में दिखी कि इसने भाजपा के खिलाफ महागठबंधन तैयार करने के टीएमसी के प्रस्ताव को खारिज कर

दरकता आधार

अभी तक कांग्रेस और भाजपा गोवा की राजनीति में हावी रही हैं

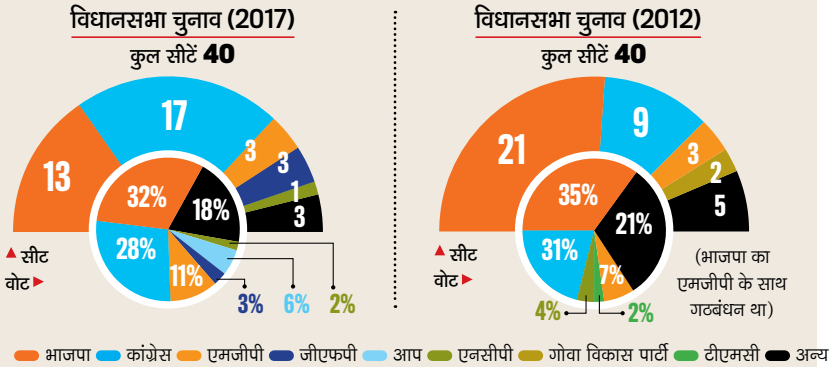

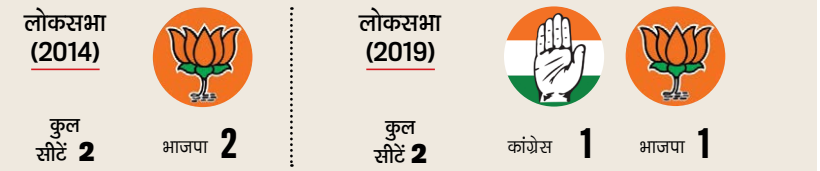

समुदायों का नक्शा

राजनैतिक प्रतिनिधित्व के मामले में भंडारी समुदाय की स्थिति सबसे खराब है

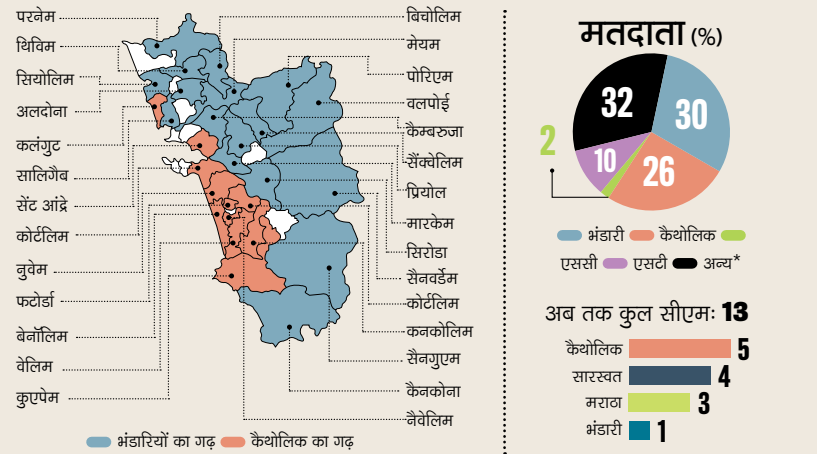

*'अन्य': 10 फीसद मुस्लिम (मुख्यतः बिचोलिम, वास्को और मडगांव में), 7 फीसद मराठा (मुख्यतः सांखली, मंदरेम में), 2 फीसद सारस्वत ब्राह्मण (मुख्यतः पणजी, मडगांव में), 13 फीसद अन्य गैर एससी-एसटी हैं. परनेम एससी के लिए आरक्षित सीट है, जिनकी वास्को में भी खासी संख्या है. कैनकोना और फटोर्डा में एसटी की अच्छी संख्या है.

ग्राफिक: असित राय

दिया. कांग्रेस के चुनाव प्रभारी पी. चिदंबरम और उनके टीएमसी समकक्ष महुआ मोइत्रा के बीच वाक्-युद्ध से दोनों पार्टियों को जख्म लगे हैं.

इसकी शुरुआत टीएमसी ने की. कांग्रेस के तत्कालीन राज्य प्रमुख लुइजिन्हो फलेरियो को ही फांसा, उसके बाद कांग्रेस और अन्य जगहों से पूरी भीड़ उमड़ पड़ी. लेकिन उसके बाद टीएमसी की चमक फीकी पड़ गई. सबसे पहले, जीएफपी ने कांग्रेस के साथ मामूली सौदेबाजी को ही प्राथमिकता दी और टीएमसी के साथ विलय के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया. उधर, टीएमसी ने महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी (एमजीपी) के साथ गठजोड़ कर लिया, जिसका हिंदुत्व के प्रति झुकाव सर्वज्ञात है. (टीएमसी 26 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एमजीपी 13 पर, और यह गठबंधन एक सीट पणजी पर चुनाव नहीं लड़ रहा). टीएमसी मीडिया प्रमुख ओमप्रकाश मिश्र कहते हैं, ''आप इसे विभिन्न विचारधाराओं का गठजोड़ कह सकते हैं लेकिन इससे भाजपा की पराजय की जमीन तैयार होगी.'' टीएमसी के थिंक-टैंक को यकीन है कि धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण वह कैथोलिक वोट बटोर लेगी, जबकि एमजीपी भाजपा के हिंदू वोटों पर चोट कर सकती है.

इस बीच, आप ने कुछ हलचल मचाने में कामयाबी हासिल की है. उसने सबसे पहले सीएम उम्मीदवार के नाम की घोषणा की. पार्टी की पसंद—लोकप्रिय अमित पालेकर—यहां की राजनीति के अभी तक परती रहे पहलू को छेड़ने वाले नेता हैं. आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ओबीसी भंडारी समुदाय को एकजुट करने की संभावनाएं तलाश रहे थे. वकील-आंदोलनकारी रहे पालेकर भंडारी चेहरा हैं जो आप के उस आख्यान में बिल्कुल फिट बैठते हैं कि पार्टी गोवा के सबसे बड़े समुदाय के लिए उचित मंच पर दावा कर रही है. यहां की सियासत में ब्राह्मण-मराठा-कैथोलिक का त्रिकोण अधिकतर समय तक हावी रहा है, ऐसे में भंडारी ज्यादातर नजरअंदाज किए जाते रहे. विडंबना है कि यह सुर केजरीवाल ने छेड़ा है जिनका वैचारिक जन्म आरक्षण विरोधी राजनीति के साथ हुआ था और वे अब गोवा का मंडलीकरण करने वाले हैं. भ्रष्ट नेताओं को दोष देते हुए पालेकर कहते हैं, ''हमारे प्रतिभावान युवा पलायन कर रहे हैं क्योंकि यहां उनके लिए कोई अवसर नहीं है. अगर हम सत्ता में आए, मैं 24 घंटों में व्यवस्था दुरुस्त कर दूंगा.''

भरपूर उत्साह
कलंगूट में चुनाव प्रचार करते कांग्रेस के प्रत्याशी माइकल लोबो

जाति के मोर्चे पर पहला पासा टीएमसी ने फेंका था. आप के पालेकर वाले दांव से भी पहले, उसने एक प्रमुख भंडारी नेता और जीएफपी से पार्टी में आने वाले किरण कंडोलकर को अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया था. कंडोलकर एल्डोना से और उनकी पत्नी कविता थिविम से चुनाव मैदान में हैं.

गोवा के 11 लाख वोटरों में भंडारियों की आबादी करीब 30 फीसद है और वे कम से कम 17 सीटों पर स्विंग कर सकते हैं. इस समुदाय की 19 उप-जातियां हैं जो राज्य की ओबीसी आबादी का 63 फीसद हैं. 1961 में पुर्तगालियों के कब्जे से राज्य की स्वतंत्रता के बाद बने 13 मुख्यमंत्रियों में (कुल मिलाकर 24 बार) से अभी तक महज एक भंडारी रहे हैं: रवि नाइक, जो नब्बे के दशक की शुरुआत में दो बार कुछ समय के लिए कुर्सी पर बैठे थे. वह भी तब, जब गोवा में सत्ता बड़े पैमाने पर कृषक समुदायों के वोटिंग के मिज़ाज पर निर्भर करती है. उत्तरी गोवा में उनके वोट अक्सर नतीजों पर सीधा असर डाल सकते हैं. अन्यथा, कैथोलिक समर्थन वाला भंडारी उम्मीदवार हर हाल में विजेता होगा.

आप ने भंडारी-कैथोलिक गठजोड़ की अहमियत को समझ लिया है. केजरीवाल ने ऐलान किया कि अगर पार्टी सत्ता में आती है तो पार्टी किसी कैथोलिक को डिप्टी सीएम बनाएगी. आप ने इस बार अधिकतर हिंदू उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखा है कि उनमें से अधिकतर ओबीसी जातियों से हों.

लेकिन क्या इससे भंडारी आप की ओर बढ़ेंगे? राजनैतिक टिप्पणीकार राजेंद्र देसाई संशय जताते हुए कहते हैं कि गोवा उत्तर प्रदेश की तरह जाति के आधार पर वोट नहीं करता. वे कहते हैं, ''सभी दलों के पास भंडारी नेता हैं. गोवा में उम्मीदवार की साख उसकी जाति से अधिक मायने रखती है.'' लेकिन साथ में मानते हैं कि आप के दांव ने भंडारी समुदाय को उसकी अहमियत का एहसास कराया है.

लेकिन खेल में निष्ठाओं की भी भूमिका है. उनमें से एक पणजी के सेंट इनेज इलाके में भीड़भाड़ वाले मुस्लिमवाड़ा में शाम ढलते ही दिखाई देता है. अपने बाएं हाथ में पावर बैंक से जुड़ा मोबाइल फोन, दाहिनी ओर बंधे पवित्र धागे, बुजुर्गों के पैर छूकर और युवाओं से हाथ मिलाते हुए उत्पल पर्रीकर अतीत और भविष्य का मिश्रण मालूम होते हैं. एक घर में, एक बुजुर्गों महिला उन्हें पुकारकर बुलाती है—वह अभी बस उनके पैर छूकर आए ही हैं. वे कहती हैं, ''आपने बताया नहीं कि आप पर्रीकर हैं. हमारा वोट आपको ही मिलेगा.''

उत्पल को भरोसा है कि जो लोग उनके पिता मनोहर पर्रीकर को पसंद करते थे, वे उनके पीछे खड़े होंगे. पणजी वह सीट है जिसे उनके पिता ने 1994 से तैयार किया है लेकिन राजनैतिक रूप से अधिक तजुर्बेकार एंटोनियो 'बाबुश' मोंसेरात्ते, जिनकी वजह से उत्पल की उपेक्षा की गई, का उनकी सीमाओं में आने वाले सभी 24 कॉर्पोरेशन वार्ड पर गहरा नियंत्रण है. सामुदायिक अंकगणित उत्पल की निर्दलीय उम्मीदवारी के लिए मुफीद नहीं है. पणजी में 23 फीसद लोग कैथोलिक और 20 फीसद लोग सारस्वत हैं. बगैर पार्टी की मदद के सारस्वत उत्पल के लिए कैथोलिक और ओबीसी वोटरों को अपने पाले में करना टेढ़ी खीर होगा. खासतौर पर, जाति के मोर्चे पर ओबीसी समुदाय में मजबूत बेचैनी के मद्देनजर यह काम और भी कठिन लगता है. 'आनि एक बामन आमका नाका' (हम एक और ब्राह्मण नहीं चाहते) का नारा जोर पकड़ रहा है. धारा के नीचे होने वाले एक और सामाजिक बदलाव के संकेत दिख रहे हैं जिसने लंबे समय से जड़ रहे सियासी मैदान में हलचल पैदा कर दी है. ■

अपने ही घर में खैर नहीं

कांग्रेस के भीतर ही प्रतिद्वंद्वियों से घिरे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भाजपा के गढ़ में कठिन चुनाव लड़ने को मजबूर

अनिलेश एस. महाजन

अपने मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश के दौरान 30 जनवरी को कांग्रेस नेता हरीश रावत बिंदुखत्ता गांव के कबड्डी मैदान में उतर पड़े. इस 73 वर्षीय वरिष्ठ नेता ने कुछ मिनटों के दोस्ताना मैच में हाथ आजमाया और एक-दो अंक भी हासिल किए. हालांकि उनका असल खेल इतना आसान नहीं है. बिंदुखत्ता उत्तराखंड के नैनीताल जिले के तराई क्षेत्र में स्थित है और लालकुआं विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है. और यह उनकी पसंद का चुनावी मैदान नहीं है. रावत को अपेक्षाकृत आसान सीट रामनगर से चुनाव लड़ना था, लेकिन वहां से वे बाहर कर दिए गए... क्या हम इसे पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र कहें? अब पूर्व मुख्यमंत्री रावत को सीधे दुश्मन के गढ़ में उतार दिया गया है और वे भाजपा के मोहन सिंह बिष्ट के खिलाफ खड़े हैं. कबड्डी के मैदान में किए थोड़े खतरनाक प्रयोग की तरह—14 फरवरी को मतदान के दिन उन्हें प्रेम मिलना मुश्किल हो सकता है.

कांग्रेस खेमे के भीतर भी आपसी प्रेम दिखना दुर्लभ चीज हो गया है. अगर उत्तराखंड की चुनावी राजनीति मोटे तौर पर दो-ध्रुवीय है, तो यह पुरानी पार्टी अपने आप में दो-ध्रुवीय संगठन बन गई है. राज्य के सबसे बड़े नेता होने के बावजूद हरीश रावत केवल एक धुरी बनाते हैं. दूसरी धुरी के नेता प्रीतम सिंह हैं जो उनसे करीब दस साल छोटे हैं. प्रीतम सिंह विपक्ष के नेता हैं और रावत के कट्टर विरोधी हैं. वे राहुल गांधी के करीबी माने जाते हैं और हाल के वर्षों में उनका ग्राफ लगातार बढ़ा है.

लेकिन उन्हें यह दिखाना अभी बाकी है कि वे अकेले दम पर पार्टी को चुनावी जीत तक ले जा सकते हैं. हाल ही में पंजाब का प्रभार छोड़ने के बाद रावत उत्तराखंड की राजनीति में वापस लौटे हैं. लेकिन उनके गृह राज्य में चीजें उनके हिसाब से नहीं चल रहीं. उम्मीदवारों के चयन में उन्हें खुली छूट नहीं मिली, तो वे नाराज हो गए, फिर भी उन्हें छोटी-सी छूट हासिल हुई—उन्हें पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बल्कि केवल चुनावी अभियान का प्रमुख बनाया गया.

उनकी अपनी सीट के लिए जिद नहीं कर पाना दिखाता है कि रावत के लिए समीकरण किस तरह बदल गए हैं. उन्हें रामनगर से हटना पड़ा क्योंकि प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रणजीत रावत ने वहां से दावा ठोक दिया था. रणजीत प्रीतम सिंह के खेमे के हैं. हालांकि रणजीत रावत को आखिरकार अल्मोड़ा जिले की साल्ट सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन तब तक हरीश रावत नरम पड़कर लालकुआं स्थानांतरित हो चुके थे. लेकिन उनकी परेशानी कम नहीं हुई है. लालकुआं में संध्या डालाकोटी की जगह हरीश रावत को टिकट दे दिया गया, लेकिन संध्या ने दावेदारी नहीं छोड़ी है और निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन दाखिल कर दिया है. माना जा रहा है कि उन्हें प्रीतम का समर्थन हासिल है. लालकुआं उन 29 सीटों में से एक है जहां बागी उम्मीदवार कांग्रेस की संभावनाओं को खत्म करने पर उतारू हैं. हरीश ने खुद को ''पार्टी का सच्चा सिपाही'' बताते हुए यह सब सहने का विकल्प चुना है. लेकिन उनके वफादारों का कहना है कि इससे मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा रखने वाले इस वरिष्ठ नेता की छवि को धक्का लगा है.

दिल्ली के कुछ कांग्रेसी नेताओं का मानना है कि भाजपा के लिए भारी सत्ता-विरोध रूझान से बच पाना काफी मुश्किल है. निवर्तमान 70-सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस के पास केवल 11 सीटें हैं, लेकिन उसने 34 फीसद वोट हिस्सेदारी हासिल की थी. भाजपा को 47 फीसद वोट हिस्सेदारी के साथ 57 सीटें मिली थीं. उसको पाटा जा सकता है, लेकिन कांग्रेस के लिए चिंता की बात यह है कि क्या वह 14 फीसद मुस्लिम वोटों को एकमुश्त अपने पाले में कर पाएगी. दरअसल, इस बार मुस्लिम वोटों के कई दावेदार मैदान में हैं. बसपा, सपा और असदुद्दीन ओवैसी की एआइएमआइएम ने 18 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है. इनमें से हरिद्वार (ग्रामीण) सीट भी शामिल है, जहां से हरीश रावत की बेटी अनुपमा चुनाव लड़ रही हैं. उधम सिंह नगर और नैनीताल तथा देहरादून के कुछ हिस्सों में थोड़ी-बहुत मौजूदगी के अलावा मुस्लिम आबादी मुख्य रूप से हरिद्वार जिले में बसी हुई है. हरिद्वार जिले में बसपा का भी थोड़ा-बहुत प्रभाव है. 2017 में बसपा ने कुल वोटों का 7 फीसद हासिल कर लिया था. उसे ज्यादातर वोट हरिद्वार में ही मिले थे, हालांकि उसे एक भी सीट नसीब नहीं हुई थी. भाजपा ने शासन में कोई भी उत्साहजनक उपलब्धि हासिल नहीं की है, इसे बताने के अलावा बिखरी हुई कांग्रेस के पास है ही क्या? ■

घर में कलह
देहरादून में पार्टी के नेताओं के साथ हरीश रावत

एएनआइ

सत्ता का द्वार!
अयोध्या की सभी पांचों सीटें जीतने वाली पार्टी की सरकार बनती रही है

पीटीआइ

उत्तर प्रदेश

अयोध्या जीतो, पूर्ण बहुमत पाओ !

उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के साथ रामनगरी अयोध्या (पूर्व में फैजाबाद जिला) को लेकर एक मिथक भी जुड़ा है. वह यह कि जब भाजपा ने अयोध्या की पांचों विधानसभा सीटें जीती हैं तब उसने यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार भी बनाई है. वर्ष 1991 के विधानसभा चुनाव में राम लहर के दौरान भाजपा ने अयोध्या की सभी विधानसभा सीटें जीती थीं और प्रदेश भर में कुल 221 विधानसभा सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी. 26 साल बाद दोबारा यह मौका आया, जब 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अयोध्या की सभी विधानसभा सीटें जीतने के साथ कुल 312 विधानसभा सीटें जीतकर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई. अगर यह मिथक कायम रहता है तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए अयोध्या की सभी सीटें जीतने की चुनौती है. 1991 के बाद जब 1993 में विधानसभा चुनाव हुए थे तब भाजपा ने फैजाबाद (वर्तमान में अयोध्या) जिले की सभी पांचों सीटों पर पुराने उम्मीदवारों पर ही दांव लगाया था. वैसे भाजपा का वह दांव बेकार साबित हुआ. वर्ष 1993 के विधानसभा चुनाव में भाजपा तीन सीटें ही जीत सकी और यूपी में सरकार बनाने से भी चूक गई. हालांकि वर्ष 2022 विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन में भाजपा ने कुछ मायनों में 1993 के प्रयोग को ही दोहराया है. 2017 के विधानसभा चुनाव में अयोध्या की सभी सीटों पर भाजपा का परचम लहराने वाले सभी उम्मीदवारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मैदान में उतार दिया गया है. मौजूदा विधायकों में से रुदौली से राम चंदर यादव, मिल्कीपुर से बाबा गोरखनाथ और अयोध्या से वेद प्रकाश गुप्ता को उतारा गया है तो गोसाइगंज के विधायक रहे इंद्र प्रताप तिवारी उर्फ खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी और बीकापुर से विधायक शोभा सिंह चौहान के बेटे अमित सिंह को उम्मीदवार बनाया है. अब देखना है कि भाजपा लगातार दो बार अयोध्या की सभी विधानसभा सीटें जीतने की चुनौती को पार कर पाती है या नहीं.

बतकही

"कैट (कांग्रेस, आप, टीएमसी) से सावधान रहिए. अगर ये आपके रास्ते को काट दें, तो बहुत अपशकुन होगा."

शिवराज सिंह चौहान,
मुख्यमंत्री, मध्य प्रदेश, गोवा में भाजपा का चुनाव प्रचार करते हुए

"चन्नी की सरकार मोहल्ला क्रिकेट टीम की तरह था. कोई कप्तान नहीं. सिद्धू के पास बल्ला था मगर वे रूठते रह गए. चन्नी ने किसी को भी गेंदबाजी नहीं करने दी. (सुनील) जाखड़ तीनों विकेट लेकर स्विट्जरलैंड चले गए."

भगवंत मान
अध्यक्ष, आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई

उत्तर प्रदेश

नया चुनाव, नया गठबंधन

अब तक जितनी बार सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने विधानसभा चुनाव लड़ा है, उतनी बार दूसरी पार्टियों से गठबंधन किया है. ओम प्रकाश राजभर 2012 के विधानसभा चुनाव में पहली बार जहूराबाद सीट से मैदान में उतरे. उस चुनाव में उन्होंने कौमी एकता दल के साथ गठबंधन किया लेकिन चुनाव जीतने में कामयाब नहीं हो सके. 2017 के विधानसभा चुनाव में राजभर दोबारा जहूराबाद विधानसभा सीट से चुनाव में उतरे लेकिन इस बार इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन किया. यह दांव सफल बैठा और ओम प्रकाश राजभर चुनाव जीतकर विधायक बने. 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले ही सुभासपा और भाजपा गठबंधन में दरार पड़ गई. लोकसभा चुनाव समाप्त होते ही राजभर को योगी मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया गया. इसके बाद राजभर ने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाकर अपनी सियासी हसरतें परवान चढ़ाने की कोशिश की लेकिन बाद में समाजवादी पार्टी (सपा) से गठबंधन कर बैठे. वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में राजभर एक बार फिर से अपनी परंपरागत सीट से चुनाव मैदान में हैं लेकिन इस बार उनकी पार्टी सुभासपा का सपा से गठबंधन है. देखना यह है कि सुभासपा और सपा गठबंधन से भी राजभर को वही नतीजा मिलता है कि नहीं, जो भाजपा से गठबंधन करके मिला था.

पार्टी: *भाजपा/मणिपुर*

अर्जुन किसी और जगह के थे

जनमत सर्वेक्षणों ने मणिपुर में गद्दीनशीन भाजपा की बढ़त दिखाई. मगर किस्मत ने जीत की उस राह को गड्ढों से भर दिया. इनमें से कुछ तो शायद निर्वाचन क्षेत्र जितने बड़े हैं. भगवा पार्टी पहले तो अपने सहयोगी दल एनपीपी से हाथ धो बैठी, जिसने अकेले चुनाव लड़ने का फैसला लिया. एनपीएफ के साथ भी सीटों का बंटवारा आसान नहीं रहा. कितना भी बेमेल लगे, पर उत्तर प्रदेश में भाजपा के सहयोगी अपना दल (एस) ने मणिपुर में भी उम्मीदवार उतारने का फैसला कर लिया! फिर टिकटों के बंटवारे में सामान्य से ज्यादा अफरातफरी मची. पहले तो टिकट चाहने वालों की बड़ी तादाद के चलते घोषणा में देर हुई. कांग्रेस और एनपीपी ने अपनी सूचियां पहले घोषित कर दीं. जब नामों का ऐलान हुआ भी, तो राज्य भर के पार्टी दफ्तरों पर दंगों जैसी स्थिति हो गई. इसमें सांस्कृतिक झटका जोड़ लें. आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 24 जनवरी को इम्फाल में एक किताब के लोकार्पण के दौरान कहा कि मणिपुर महाभारत काल से ही भारत के इतिहास में योगदान देता रहा है. सामाजिक संगठन इस बयान की भर्त्सना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे मणिपुर के इतिहास के बारे में उनकी अज्ञानता का पता चलता है—क्योंकि उत्तरपूर्व के इस राज्य का महाभारत में वर्णित साम्राज्य से कोई संबंध नहीं रहा है! मणिपुर भगवा के पक्ष में वोट भले दे दे, पर वह उसके नैरेटिव को हजम नहीं करने वाला.

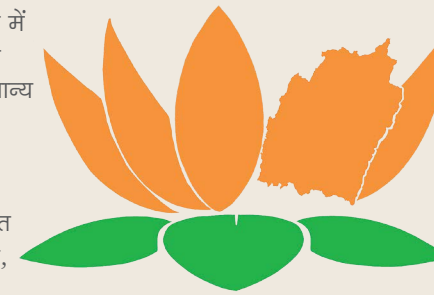

उम्मीदवार पर नजर: *एंथनी मेनेजिस*

होटल कलंगुट: सोरपोटेल की भीनी सुगंध

कलंगुट के होटल मालिक एंथनी मेनेजिस ने अपने सियासी करियर में कुछ अजीब उतार-चढ़ाव देखे हैं. दो दशक पहले उन्होंने अपने होटल में नौजवान माइकल लोबो को वेटर की नौकरी दी. चतुर लोबो धीरे-धीरे अपने मालिक से मीलों आगे निकल गए. 2005 में वे कांग्रेस के जिला पंचायत सदस्य बने. फिर दिवंगत मनोहर पर्रीकर के रूप में उन्हें गॉडफादर मिल गया और वे भाजपा के टिकट पर दो बार विधानसभा पहुंचे. मेनेजिस भी राजनीति में आ गए—लोबो के 'टुगेदर फॉर कलंगुट' बैनर तले उन्हें जिला पंचायत में जीत मिली. आज लोबो कांग्रेस के प्रमुख स्थानीय नेता हैं और उनकी नजर कलंगुट से लगातार तीसरी जीत पर है. ऐसे में 2020 में कांग्रेस में आए और इस सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे मेनेजिस हाथ मलते रह गए. पर फिर किस्मत पलटी—टीएमसी में खाली जगह निकल आई! अब पूर्व मालिक और कर्मचारी एक-दूजे के खिलाफ डटे हैं.

ट्वीट

Priyanka Gandhi Vadra @priy... · 1d
..@nsitharaman जी आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ डाला नहीं, ठीक है...लेकिन यू पी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या ज़रूरत थी?
समझ लीजिए, यूपी के लोगों को "यूपी टाइप" होने पर गर्व है। हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति व इतिहास पर गर्व है।
#यूपी_मेरा_अभिमान
1,451 5,589 18.2K
Priyanka Gandhi Vadra @priy... · 1d
न किसानों की आय दुगनी
न मध्यम वर्ग को टैक्स में छूट
न महंगाई से निजात
न छोटे उद्योगों को राहत
न युवाओं को रोजगार

उत्तर प्रदेश

ठाकुर? नहीं, माथुर

इस बार दो शातिर भाड़े के गुंडों को किराए पर लेने का दूर-दूर तक कोई संकेत नहीं है. इसलिए, *शोले* के ठाकुर का अपना काम खुद ही करना होगा... अरे, रुकिए, ठाकुर नहीं, इसे माथुर पढ़िए. चुनाव अभियान की भागमभाग में मथुरा से कांग्रेस उम्मीदवार और चार बार विधायक रहे 66 साल के **प्रदीप माथुर** एक हादसे के शिकार हो गए. उनके बाएं हाथ पर इसका असर पड़ा है—एक्स-रे की रिपोर्ट में मल्टीपल फैक्चर

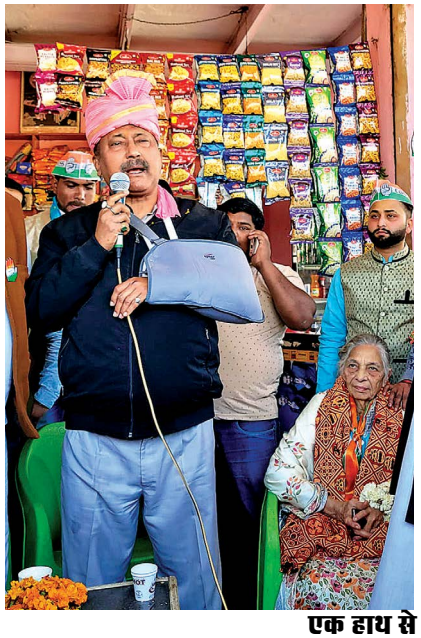

एक हाथ से
कांग्रेस उम्मीदवार प्रदीप माथुर

दिख रहा है. लेकिन माथुर पीछे हटने को तैयार नहीं हुए. इसके बजाए, उन्होंने अपना ऑपरेशन टाल दिया और चुनाव अभियान में लगे रहे और *शोले* के मशहूर डायलॉग को अपना लिया: 'एक हाथ ही काफी है भाजपा को हराने के लिए.' मथुरा में 10 फरवरी को वोटिंग होनी है, और यह उन सीटों में से एक है जहां कांग्रेस का भाजपा के साथ सीधा मुकाबला है. *शोले* के ठाकुर के उलट, मथुरा के माथुर सहानुभूति पर भी निर्भर हैं. उन्हें इसकी जरूरत भी होगी. अगले पन्ने पर 'शर्मा के ऊपर धर्मा' आइटम पढ़ेंगे तो आपको इसकी वजह का पता चल जाएगा.

इलस्ट्रेशन: सिद्धांत जुमडे

जहां सबकी नजर/*अमृतसर सीट*

सब कुलचा ही है

आरोपों की बौछार और जवाबी हमले. दुश्मन बनते दोस्त. पंजाब का अमृतसर पूर्व इस वक्त जलते तवे सरीखा है. एक कोने में नवजोत सिंह सिद्धू हैं जो अपनी महत्वाकांक्षा के आड़े आने वाली किसी भी चीज पर खुद को पेट्रोल बम की तरह फेंकते हैं, भले ही वह उनकी अपनी पार्टी का ही क्यों न हो! भला कौन उनसे मुचैटा लेना चाहेगा? अकाली दल में नंबर दो, विवादास्पद विक्रम सिंह मजीठिया के अलावा भला कौन. गिरफ्तारी पर आखिरी वक्त में सुप्रीम कोर्ट की रोक से लैस और पंजाब में मादक पदार्थों के सबसे बड़े सियासी सरपरस्त होने के आरोपों से घिरे मजीठिया ने पास के अपने पारिवारिक गढ़ मजीठा को तिलांजलि दे दी और सिद्धू की फेंकी चुनौती का तीर उठा लिया. उनके सिर पर बदले की आग जो सवार है.

मजीठिया ने ही एक दशक पहले इस शहरी निर्वाचन क्षेत्र को सिद्धू का गढ़ बनाने में मदद की थी. तब सिद्धू भाजपा में थे. उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू ने भी यह सीट मजीठिया की मदद से जीती थी. खुद मजीठिया ऐसे परिवार से हैं जिसकी माझा इलाके पर सदियों पुरानी छाप है. 2012 के चुनाव के बाद सिद्धू का मजीठिया और उनके बहनोई सुखबीर बादल से झगड़ा हो गया. बीते छह महीनों में दुश्मनी इतने चरम पर पहुंच गई कि सिद्धू ने अपने पूर्व साथी को दुरुस्त करना अपना निजी एजेंडा बना लिया. उन्हीं की शह पर मादक पदार्थों की तस्करी और रेत माफिया से कथित जुड़ावों को लेकर मजीठिया के खिलाफ एफआइआर दर्ज की गई.

इसने 2022 की बड़ी जंग का रंगमंच तैयार कर दिया, जिसके पंजाब के लिए कहीं ज्यादा बड़े नतीजे होंगे, खासकर माझा के लिए. माझा के चार जिलों में 25 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से 15 में अकाली दल का कांग्रेस से सीधा मुकाबला है. अकालियों को उम्मीद है कि यहां की तीखी लड़ाई दूसरी जगहों के कार्यकर्ताओं को भी जोश से भर देगी.

पार्टी फंड का सूचकांक

पैसे के मामले में बसपा सेकंड, कांग्रेस थर्ड

मनीष दीक्षित

कांग्रेस पार्टी लोकसभा में दूसरा सबसे बड़ा राजनैतिक दल है और राजस्थान, छत्तीसगढ़ और पंजाब जैसे राज्यों में इसकी सरकार है लेकिन संपत्ति के मामले में यह बहुजन समाज पार्टी (बसपा) से पीछे है जिसकी किसी प्रदेश में सरकार नहीं है लेकिन लोकसभा में 10 सांसद हैं. यह बात राजनैतिक दलों की तरफ से चुनाव आयोग के समक्ष घोषित वित्त वर्ष 2019-20 के आय-व्यय के ब्योरे का अध्ययन करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रिटक रिफॉर्म्स (एडीआर) ने जनवरी 2022 में जारी रिपोर्ट में कही. भाजपा नंबर एक पर और सपा, बसपा और कांग्रेस लगभग बराबरी पर हैं. संपत्ति के मामले में शीर्ष पांच पार्टियों में से चार उत्तर प्रदेश के चुनाव मैदान में प्रमुखता से उतरी हुई हैं. पार्टियों की देनदारी में बैंक कर्ज, ओवरड्राफ्ट आदि शामिल हैं. इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (आइसीएआइ) की बनाई गाइडलाइंस के मुताबिक पार्टियों को अकाउंट का ब्योरा देना होता है लेकिन पार्टियां इसमें बहुत सारे ब्योरे नहीं देतीं. एडीआर के हेड मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) अनिल वर्मा कहते हैं कि पार्टियों की आय और व्यय का मूल्यांकन शायद ही कभी किया जाता हो, लिहाजा इनकी प्रामाणिकता भी संदिग्ध रहती है. कंपनियों की तरह लेखा-परीक्षण के नियम पार्टियों के लिए बाध्यकारी नहीं हैं. आठ राष्ट्रीय पार्टियों में से सात के अकाउंट के ब्योरे आयोग के पास हैं. पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों की आय-व्यय का कोई अता-पता नहीं है जबकि इनकी संख्या अप्रैल 2018 में 2,044 थी और यह सितंबर 2021 में बढ़कर 2,796 हो गई. 2019 के चुनाव में कुल 673 दलों ने भाग लिया था. जाने-माने आरटीआइ एक्टिविस्ट सुभाष अग्रवाल कहते हैं कि ज्यादातर पंजीकृत दलों ने कभी किसी चुनाव में भाग नहीं लिया, ये सिर्फ काले धन को सफेद करने के लिए बनाए जाते हैं. दलों का चंदा आयकर मुक्त होता है और दानदाता को भी छूट मिलती है. अग्रवाल छूट हटाने और सारा चंदा ऑनलाइन लेने की मांग भी करते हैं.

2019-20 में राष्ट्रीय पार्टियों की संपत्ति

(करोड़ रु. में)

1. भाजपा
संपत्ति 4847.78
बैंक में जमा 3253
देनदारियां 590.18

2. बसपा
संपत्ति 698.33
बैंक में जमा 618.86
देनदारियां 0.318

3. कांग्रेस
संपत्ति 588.16
बैंक में जमा 240.90
देनदारियां 57.49

4. माकपा
संपत्ति 569.519
बैंक में जमा 199.56
देनदारियां 72.08

5. तृणमूल कांग्रेस
संपत्ति 247.78
बैंक में जमा 1.259
देनदारियां 0.993

6. भाकपा
संपत्ति 29.78
बैंक में जमा 15.63
देनदारियां 9.39

7. एनसीपी
संपत्ति 8.20
बैंक में जमा 1.86
देनदारियां 0.41

स्रोतः एडीआर, चुनाव आयोग, नोट-2013-14 में 6 राष्ट्रीय पार्टियां थीं, 2022 में इनकी संख्या 8 हो गई है. एनपीपी का ब्योरा उपलब्ध नहीं है. 2013-14 का समाजवादी पार्टी का भी ब्योरा नहीं है.

6988.57
करोड़ रु.
राष्ट्रीय पार्टियों की संपत्ति

2129.38
करोड़ रु.
क्षेत्रीय पार्टियों की संपत्ति

(वित्त वर्ष 2019-20)

इलस्ट्रेशनः असित रॉय

टॉप 10 क्षेत्रीय पार्टियां (2019-20)

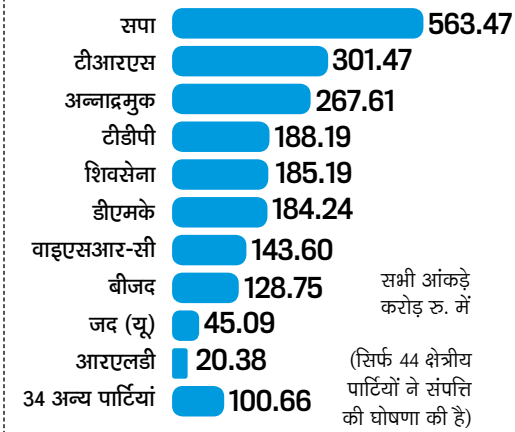

सभी आंकड़े करोड़ रु. में

(सिर्फ 44 क्षेत्रीय पार्टियों ने संपत्ति की घोषणा की है)

2013-14 में राष्ट्रीय दलों की आय

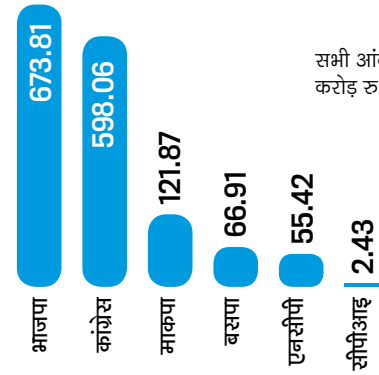

सभी आंकड़े करोड़ रु. में

उत्तराखंड

मां! मेरी नैया पार लगाओ

उत्तराखंड की हल्द्वानी विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी सुमित हृदयेश अपनी मां डॉ. इंदिरा हृदयेश के पक्ष में बनी सहानुभूति को भुनाने की हरसंभव कोशिश कर रहे हैं. डॉ. इंदिरा हृदयेश की नेता प्रतिपक्ष रहते हुए पिछले साल हुई मौत के बाद से यह सीट खाली थी. इस विधानसभा सीट पर कांग्रेस का टिकट लेकर मैदान में उतरे सुमित हृदयेश अपनी मां इंदिरा हृदयेश के चित्र को लेकर नामांकन करते दिखाई दिए. इसके जरिए सुमित अपनी मां के समर्थकों की सहानुभूति को अपने पक्ष में भुनाना चाह रहे थे. दिवंगत डॉ. इंदिरा हृदयेश को हल्द्वानी का 'विकास शिल्पी' कहा जाता है, यहां पर उनका बड़ा जनाधार है जिस पर अब उनके बेटे की नजर है.

सहानुभूति की आस सुमित हृदयेश अपनी दिवंगत मां इंदिरा हृदयेश की तस्वीर को साथ लेकर नामांकन करने पहुंचे

अखिलेश पांडे

उत्तर प्रदेश

नौकरी छोड़ो, चुनाव लड़ो

अभी तक अधिकारी रिटायरमेंट के बाद सियासत में कदम रखते थे. अब ऐसा पहली बार हो रहा है कि लंबी अवधि की नौकरी छोड़कर अधिकारी सीधे चुनावी राजनीति में कूद रहे हैं. यूपी में विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही कानपुर के पुलिस कमिश्नर असीम अरुण ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) के लिए आवेदन कर दिया. वीआरएस स्वीकृत होते ही अरुण भाजपा में शामिल हो गए. भाजपा ने भी दलित वोटों में सेंध लगाने की गरज से उन्हें कन्नौज सुरक्षित सीट से उम्मीदवार बना दिया. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) में संयुक्त निदेशक रहे पीपीएस अधिकारी राज राजेश्वर सिंह ने पिछले वर्ष अगस्त में ही वीआरएस के लिए आवेदन कर दिया था. पांच महीने बाद 1 फरवरी को उनका वीआरएस स्वीकृत हुआ और कुछ ही देर जब भाजपा ने लखनऊ जिले की विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की तो उसमें सरोजनी नगर सीट से राज राजेश्वर सिंह का नाम था. भाजपा सरकार में चर्चित रहीं राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) स्वाति सिंह का टिकट काटकर राजेश्वर सिंह को उतारा गया है.

एएनआइ

अब नेता लखनऊ में 16 जनवरी को स्वतंत्र देव सिंह और अनुराग ठाकुर की मौजूदगी में भाजपा में शामिल होते असीम अरुण

–आशीष मिश्र, किरण डी. तारे, कौशिक डेका, अनिलेश एस. महाजन, अखिलेश पांडे और प्रशांत श्रीवास्तव

उत्तर प्रदेश

शर्मा के ऊपर धर्मा

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री बी.सी. खंडूरी 'जरूरी' के साथ तुकबंदी से परेशान होने वाले अकेले शख्स नहीं हैं. अब भाजपा के मथुरा से उम्मीदवार श्रीकांत शर्मा के लिए एक नकारात्मक नारा पेश किया गया है. एक स्थानीय व्यापारी ने इसकी वजह बताते हुए कहा कि श्रीकांत शर्मा ने बतौर विधायक पिछले कार्यकाल में हर किसी को निराश किया है, लेकिन उन्हें योगी आदित्यनाथ की वजह से मजबूरन भाजपा को ही वोट करना पड़ेगा! वे कहते हैं, ''श्रीकांत मजबूरी हैं, क्योंकि योगी जरूरी हैं.'' भले ही इससे ज्यादातर लोगों की भावनाएं मेल न खाती हों, लेकिन कांग्रेस के एक हाथ वाले योद्धा प्रदीप माथुर ने इस पर निगाह टिका रखी होगी.

उत्तराखंड

चुनाव जीतने का दांव

उत्तराखंड के नैनीताल जिले की लालकुआं विधानसभा सीट से चुनावी समर में उतरे 73 साल के बुजुर्ग हरीश रावत चुनाव प्रचार के दौरान कबड्डी के अखाड़े में कूदते दिखाई दिए. चुनाव प्रचार के दौरान युवा खिलाड़ियों के साथ कबड्डी खेलने उतरे हरीश रावत का कबड्डी में दांव लगाते हुए वीडियो जमकर वायरल हुआ. रावत मतदाताओं से जुड़ाव दिखाने के लिए कभी पकौड़े की दुकान पर पकौड़े तलते हुए तो कभी जलेबियां छानते हुए दिखाई दे जाते हैं. चुनाव जो न कराए, कम है !

कबड्डी के अखाड़े में हरीश रावत

इंडिया टुडे RPG खुशी की खोज

कृतज्ञता: *खुशी की चाबी*

शांति और संतोष असली खुशी की बुनियाद हैं और आपके पास जो है, उसकी अहमियत समझने से ही ये हासिल हो सकती हैं

जया रो

इलस्ट्रेशन: सिद्धांत जुमडे

खुशी हमारे रवैये पर निर्भर करती है. हम क्या देख रहे हैं—वह जो हमारे पास है या वह, जो हमारे पास नहीं है? आपके पास अपार भौतिक संपदा हो, लेकिन अगर आप उन दो-एक चीजों पर ही ध्यान देते हैं जो आपके पास नहीं हैं, तो आप दुखी होंगे. भारतीय मिथक कथाओं में सुदामा के पास कुछ नहीं था, फिर भी वे ऐसे रहते थे जैसे उनके पास सब कुछ है.

जिंदगी की कुछ सबसे बेशकीमती चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं—ऑक्सीजन जिससे हम सांस लेते हैं, शानदार पारिवारिक रिश्ते या अच्छी सेहत. जिस क्षण आपको एहसास होता है कि आपके पास इतना कुछ है, आप उस अज्ञात शक्ति के प्रति कृतज्ञता से भर जाते हैं जिसने ये सब चीजें आप पर न्योछावर की हैं और फिर खुशी अपने आप चली आती है. हमें यह याद रखना चाहिए कि जिंदगी में हमें वही मिलता है, जिसके हम हकदार होते हैं, वह नहीं जो हम चाहते हैं. हकदार हम उसी के होते हैं जो अतीत में हमने अपने कर्मों से कमाया है.

कैसे खोजें खुशी...

● **आपके पास जो है उस पर ध्यान दें.** यह एहसास आपको कृतज्ञता की तरफ ले जाता है और आपके मन को शांति और संतोष की अवस्था में लाता है. जब आपका मन संतुष्ट और शांत होता है, आपकी बुद्धि तीक्ष्ण हो जाती है और आप साफ-साफ सोच पाते हैं. इससे आप अपना सर्वश्रेष्ठ बाहर ला पाते हैं और इस तरह जिंदगी में कहीं ज्यादा हासिल करते हैं. संतुष्ट होने का मतलब यह नहीं कि आप कोई आकांक्षा ही न करें.

● **दें.** देने का वास्तविक कृत्य ही नहीं, उससे पहले देने का विचार मात्र आपको खुशी से भर सकता है. आप भावनाएं, प्रेम, सरोकार, ज्ञान और अनुकंपा दे सकते हैं. जब आप देते हैं, तो हासिल करते हैं. जब आप झपटते हैं, तो गंवा देते हैं. यही हमने समझा नहीं. इसीलिए हम लेने वाले हैं, देने वाले नहीं.

● **खुद को नवाजी गई पांच चीजें लिखकर दिन शुरू करें.** ईश्वर में आपका भरोसा हो या न हो, उस शक्ति को जरूर महसूस करें जिसने आपको इतनी सारी चीजों से नवाजा है.

● **बच्चों को देने का आनंद सिखाएं.** वे बड़े होकर सफल, संतुष्ट और सानंद वयस्क बनेंगे! यह कहने के बजाए कि खूब अच्छा करो ताकि खूब धन कमा सको, बच्चों को सिखाएं कि लोगों की सेवा कैसे करें. इससे उन्हें सच्ची खुशी मिलेगी. ■

जया रो *आध्यात्मिक गुरु और वेदांता विजन की संस्थापिका हैं*
(अदिति पै से बातचीत पर आधारित)

मुझे किस चीज से *खुशी मिलती है*

हर्षवर्धन नेवतिया
चेयरमैन, अंबुजा नेवतिया ग्रुप

''खुशी मेरे लिए मनःस्थिति है. यह सांसारिक लाभ पर आधारित नहीं है. मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब होती है जब हमारे काम से दूसरे लोगों को आनंद मिलता है. महामारी के दौरान खुशी के विचार में काफी बदलाव आया है. आज हमारे विचारों की गुणवत्ता हमारी भौतिक संपत्ति से ज्यादा अहमियत रखती है क्योंकि खुशी का स्वामित्व हासिल नहीं किया जा सकता या उसे किसी बक्से में नहीं रखा जा सकता—जब हम जीवन के हर क्षण को आशा, शिष्टता, कृतज्ञता और विनम्रता के साथ महसूस करते हैं तो यह सांस लेकर खिलती है''

खुशी की तलाश: खुशियां बिखेरने की इंडिया टुडे ग्रुप और आरपीजी ग्रुप की साझा पहल है

ओशो की दीवानी

ऐक्ट्रेस **वामिका गब्बी** की साउथ की फिल्मों के हिंदी रीमेक, अपनी सीरीज *ग्रहण*, विशाल भारद्वाज, अपने ड्रीम डायरेक्टर और ओशो के प्रति दीवानगी के बारे में राय

● आप साउथ, पंजाबी और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही हैं. इन दिनों साउथ की फिल्में हिंदी पट्टी में भी खूब चल रही हैं. क्या आप इसे हिंदी इंडस्ट्री पर साउथ की फिल्मों के प्रेशर के रूप में देखती हैं?

यह पॉजिटिव प्रेशर है. मैं तो खुश हूं कि साउथ की फिल्में अब सब लोग देख पा रहे हैं. वे हमेशा से अच्छी फिल्में बनाते रहे हैं. लोग अब ओटीटी प्लेटफॉर्म की वजह से साउथ की फिल्मों के डब वर्जन देख पा रहे हैं. हिंदी में अब और अच्छी फिल्में बनेंगी.

● लेकिन इस समय जब साउथ की फिल्में खूब कमाई कर रही हैं तो आपने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिलचस्पी बढ़ा ली है.

ऐसा कुछ नहीं है. इस साल मैं हिंदी के अलावा साउथ और पंजाबी की फिल्में भी कर रही हूं. साउथ की फिल्में इसलिए करती हूं क्योंकि उनमें कुछ अलग कंटेंट होता है. ऐक्टर के लिए भाषा कोई दीवार नहीं होती. हिंदी में नेटफ्लिक्स के लिए साक्षी तंवर के साथ *माई* सीरीज है. दो प्रोजेक्ट विशाल भारद्वाज के निर्देशन में कर रही हूं. वे अमेरिकन एंथोलॉजी की सीरीज *मॉडर्न लव* के हिंदी वर्जन का एक एपिसोड कर रहे हैं. उसमें मैं भी हूं.

● आप रणबीर सिंह की बड़े कैनवस वाली फिल्म *'83* और वेब सीरीज *ग्रहण* का हिस्सा भी रही हैं. इनमें निभाए किरदारों से आपके करियर पर भला क्या फर्क पड़ा?

फिल्म *'83* में मैंने क्रिकेटर मदन लाल की पत्नी अनु लाल का किरदार किया था. पहला लॉकडाउन खुलने के बाद मैंने अपनी पहली वेब सीरीज *ग्रहण* शूट की थी. उसी ने तो मेरा करियर सेट कर दिया. उसी की वजह से आज मैं हिंदी सिनेमा में काम कर रही हूं.

● कोई ड्रीम डायरेक्टर जिसके साथ काम करने की दिली ख्वाहिश हो?

इम्तियाज अली के साथ काम करने की बड़ी तमन्ना है दिल में. मैंने जिंदगी में जिस पहली बड़ी फिल्म का सेट देखा वह इम्तियाज की ही *जब वी मेट* का था. इस फिल्म में मैं करीना कपूर की कजिन बनी थी. तब मैं आठवीं में पढ़ती थी. अब जब मैं मेनस्ट्रीम में हूं तो मुझे लगता है कि वह बड़ा खूबसूरत लम्हा होगा जब मैं दोबारा उनके साथ काम करूंगी.

● आप ओशो की दीवानी बताई जाती हैं.

जी. मैं ओशो को बहुत सुनती हूं. मेरे डैड (साहित्यिक पत्रकार गोवर्धन गब्बी) भी उनके फैन रहे हैं. विशाल के साथ काम करते हुए मैंने ओशो को भी थोड़ा एक्स्प्लोर किया है. उनकी पत्नी रेखा भारद्वाज भी ओशो को फॉलो करती हैं. ओशो दरअसल जिंदगी के बारे में, नेचर के बारे में बात करते हैं और वे बातें आपको गहरे तक छूती हैं.

—नवीन कुमार

आज तक

देश का नं. 1 हिंदी न्यूज़ ऐप

जुड़े रहिए हर खबर से,
कहीं भी, कभी भी

अभी डाउनलोड करें

aajtak.in/app

उपलब्ध है

IndiaContent

SEARCH FOR EDITORIAL IMAGES ENDS HERE